CENTRAL SQUARE FOUNDATION

भारत में स्कूली शिक्षा

डेटा, रुझान और नीतियां

संस्था के बारे में जानकारी

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

सेंट्रल स्क्वेयर फाउंडेशन (CSF) एक गैर लाभकारी संस्था है, जो यह सुनिश्चित करती है कि भारत में सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। 2012 से CSF - सरकार, निजी क्षेत्र, गैर लाभकारी संस्थाओं एवं अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी करके विशेष रूप से निम्न आय वर्ग से आने वाले बच्चों के शिक्षा प्रदर्शन को सुधार में जुटी है.CSF का ध्येय है स्कूली शिक्षा व्यवस्था को ऐसे समाधान अपनाने में मदद करना जो दीर्घकालीन और प्रभावी हों, ताकि सभी बच्चों को बेहतर जीवन जीने के लिए बराबरी का मौका मिल सके.

अधिक जानकारी के लिए विज़िट करें http://www.centralsquarefoundation.org/

स्पष्टीकरण: हमने पूरा प्रयास किया है कि 3 अगस्त 2020 तक के लिए इस केस स्टडी में दी गई जानकारी सही और पूर्ण हो। इस अध्ययन के किसी भी हिस्से को भारत सरकार, राज्य सरकारों या इनसे संबद्ध एजेंसियों और विभागों का आधिकारिक मत नहीं माना जाना चाहिए।

सेंट्रल स्क्वेयर फाउंडेशन द्वारा एक संदेश

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) से लेकर PISA 2022 में भारत के शामिल होने की योजना तक – हमारे देश के लिए शिक्षा क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण पल है। आज और कल के विद्यार्थियों के लिहाज से अगले कुछ कदम बहुत महत्वपूर्ण होंगे; ऐसे में ज़रूरी है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जिन उपकरणों या व्यवस्था का इस्तेमाल होगा, वह रिसर्च और साक्ष्यों पर आधारित हों।

नए प्रचलन, उपलब्ध साक्ष्यों और हाल के पॉलिसी विकास पर आधारित यह रिपोर्ट भारतीय शिक्षा व्यवस्था की पूरी तस्वीर दिखाती है। CSF की यह रिपोर्ट, शिक्षा व्यवस्था पर एक ऐसे स्त्रोत की कमी पूरा करती है जो संबंधित स्त्रोतों को जुटाकर उनकी समीक्षा करती है। यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं, समाजसेवियों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों के लिए संदर्भ का काम करेगी।

आशीष धवन
संस्थापक चेयरमैन
सेंट्रल स्क्वेयर फाउंडेशन

हम इस रिपोर्ट पर काम कर रहे थे, जब पूरे भारत में नोवेल कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन से स्कूल भी अछूते नहीं रहे। ऐसी स्थितियों में शिक्षा उपलब्ध करवाना और भी चिंता का विषय बन गया। अभिभावकों से लेकर सरकार तक सभी ने टेक्नलजी आधारित संसाधनों का सहारा लिया ताकि बच्चों की पढ़ाई जारी रह सके। यह संकट एडटेक यानि शिक्षा की टेक्नॉलजी के लिए वरदान साबित हुआ। यह रिपोर्ट, कुछ राज्य सरकारों द्वारा बड़े पैमाने शुरू किए गए एडटेक का भी गहराई से विश्लेषण करती है ताकि यह समझा जा सके कि किस तरह से उचित एडटेक सल्यूशन्स को लंबी अवधि में स्कूलों लागू किया जा सकता है।

रिपोर्ट में इस बात का भी ज़िक्र किया गया है कि किस तरह से निजी स्कूलों के आंकलन और प्रमाणन के लिए एक स्वतंत्र नियामक संस्था का गठन, जैसा कि NEP 2020 में ज़िक्र है, करना इन स्कूलों के लिए एक सक्षमता भरे वातावरण का निर्माण कर सकता है। आखिर हम अपने सपनों को तभी पूरा कर सकते हैं जबकि इन स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चों का लर्निंग आउटकम भी सुधरेगा।

आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं वे 2030 में कामकाजी वर्ग का हिस्सा बनेंगे। उस समय इस जनसंख्या विकास का फायदा लेना है तो सभी हितधारकों को अभी से मिलकर काम करना होगा ताकि बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

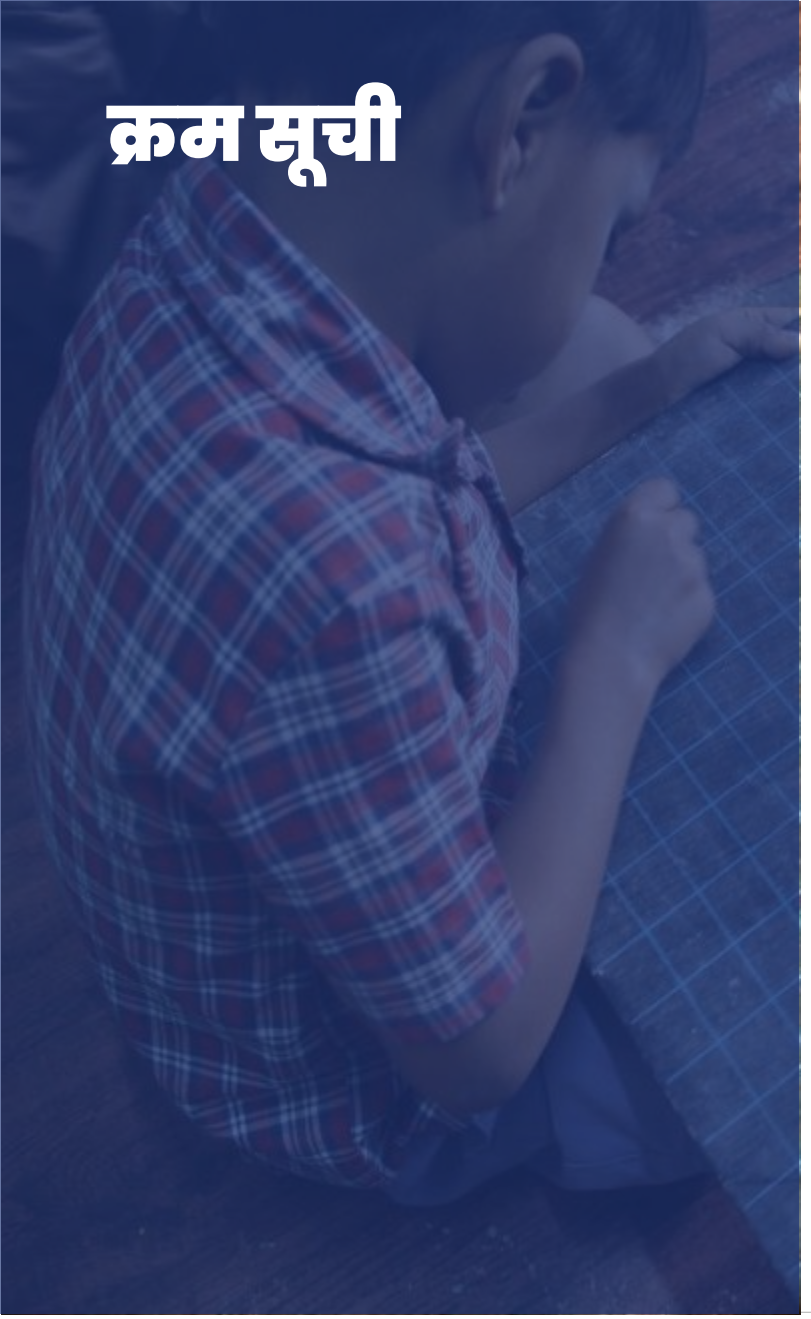

क्रम सूची

शैक्षणिक डेटा और रुझान

- परिचय
- गांव बनाम शहर
- निजी बनाम सरकारी
- शैक्षणिक परिणाम
- बजट

नीतिगत विशिष्टता एवं पहल

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) एवं अन्य विकास
- शिक्षा क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई पहल
- कोविड-19 के दौर में शिक्षा

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

दि स्टेट ऑफ एजुकेशन

शैक्षणिक डेटा और ट्रेंड्स

संक्षिप्त नामों की सूची

AEC: प्रौढ़ शिक्षा केंद्र
ASER: शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट
AWC: आंगनवाड़ी केंद्र
BEO: ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
BRC: ब्लॉक संसाधन केंद्र
CBSE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CRC: क्लस्टर संसाधन केंद्र
DCF: डेटा संग्रह फॉर्म
DIET: जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
DIKSHA: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग
ECCE: बचपन की देखभाल और शिक्षा
ETB: एनर्जाइज्ड टेक्स्टबुक
FLN: मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता
GDP: सकल घरेलू उत्पाद
GER: सकल नामांकन अनुपात
GSDP: सकल राज्य घरेलू उत्पाद
KRP: प्रमुख संसाधन व्यक्ति
MHRD: मानव संसाधन विकास मंत्रालय
MIS: प्रबंधन सूचना प्रणाली
MOE: शिक्षा मंत्रालय
NAS: राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण
NCERT: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
NCF: राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
NCTE: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
NEP: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020
NGO: गैर-सरकारी संगठन
NIEPA: राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
NISHTHA: स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल
OBC: अन्य पिछड़ा समुदाय
PGI: प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक
PISA: अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों के आंकलन का कार्यक्रम
pp: प्रतिशत बिंदु
PTR: छात्र शिक्षक अनुपात
RTE: नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार
SC: अनुसूचित जाति
SCERT: राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
SEQI: स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक
SEZ: विशेष शिक्षा क्षेत्र
SMC: स्कूल प्रबंधन समिति
SSA: सर्व शिक्षा अभियान
SSSA: राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण
ST: अनुसूचित जनजाति
UDISE: शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
URG: अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप

भाग अ : शैक्षिक आंकड़े और ट्रेन्ड्स

15 लाख से ज्यादा स्कूल, 92 लाख टीचर और दाखिल होने वाले 25 करोड़ छात्रों के साथ, भारत की शिक्षा व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी और जटिल शिक्षा व्यवस्था है। इस भाग में आंकड़ों पर आधारित इस व्यवस्था की अंदरूनी जानकारी है जो इन बिंदुओं पर नज़र डालती है:

- स्कूलों, विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या का ट्रेंड
- मैनेजमेंट और ग्रामीण-शहरी प्रकार का प्रतिशत और उनमें आए बदलाव
- पढ़ाई के नतीजे (लर्निंग आउटकम)
- बजटीय खर्च

» इस रिपोर्ट का मकसद है स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित आंकड़े तलाशने वालों के लिए एक संदर्भ उपलब्ध करवाना। इस डेटा विश्लेषण की संदर्भ अवधि 2013 से 2018 के बीच है। डेटा के स्त्रोतों की जानकारी अगली स्लाइड पर दी गई है।

डेटा के स्त्रोत और रिपोर्ट

- DISE[1] 2013-2018
- एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स ऐट अ ग्लांस 2005-06, 2015-16
- भारत का आर्थिक सर्वेक्षण
- NAS 2017
- ASER 2018
- 2013-14 से 2019-20 का केंद्रीय बजट

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

[1]DISE does not cover all of the 'unrecognised' private unaided schools, leading to an under-estimation in the true size of the private school sector

परिचय

15 लाख स्कूलों में दाखिल 25 करोड़ बच्चों के साथ भारत की शिक्षा व्यवस्था है विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था

- 2013 से 2018 के बीच यह आंकड़ा लगभग एक समान ही रहा है।

स्कूलों की संख्या

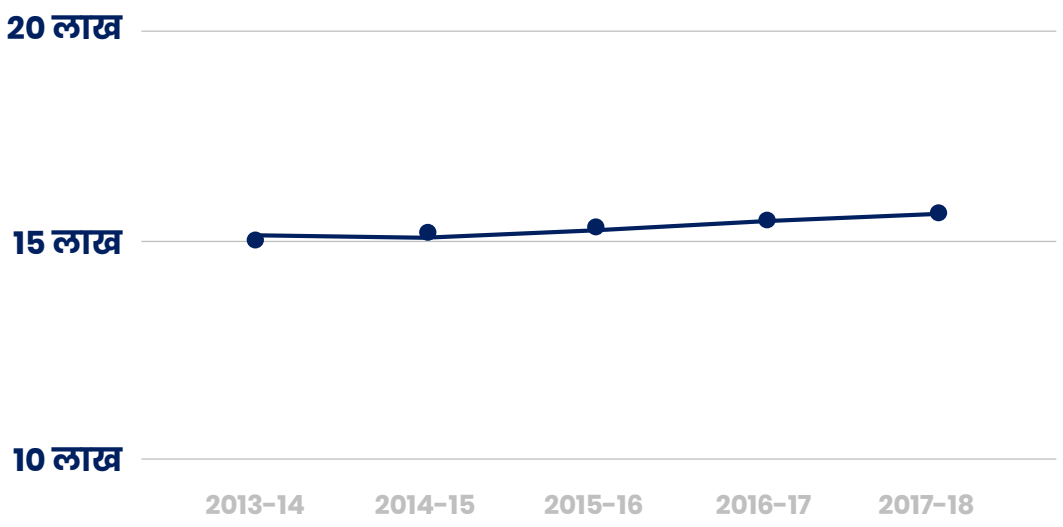

दाखिले

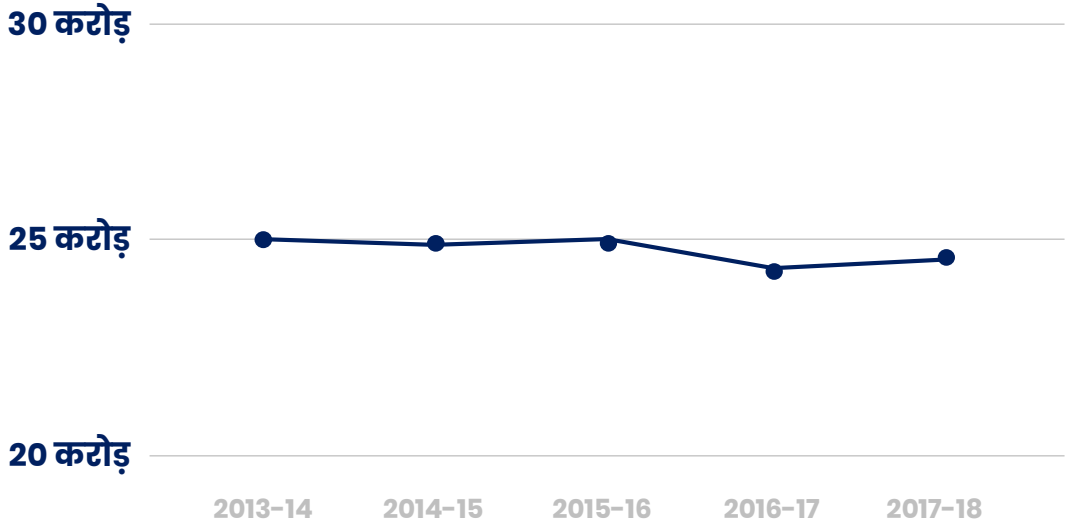

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source: DISE

भारत में स्कूल जाने वाले कुल बच्चों में से आधे बच्चे प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं।

शिक्षा के स्तर के अनुसार दाखिले (2017-18)

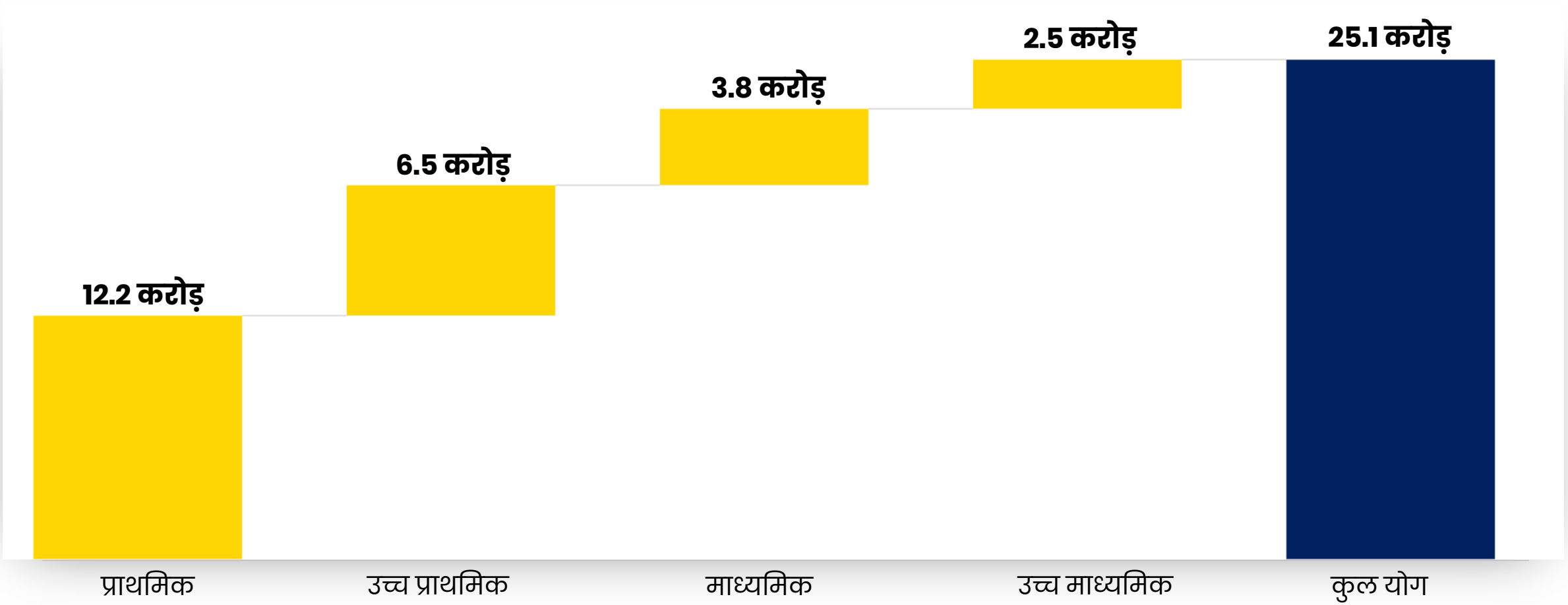

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source: DISE

2013-2018 के बीच प्राथमिक कक्षाओं में होने वाले दाखिलों में लगातार कमी आई

- यह अवलोकन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार किया गया है।
- सर्वेक्षण यह भी कहता है कि अगले दो दशकों में भारत की आबादी बेहद तेज़ी से घटेगी। देश भर में कुल जन्म दर (TFR) में आई तेज़ गिरावट के कारण 0-19 वर्ष का आयु वर्ग पहले ही चरम बिंदु पर पहुंच गया है।
- दक्षिण भारतीय राज्यों, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में जन्म दर पहले ही रिप्लेसमेंट रेट से नीचे जा चुकी है।

शिक्षा के अनुसार दाखिले का स्तर

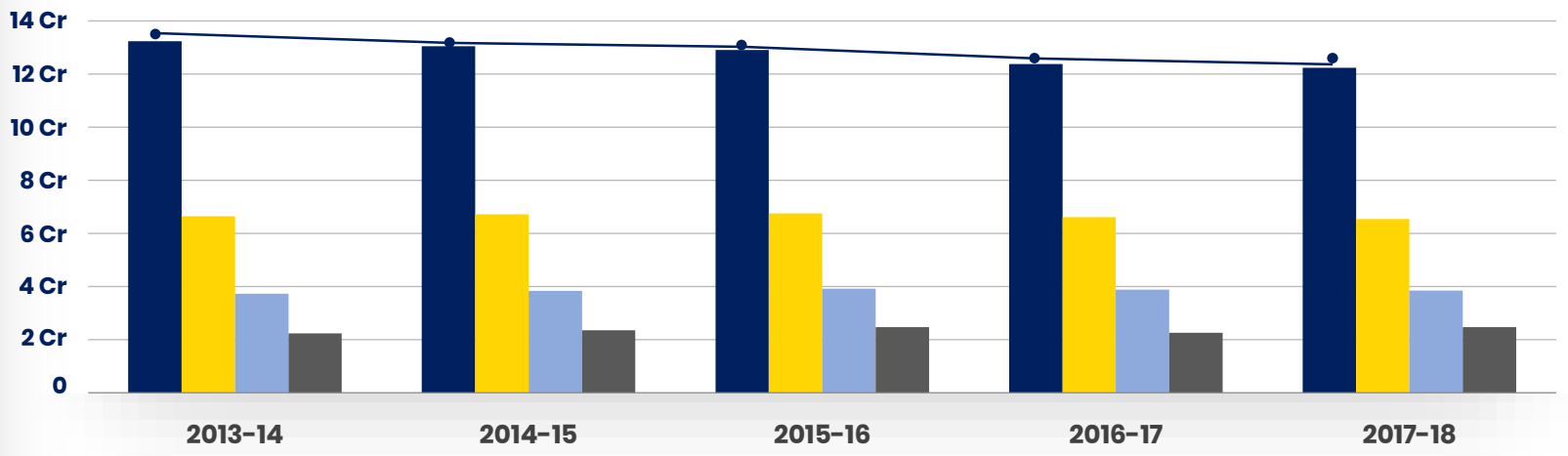

वार्षिक जनसंख्या विकास दर (भारत का %)

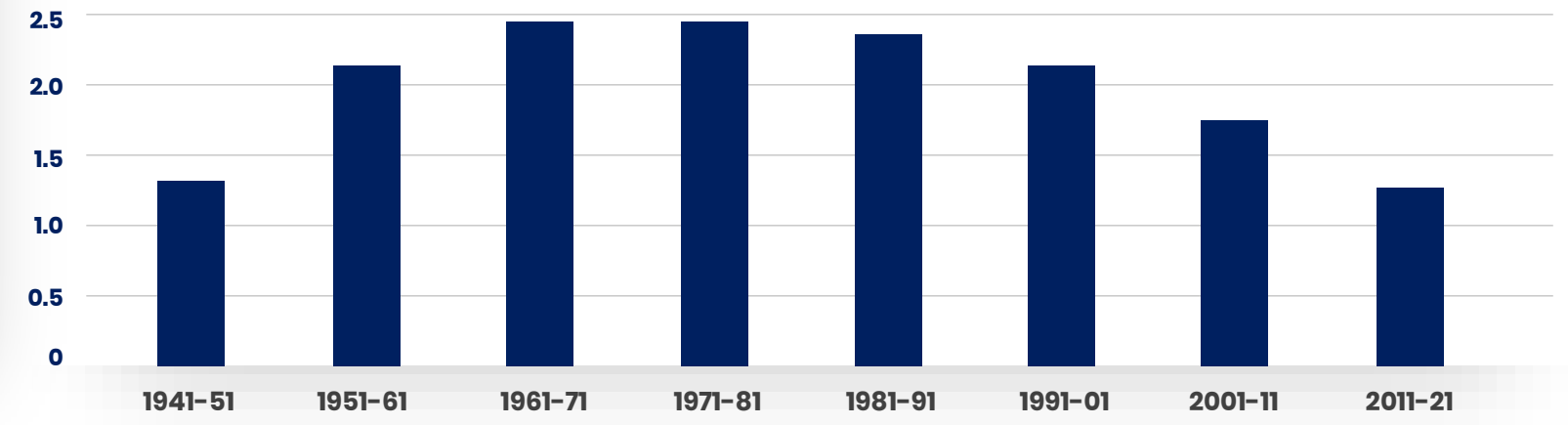

Source: DISE

बच्चे जैसे-जैसे ऊपरी कक्षा में जाते हैं वैसे-वैसे ड्रॉपआउट की संख्या बढ़ती जाती है

- हालांकि पहली से आठवीं कक्षा के स्तर पर हम वैश्विक भर्ती दर के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर चुके हैं लेकिन ऊपरी कक्षाओं के स्तर तक आते आते बच्चों की संख्या लगातार कम होती जाती है।

- लेकिन उच्च प्राथमिक (92.8%), माध्यमिक (80%) और उच्च माध्यमिक (56.2 %) स्तर पर GER के स्तर मेंसाल 2008-2015 के बीच बढ़ोत्तरी हुई है।

शैक्षणिक स्तर के अनुसार भर्तियां

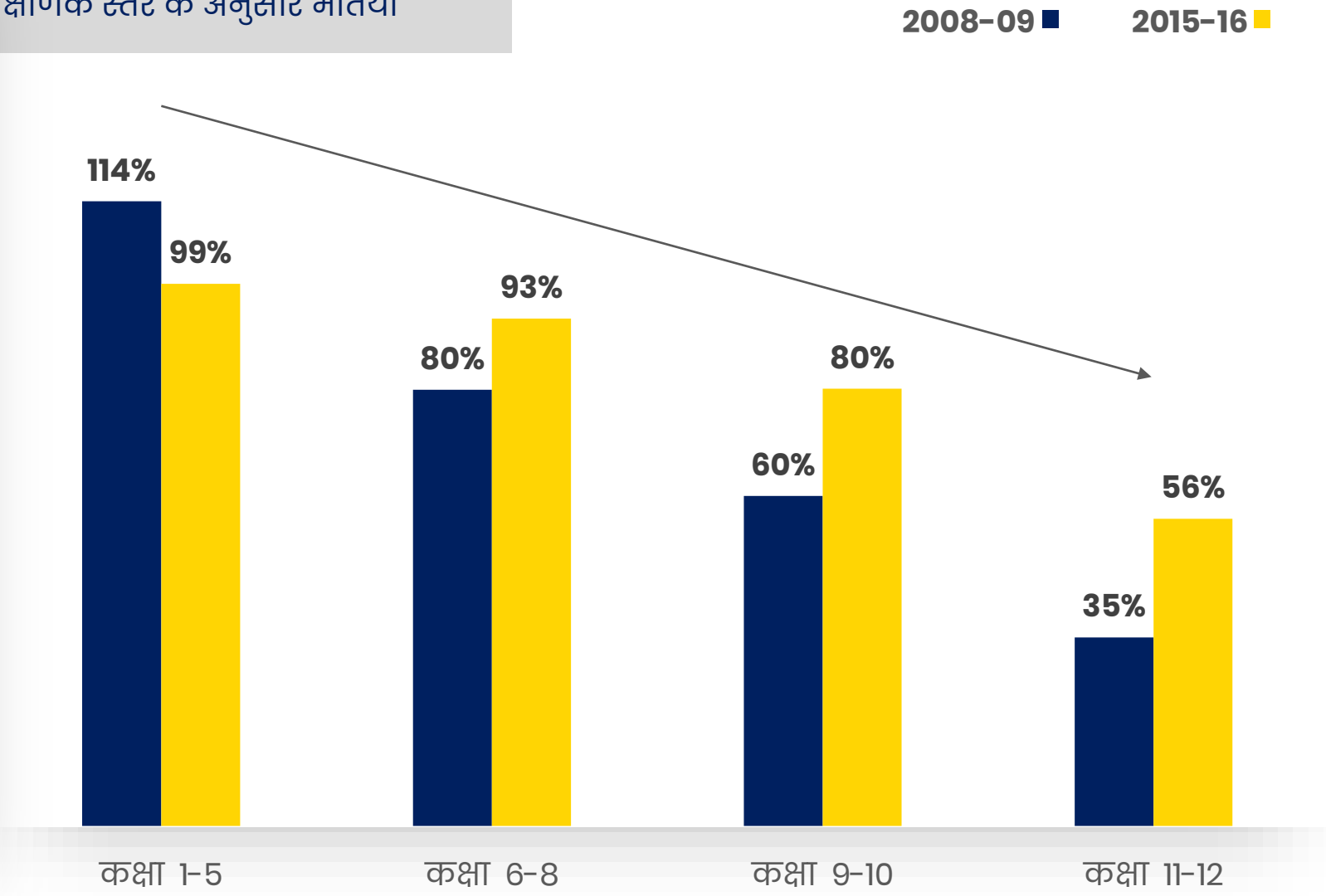

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source : Education statistics at a glance, MHRD, 2018
*Gross Enrolment Ratio (GER) is the number of students enrolled in a given level of education, regardless of age, expressed as a percentage of the official school-age population corresponding to the same level of education. GER can exceed 100% due to the inclusion of over-aged and under-aged students because of early or late school entrance and grade repetition

बिना किसी लैंगिक या जातीय भेदभाव के सभी को मिल रही है शिक्षा

- सभी शैक्षणिक स्तरों पर लड़कियों के सकल दाखिले की दर (GER) लड़कों के समान या उनसे ज्यादा है।

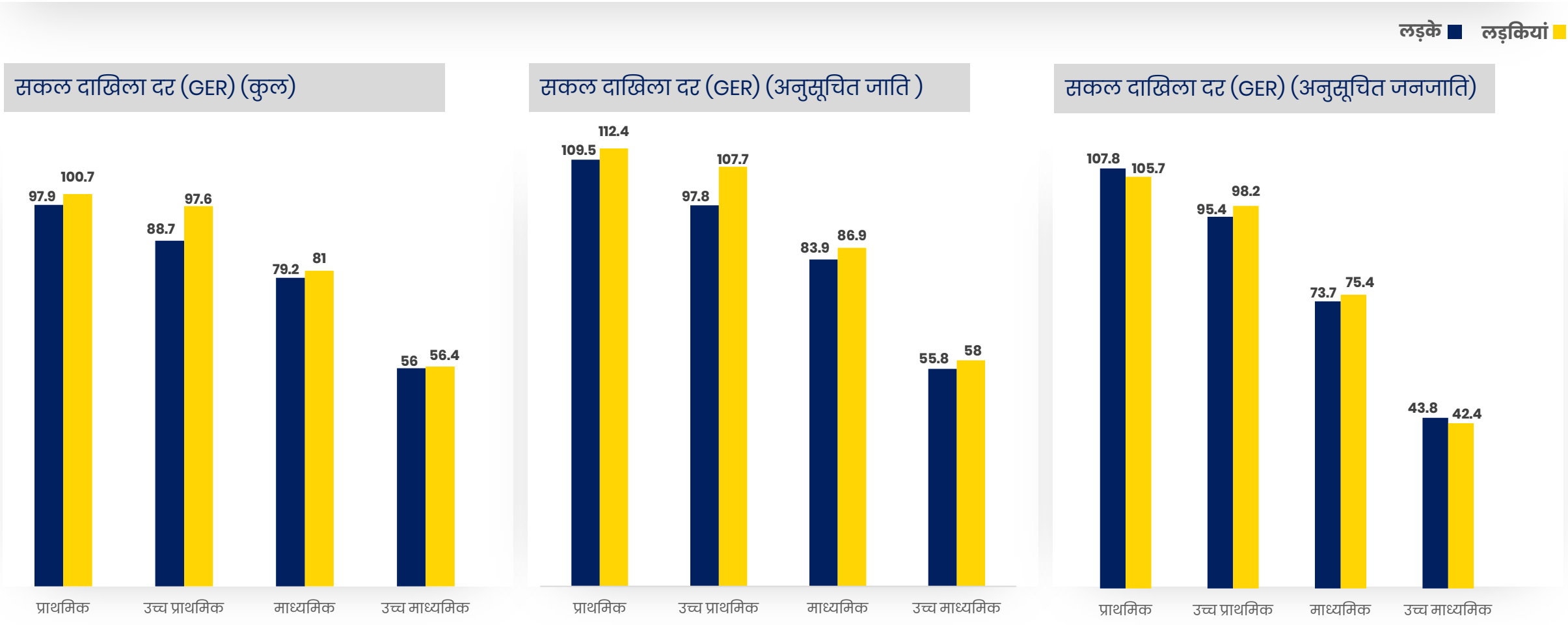

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source: Education Statistics at a Glance, MHRD, 2018

*DISE does not cover all of the 'unrecognised' private unaided schools, leading to an under-estimation in the true size of the private school sector.
Also, parents prefer sending boys to private schools (ASER 2019), hence it is likely that these calculations have underestimated number of boys enrolled in schools

सभी शैक्षणिक स्तरों पर लड़कियों के दाखिले में बढ़ोत्तरी

- प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में भर्ती दर (GER) में ज़बरदस्त सुधार

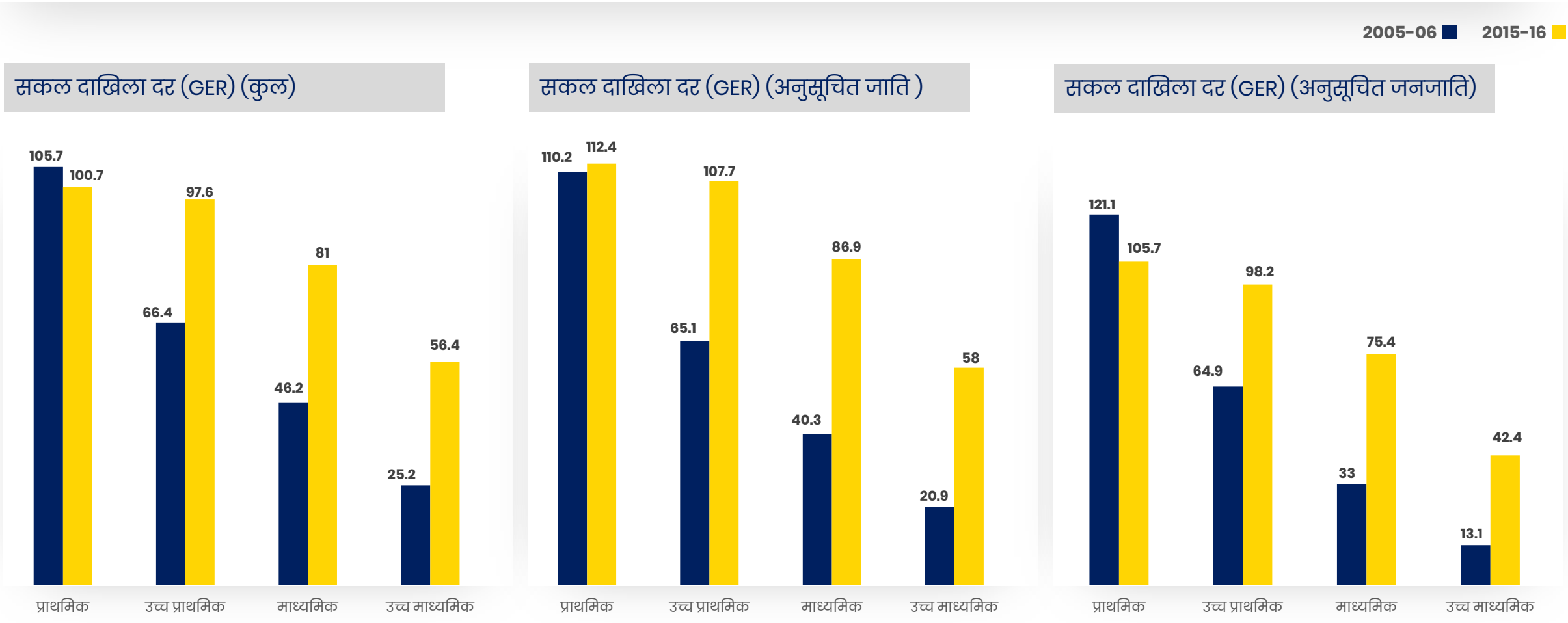

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source: Education Statistics at a Glance 2018; Education Statistics at a Glance 2005-06

2013 से 2018 के बीच विद्यार्थियों की संख्या स्थिर रहने के बावजूद टीचरों की संख्या में बढ़ोत्तरी

- इस अवधि में टीचरों की संख्या **82 लाख** से बढ़कर **92 लाख** हुई।

टीचरों की संख्या (5 वर्ष का ट्रेंड)

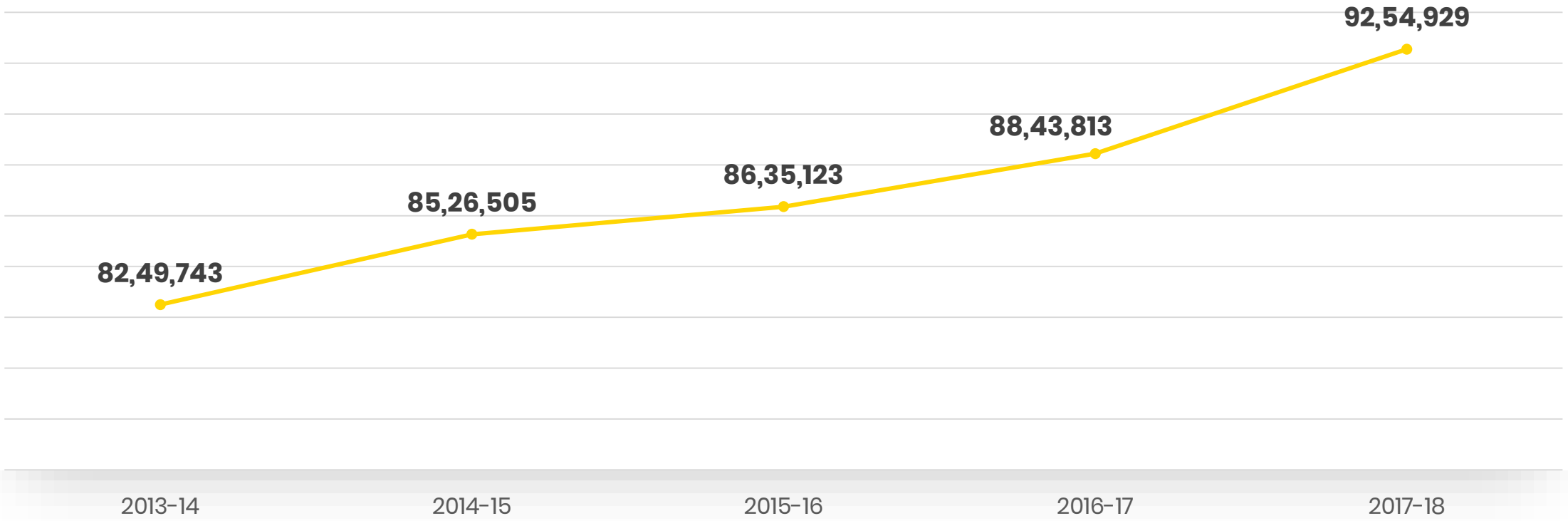

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source: DISE

विद्यार्थी-टीचर अनुपात (PTR) में कमी, प्रति टीचर 31 विद्यार्थियों से घटकर 27 तक पहुंचा

- शिक्षा के अधिकार कानून के अनुसार ज्यादातर राज्यों का PTR आदर्श PTR (30:1) से काफी कम या करीब ही रहा।
- बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और झारखंड तीन ऐसे राज्य हैं जहां बीते वर्षों में PTR में सबसे तेज़ी से कमी देखने को मिली। इन राज्यों में टीचरों की संख्या तो बढ़ी लेकिन इस अवधि में विद्यार्थियों की भर्ती में भी कमी आई।
- कर्नाटक इकलौता ऐसा राज्य है जहां इन पांच वर्षों की अवधि में PTR में 1.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।

विद्यार्थी- टीचर अनुपात (राष्ट्रीय स्तर)

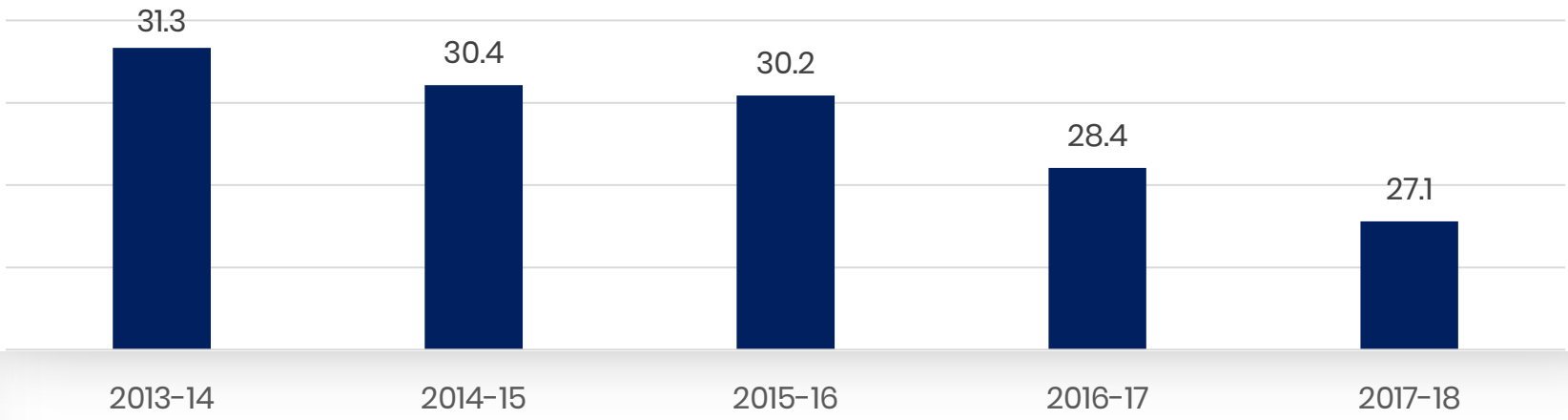

PTR में बदलाव (2017-18 बनाम 2013-14)

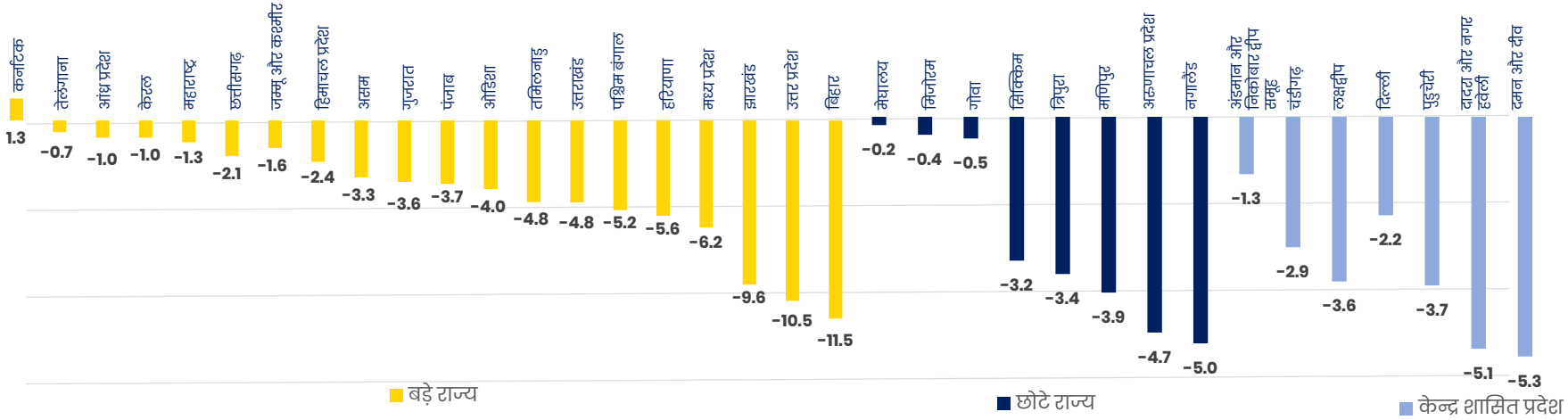

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source: DISE

टीचर विहीन या केवल 1 टीचर वाले स्कूलों की संख्या में लगातार गिरावट

- बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां टीचर विहीन या केवल 1 टीचर वाले स्कूलों का अनुपात सबसे ज्यादा है।
- अरुणाचल प्रदेश के 25% स्कूल ऐसे हैं जहां या तो केवल 1 टीचर है या कोई टीचर नहीं है।
- केवल चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी ऐसे राज्य हैं जहां कोई स्कूल ऐसा नहीं जहां टीचरों की संख्या 2 से कम हो।

टीचर विहीन या केवल 1 टीचर वाले स्कूलों का प्रतिशत

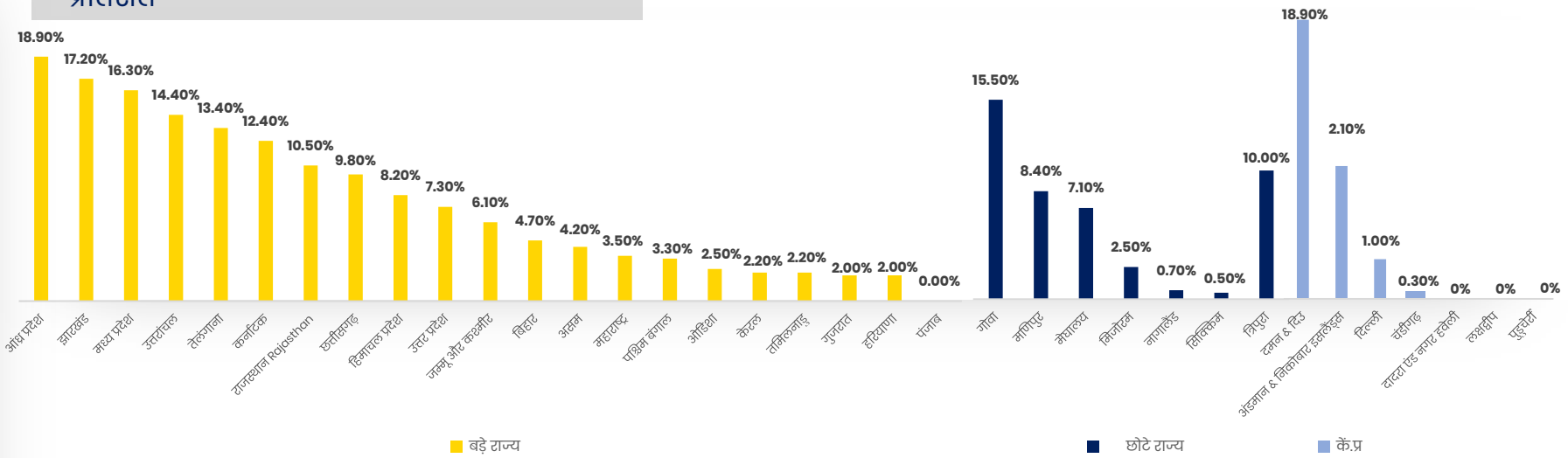

टीचर विहीन या केवल 1 टीचर वाले स्कूलों की संख्या

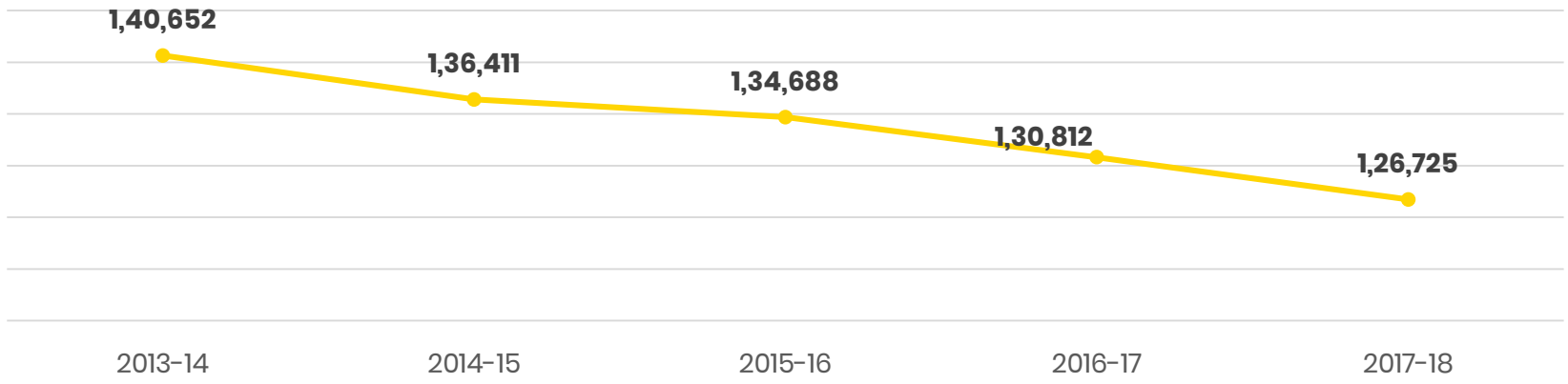

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source: DISE

ग्रामीण बनाम शहरी क्षेत्र

भारत के 15 लाख में से 85 % स्कूल ग्रामीण इलाकों में हैं।

- 2013 से 2018 के बीच ग्रामीण (85%) और शहरी (15%) स्कूलों के प्रतिशत अनुपात में कोई बदलाव नहीं आया।

स्कूलों की संख्या – ग्रामीण बनाम शहरी

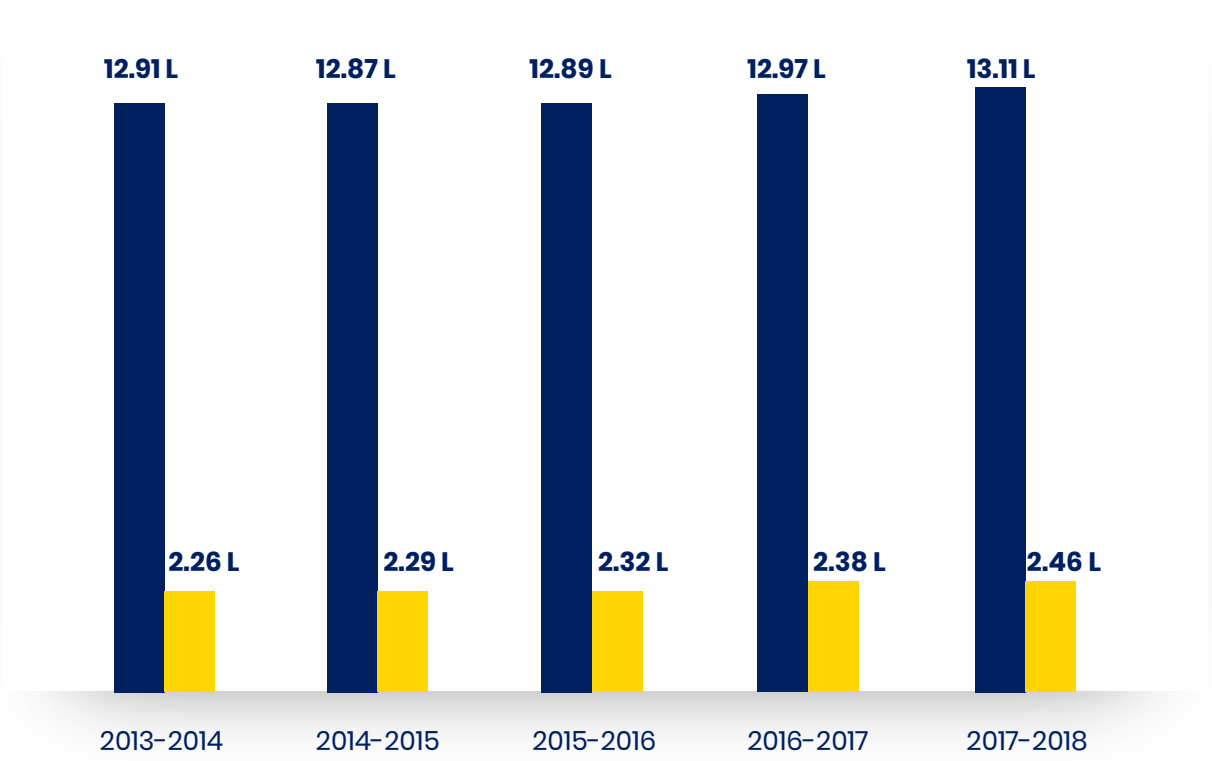

स्कूलों की संख्या – ग्रामीण बनाम शहरी

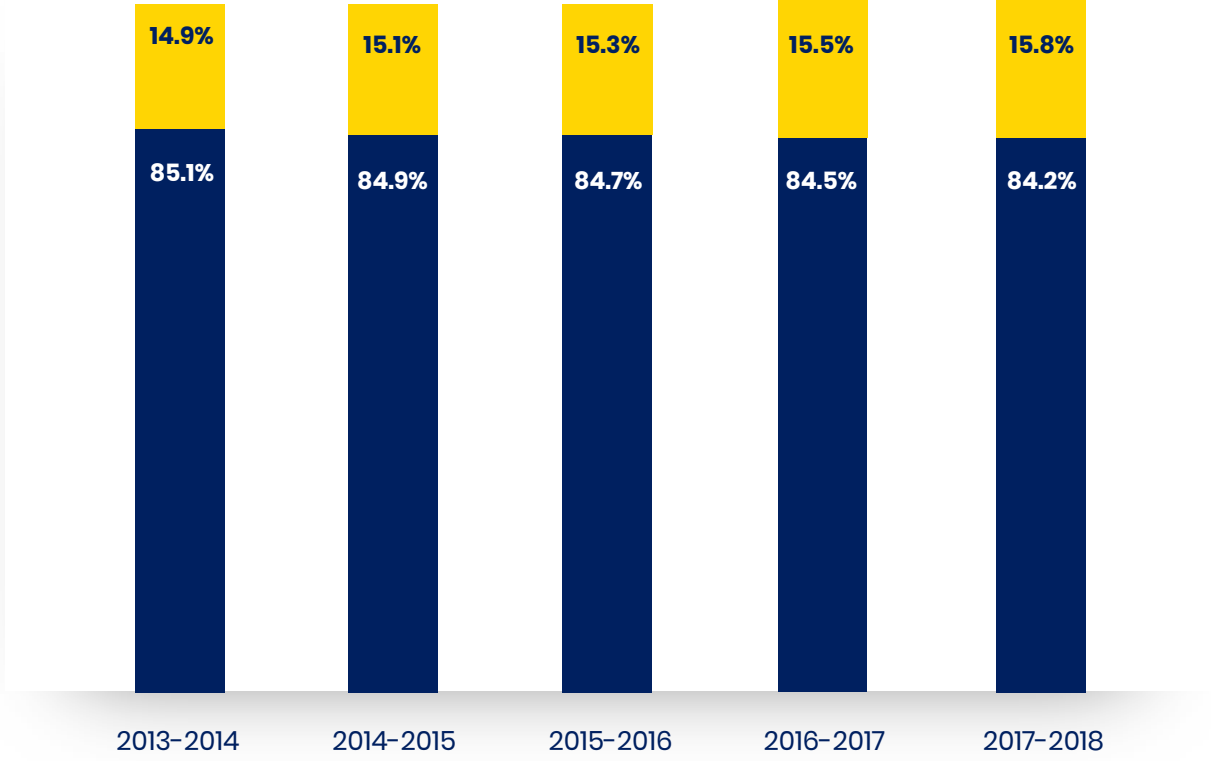

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source: DISE

ग्रामीण इलाकों में स्कूलों और दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक

ग्रामीण इलाकों में देश के 85 % स्कूल हैं जिनमें देश के 71% बच्चे दाखिला लेते हैं।

स्कूलों की संख्या – स्थानानुसार (2017-18)

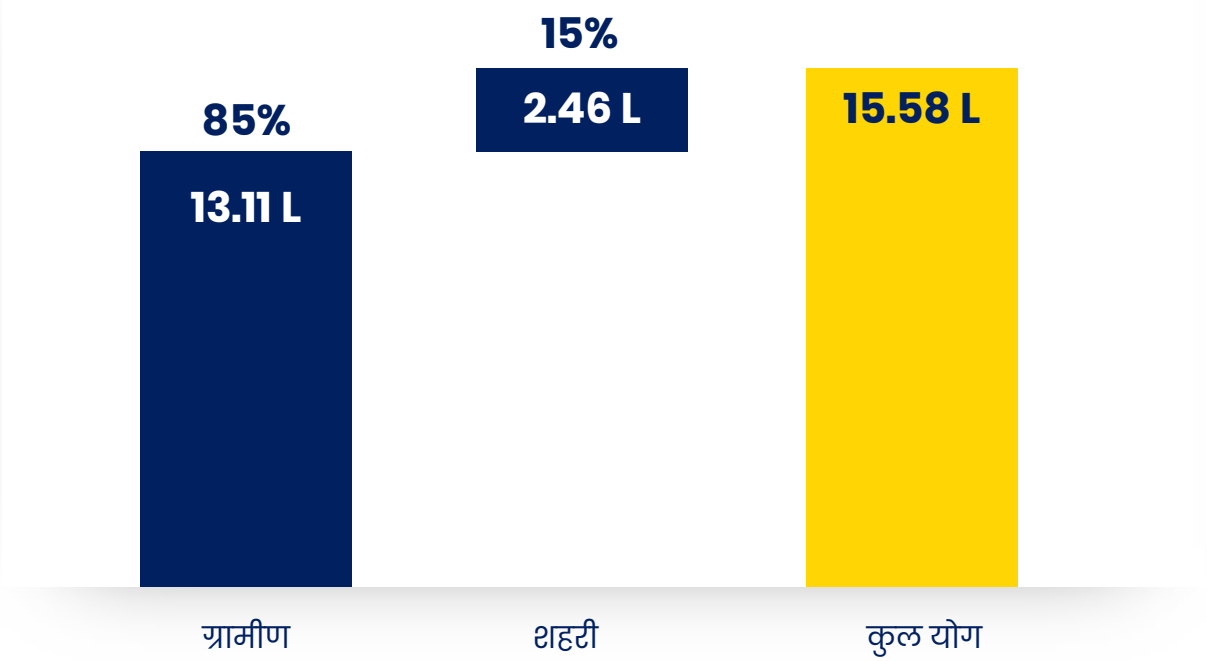

विद्यार्थियों की संख्या – स्थानानुसार (2017-18)

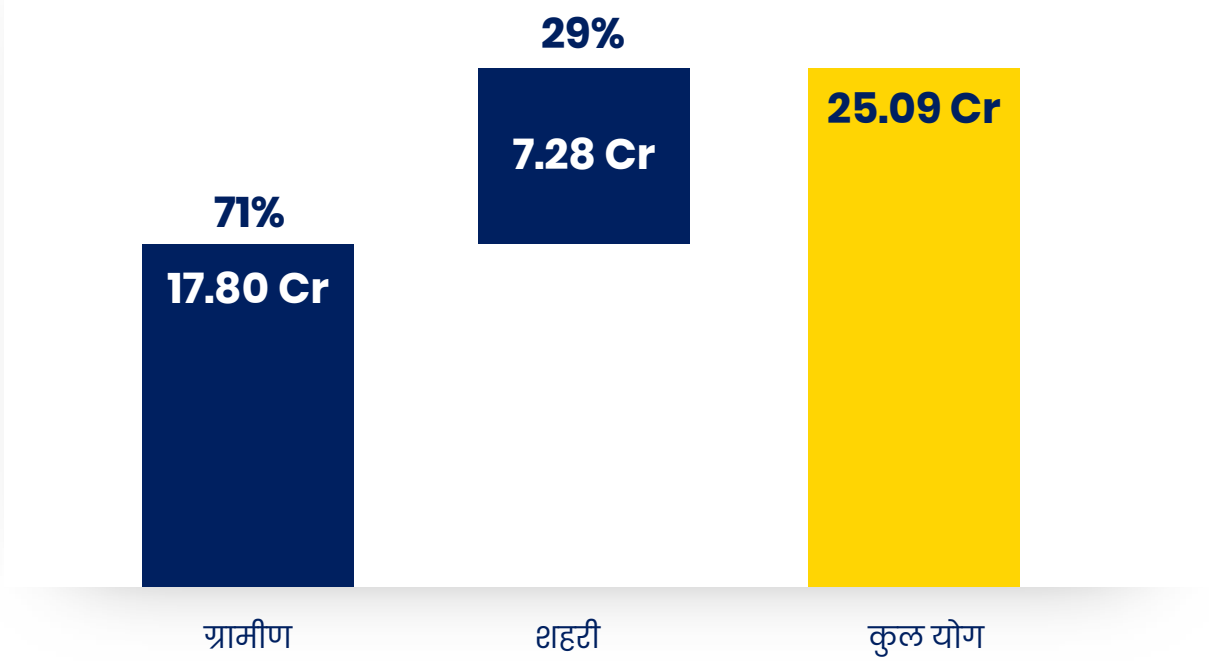

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source: DISE

समान रूप से सभी टीचरों में से तीन-चौथाई ग्रामीण इलाकों में रहते हैं

- शहरी और ग्रामीण, दोनों ही इलाकोंमें टीचरों की संख्या बढ़ी है।
- शहरी इलाकों में 2013 से 2018 के दौरान टीचरों की संख्या 21 लाख से बढ़कर 25 लाख हुई
- इसी अवधि में ग्रामीण इलाकों में चीटरों की संख्या 61 लाख से बढ़कर 67 लाख पहुंची

टीचरों की संख्या – ग्रामीण बनाम शहरी

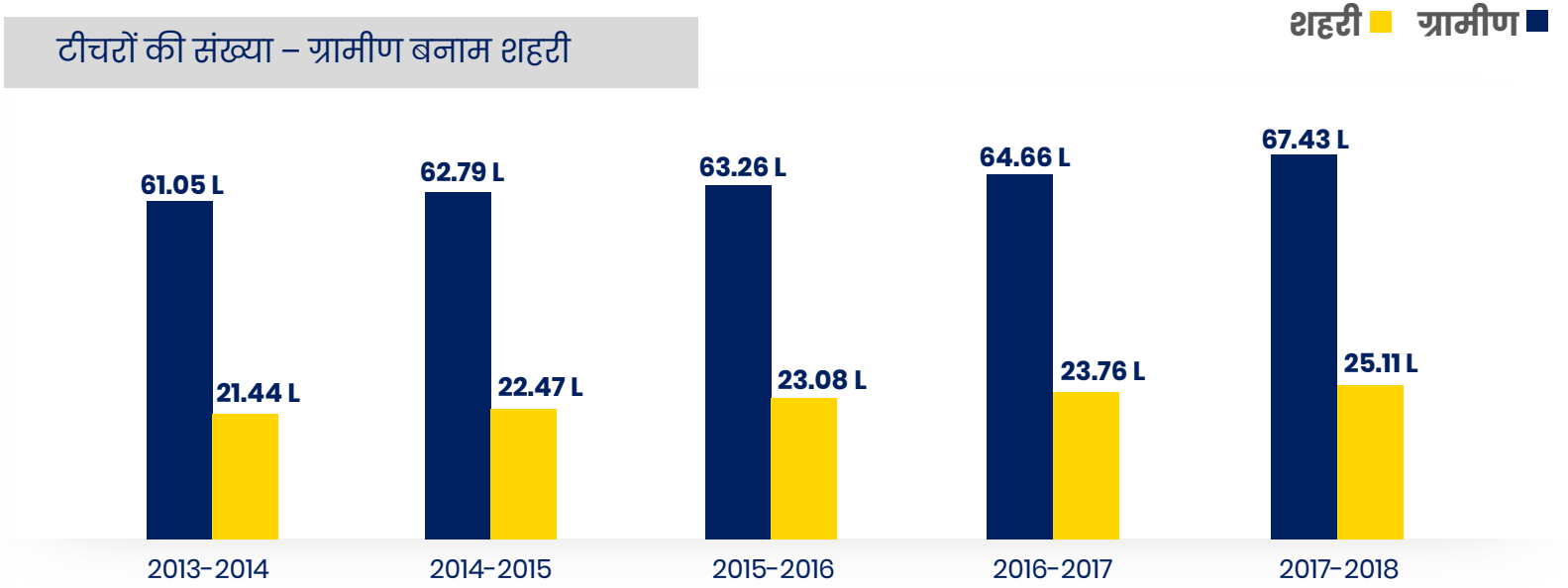

इलाके के अनुसार टीचरों का अनुपात

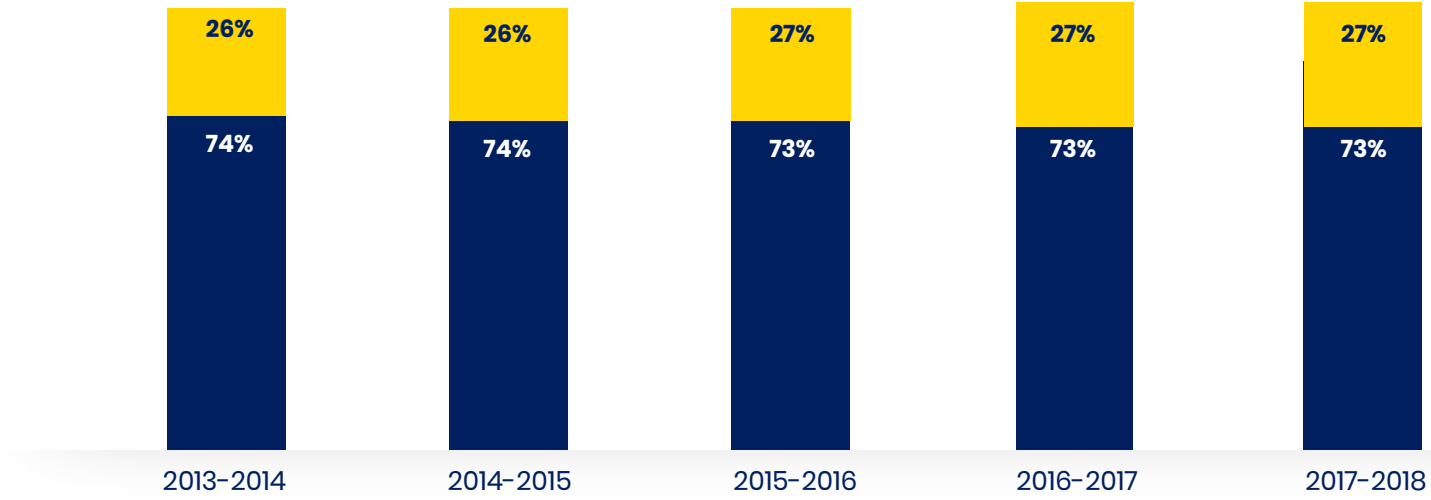

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source: DISE

निजी बनाम सरकारी

स्कूलों की कुल संख्या में से 70 % या 11 लाख सरकारी स्कूल हैं लेकिन इनकी संख्या घट रही है

- 2013 से 2018 के बीच निजी स्कूलों का प्रतिशत 0.5 फीसदी बढ़ा
- हालांकि सरकारी स्कूलों की संख्या में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। लेकिन इनका प्रतिशत 0.2 फीसदी घटा है।

मैनेजमेंट के प्रकार के अनुसार स्कूलों की संख्या (2017-18)

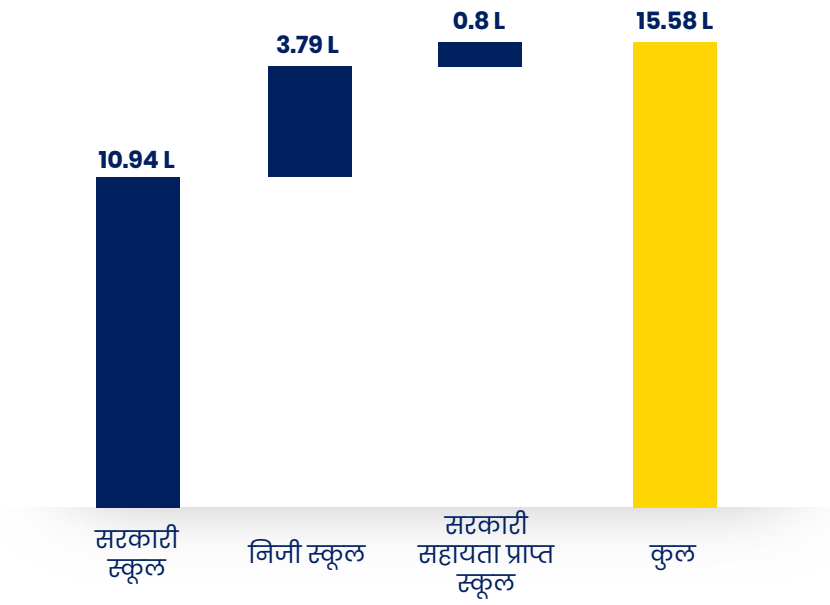

मैनेजमेंट के प्रकार के अनुसार स्कूलों की संख्या

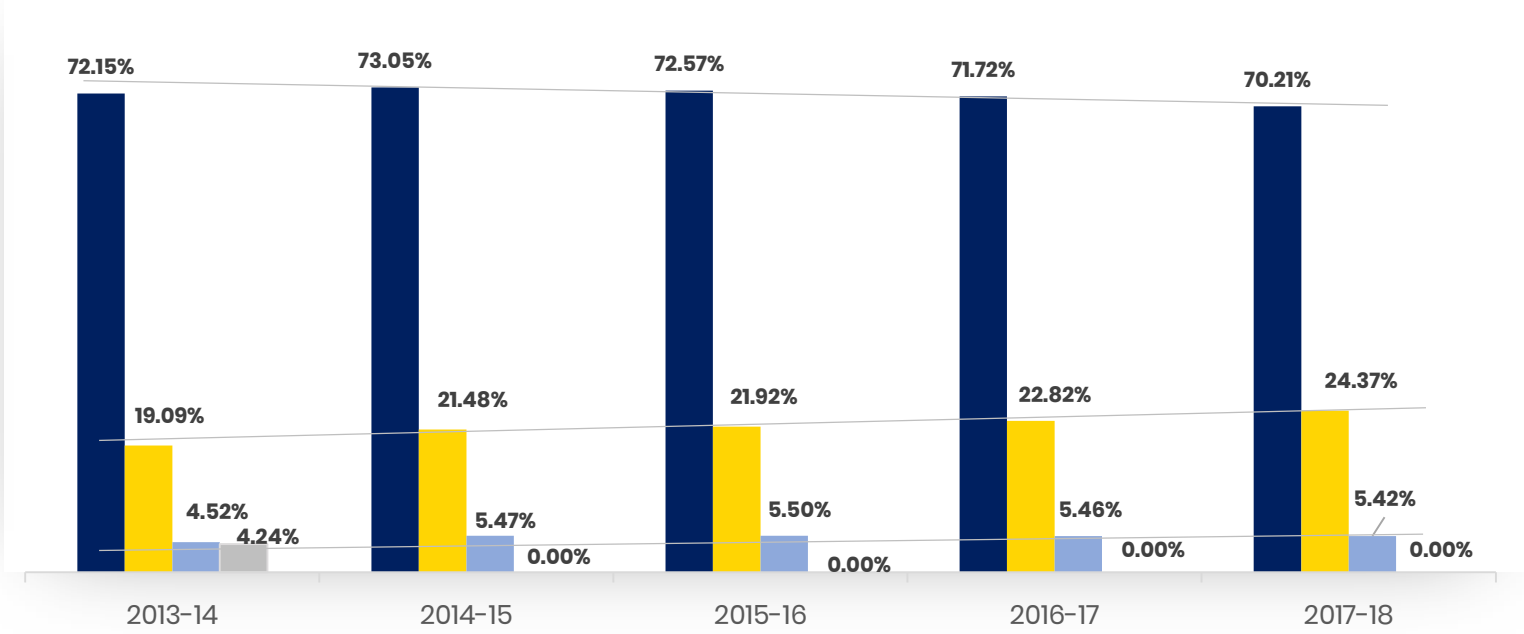

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source: DISE

निजी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है

- 2013-14 से निजी स्कूलों में होने वाली भर्तियों और उनके प्रतिशत हिस्से में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है
- इसी अवधि के दौरान सरकारी 2014-15 में सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़े लेकिन इसके बाद से इसमें गिरावट आई
- इस पांच वर्ष की अवधि के दौरा, सभी राज्यों में निजी स्कूलों मेंहोने वाली भर्तियों में बढ़ोत्तरी देखी जा सकती है।

मैनेजमेंट के प्रकार के अनुसार दाखिला

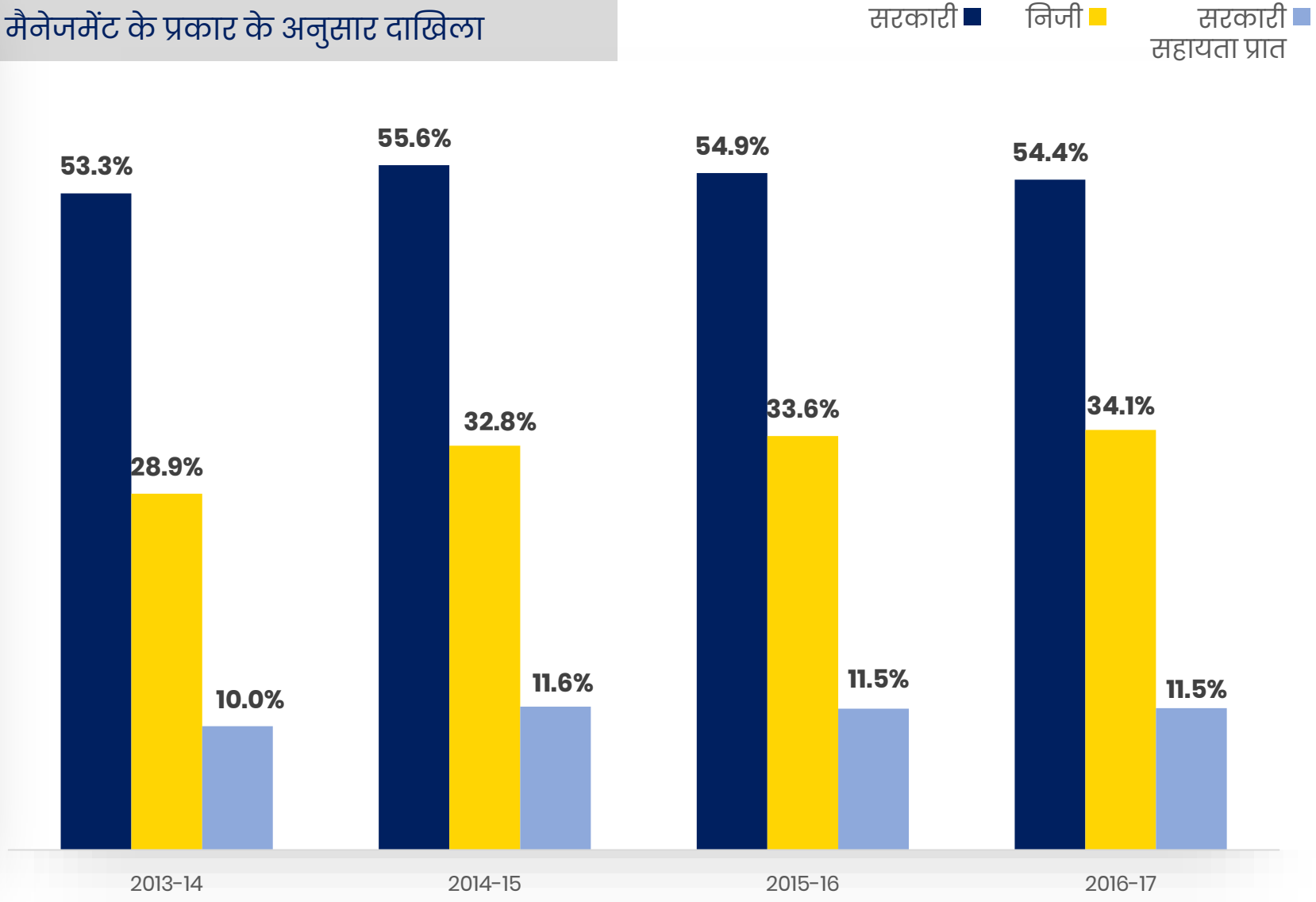

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source: DISE

ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों की संख्या अधिक

- ग्रामीण इलाकों के 77% स्कूल सरकारी हैं। लेकिन शहरों में केवल 33% स्कूल सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं।
- शहरी और ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों के प्रतिशत में हल्की गिरावट आई

मैनेजमेंट के प्रकार के अनुसार स्कूलों का प्रतिशत (ग्रामीण)

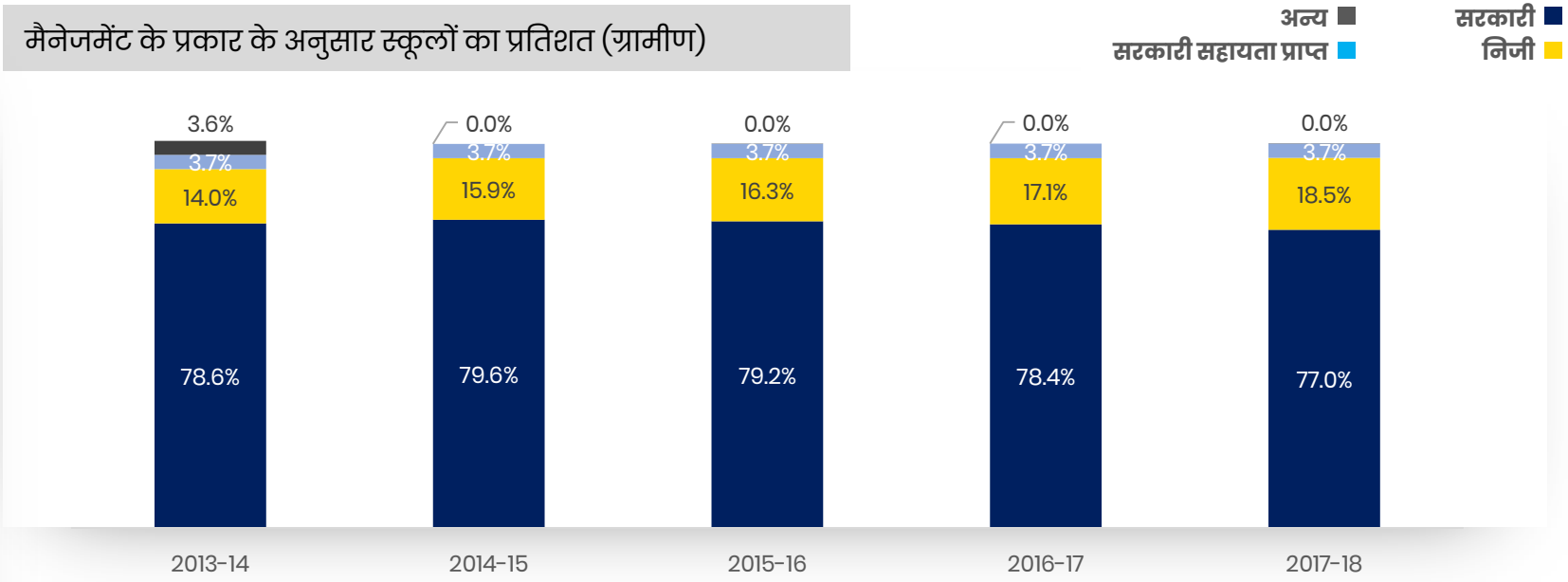

मैनेजमेंट के प्रकार के अनुसार स्कूलों का प्रतिशत (शहरी)

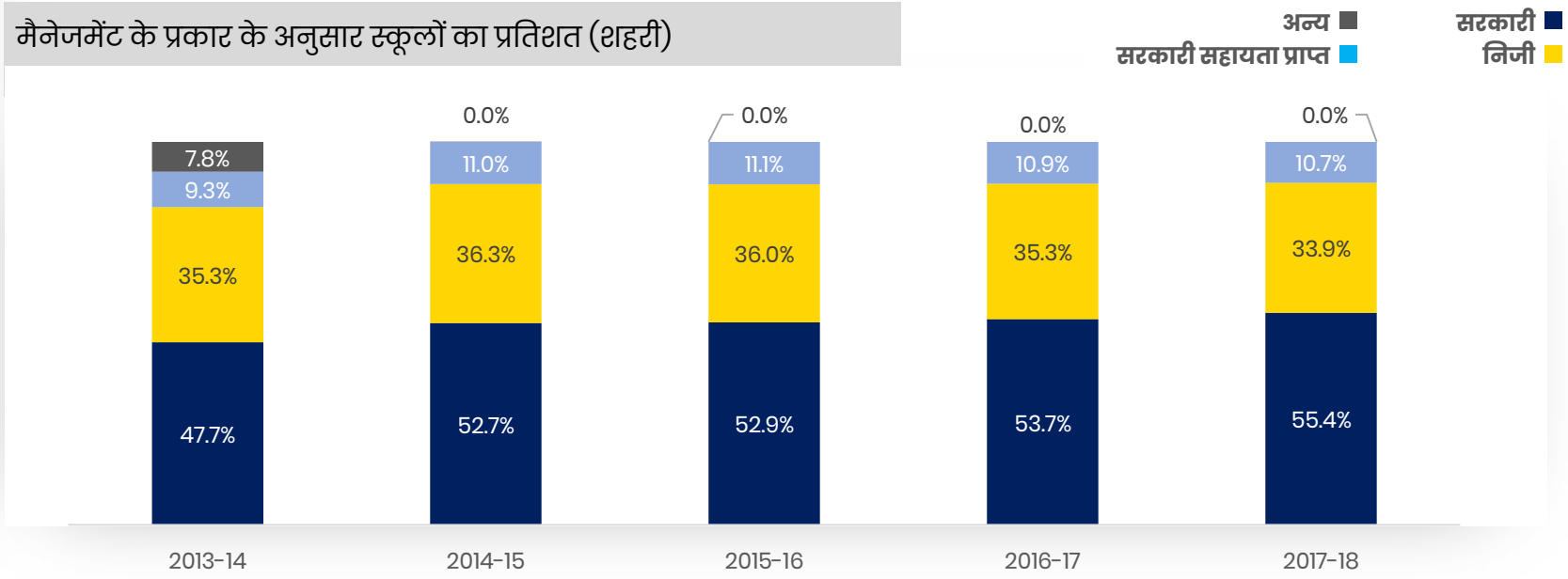

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source: DISE

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रामीण परिवेश के ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं।

भर्तियों के मामले में ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में निजी स्कूलों का प्रतिशत हिस्सा बढ़ा

मैनेजमेंट के प्रकार के अनुसार भर्तियों का हिस्सा (शहरी)

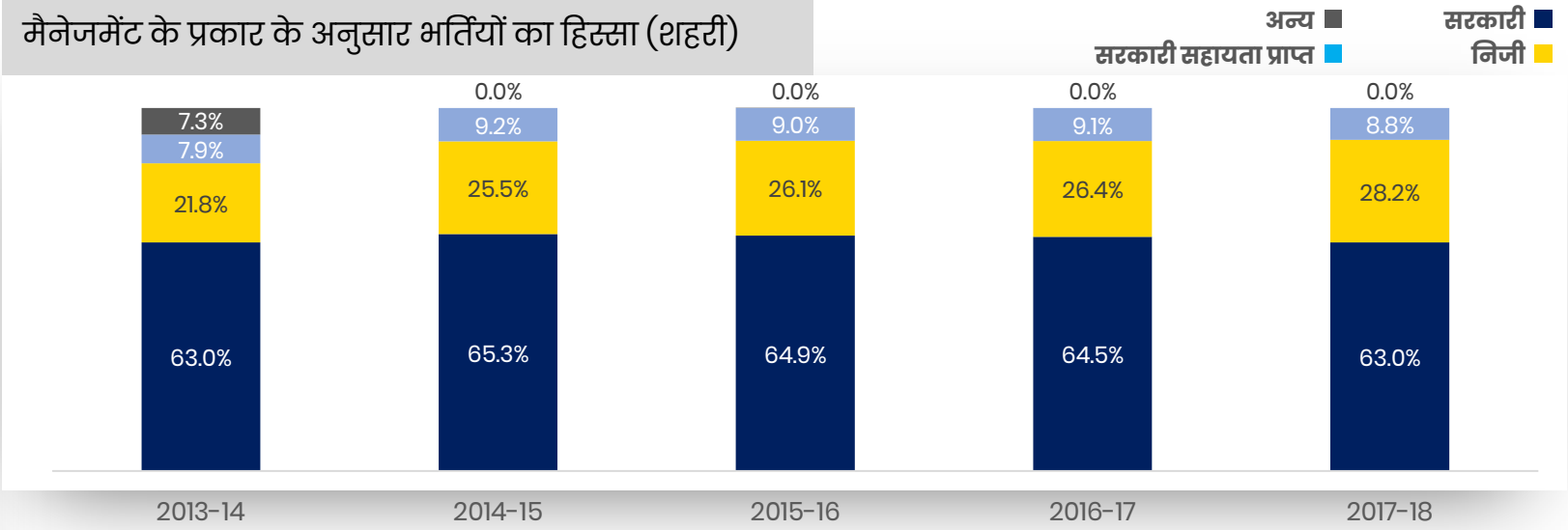

मैनेजमेंट के प्रकार के अनुसार भर्तियों का हिस्सा (ग्रामीण)

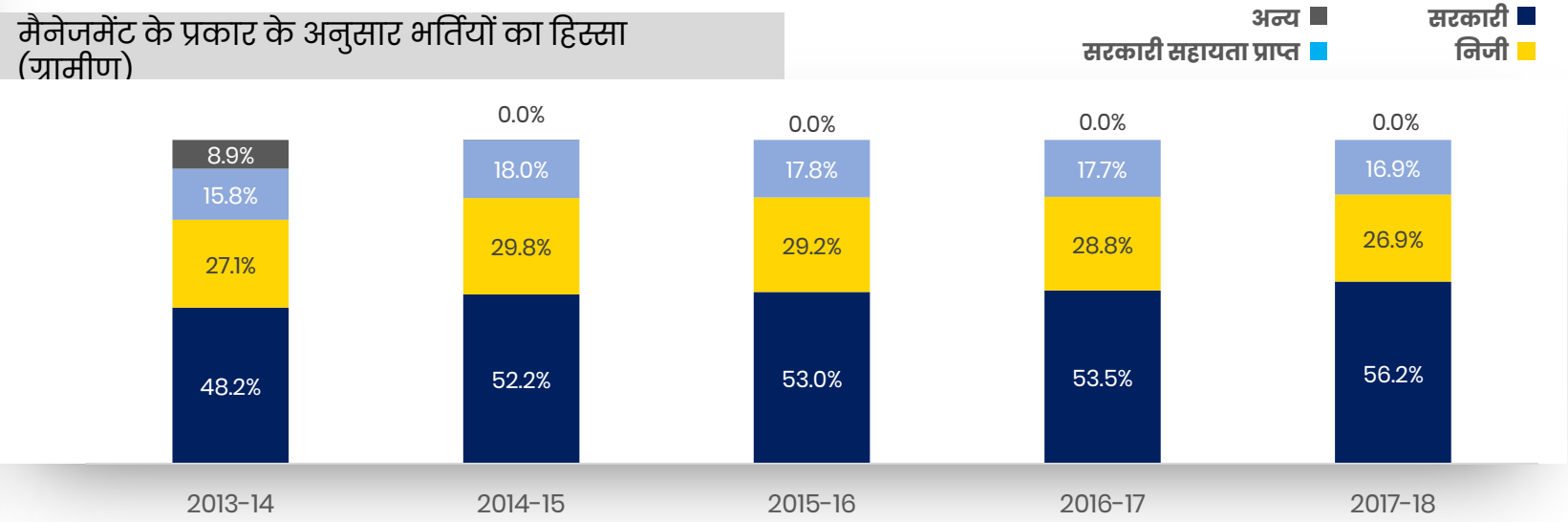

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source: DISE

सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, मिज़ोरम और उत्तराखंड में निजी स्कूलों की ओर बढ़ा झुकाव

- ज्यादातर राज्यों में निजी स्कूलों के प्रतिशत हिस्से में बढ़ोत्तरी
- इसके ठीक उलट त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निजी स्कूलों का प्रतिशत हिस्सा घटा

निजी स्कूलों की हिस्सेदारी में अंतर (2017-18 बनाम 2013-14)

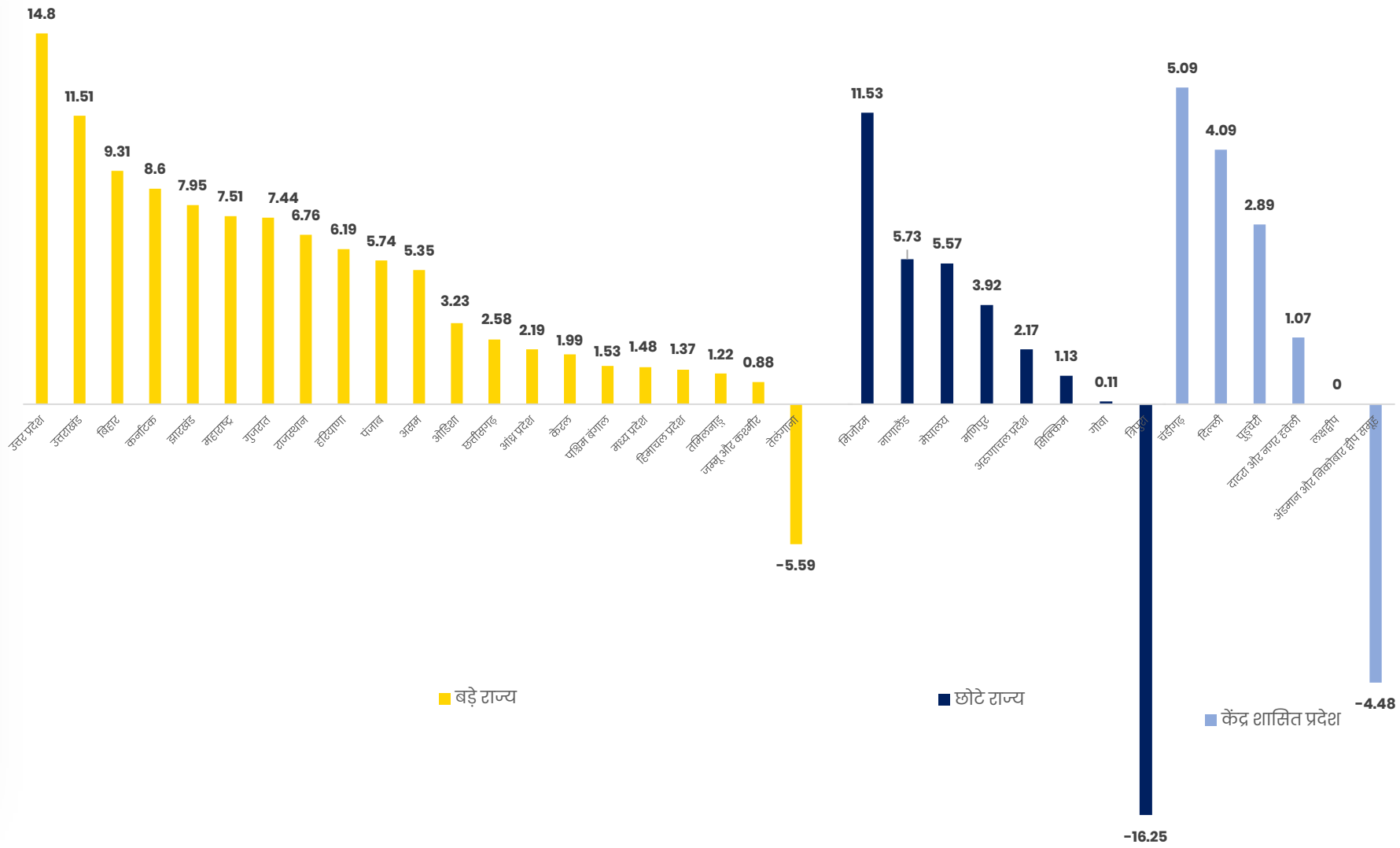

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source: DISE

निजी स्कूलों में प्रति स्कूल विद्यार्थियों की संख्या सरकारी स्कूलों के मुकाबले ज्यादा

- सरकारी स्कूलों में ग्रामीण और शहरी इलाकों में क्रमश: 111 और 234 बच्चे पढ़ते हैं। जबकि निजी स्कूलों में यह संख्या ग्रामीण इलाकों में 207 और शहरी इलाकों में 299 रही।

- 2013- 2018 के बीच प्रति स्कूल विद्यार्थियों की संख्या घटी है लेकिन यह ट्रेंड निजी स्कूलों में ज्यादा देखने को मिला।

प्रति स्कूल विद्यार्थियों की संख्या
(2013-14 बनाम 2017-18)

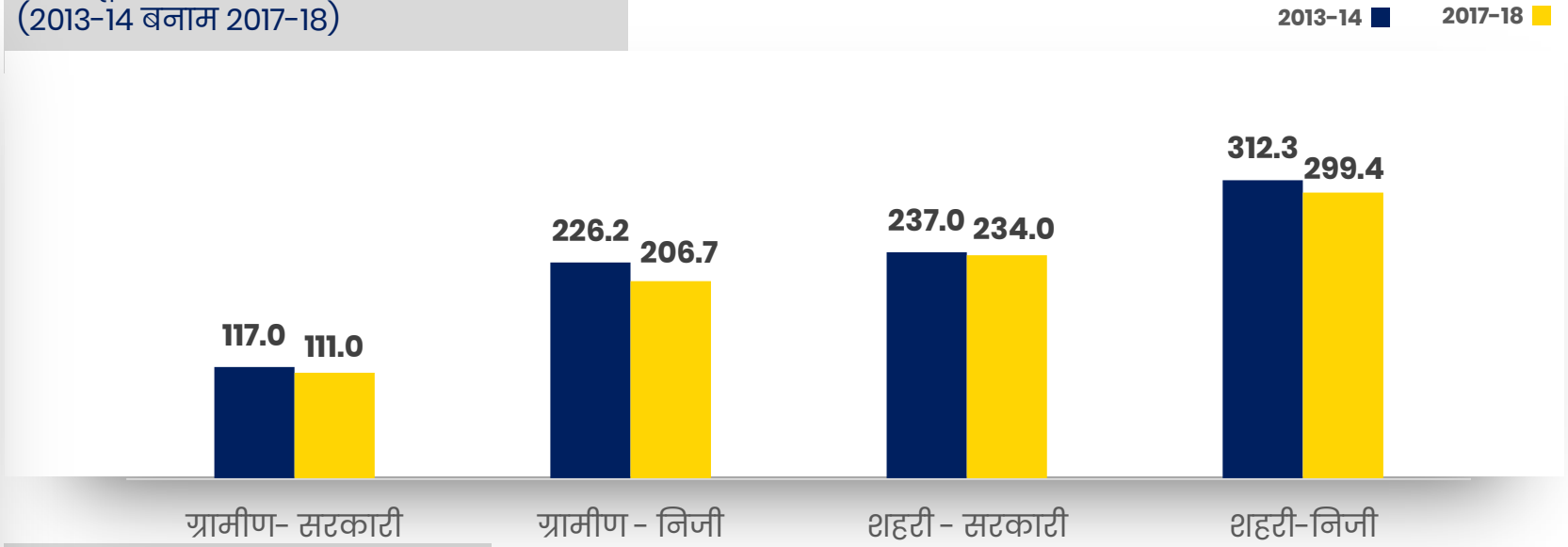

प्रति स्कूल विद्यार्थियों की संख्या
(2017-18)

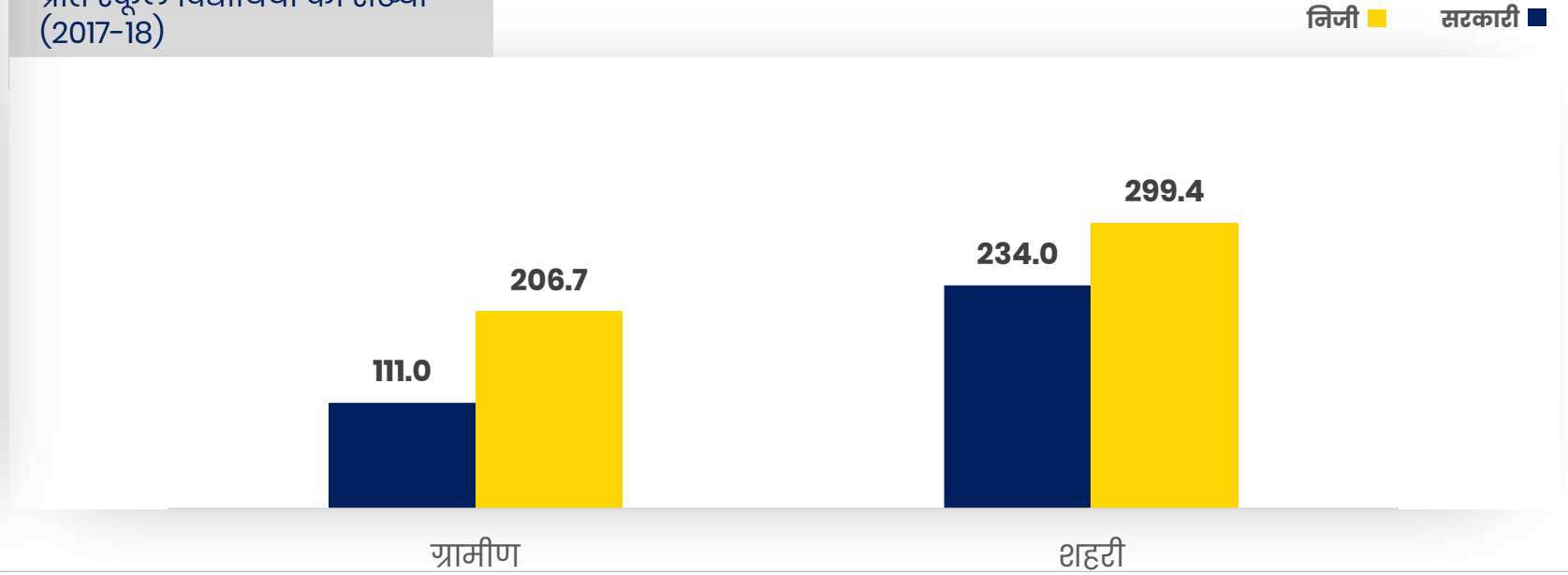

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source: DISE

भारत के अधिकतर टीचर्स सरकारी स्कूलों में कार्यरत

- 2013 से 2018 के बीच सरकारी स्कूलों में टीचरों का प्रतिशत 56% से घटकर 53.8% हुआ।
- इसी अवधि में निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या 8% बढ़ोत्तरी के साथ 29.4% से बढ़कर 37% हुई।

मैनेजमेंट के प्रकार के अनुसार टीचरों की संख्या (2017-18)

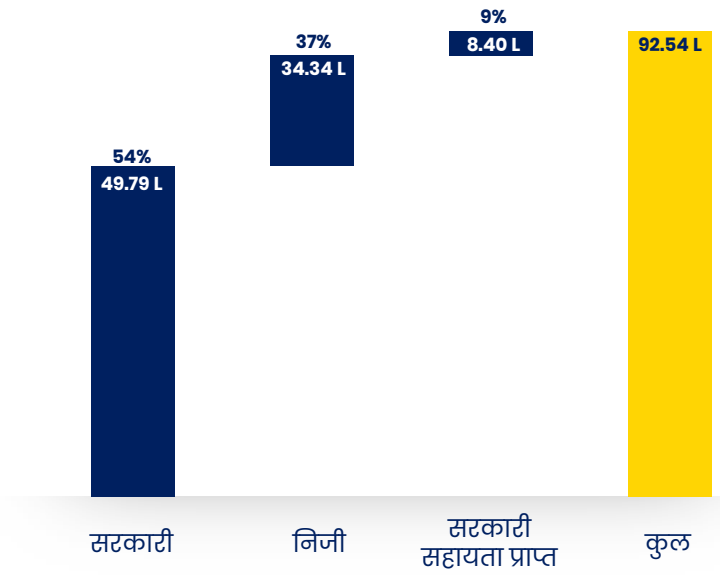

मैनेजमेंट के प्रकार के अनुसार टीचरों की संख्या

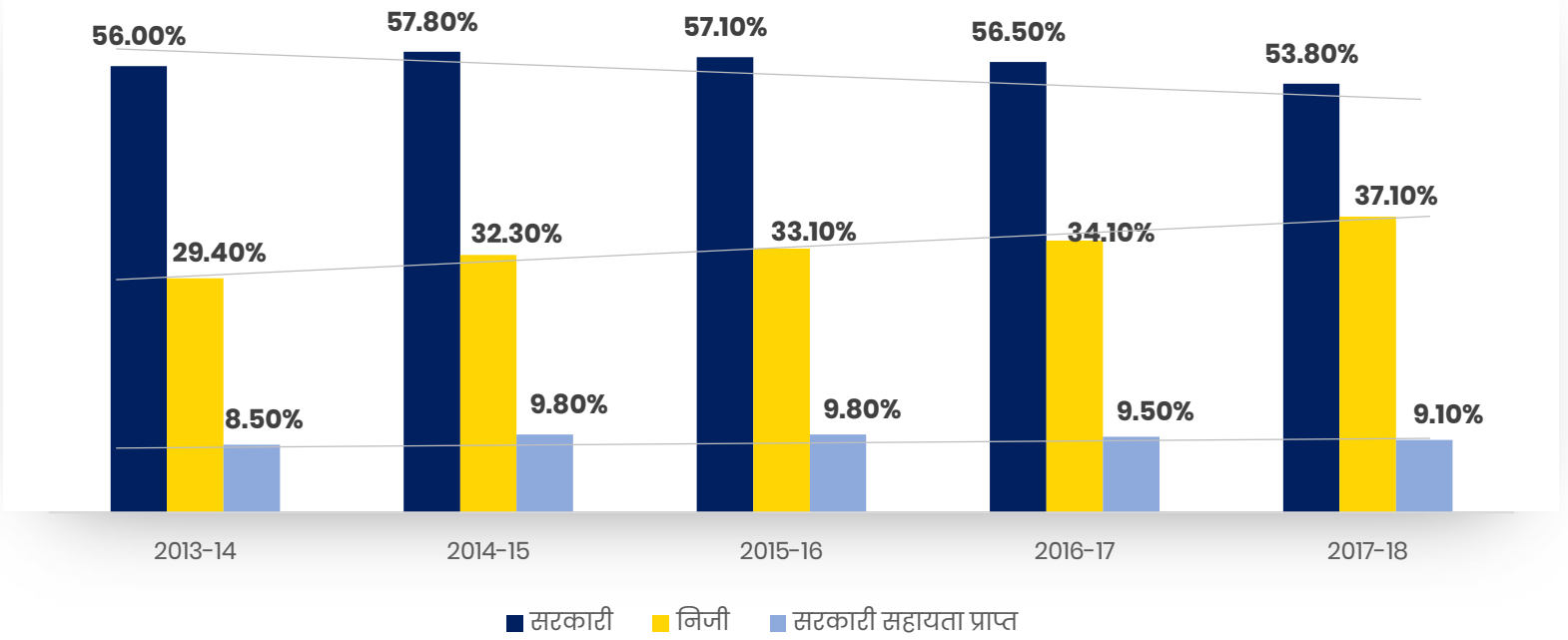

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source: DISE

सरकारी स्कूलों के मुकाबले निजी स्कूलों में प्रति स्कूल टीचरों की संख्या ज्यादा

- शहरी इलाकों के सरकारी स्कूलों में प्रति स्कूल टीचरों की संख्या (8) ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों (4) से दोगुनी रही
- 2013 और 2018 के बीच शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों के निजी और सरकारी स्कूलों में टीचरों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई

प्रति स्कूल टीचरों की संख्या (2013-14 बनाम 2017-18)

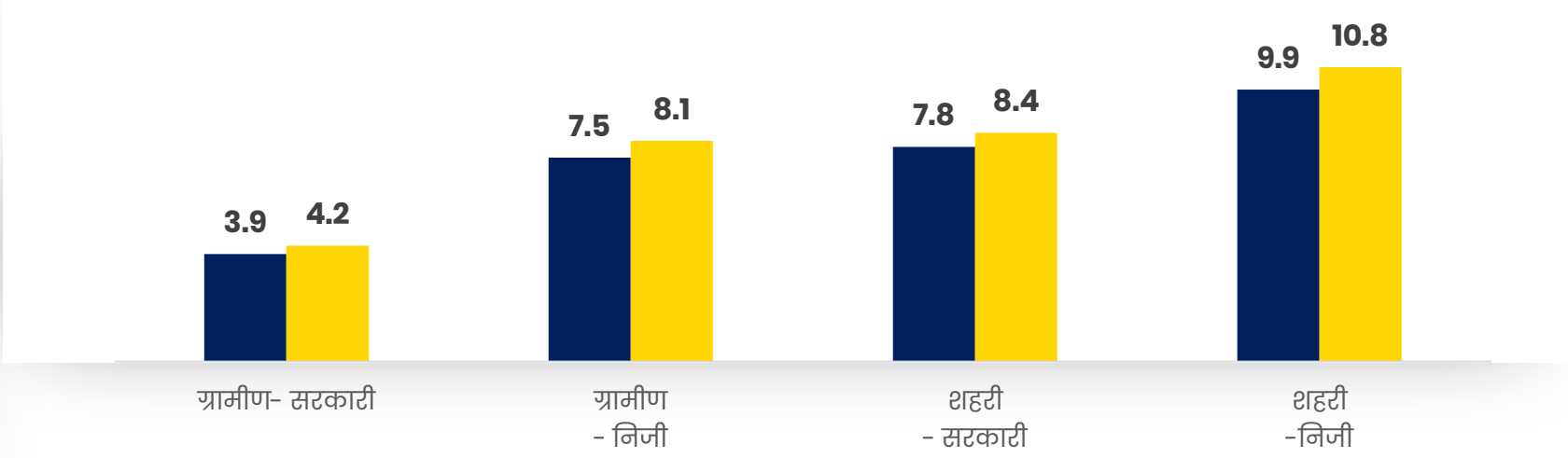

प्रति स्कूल टीचरों की संख्या (2017-18)

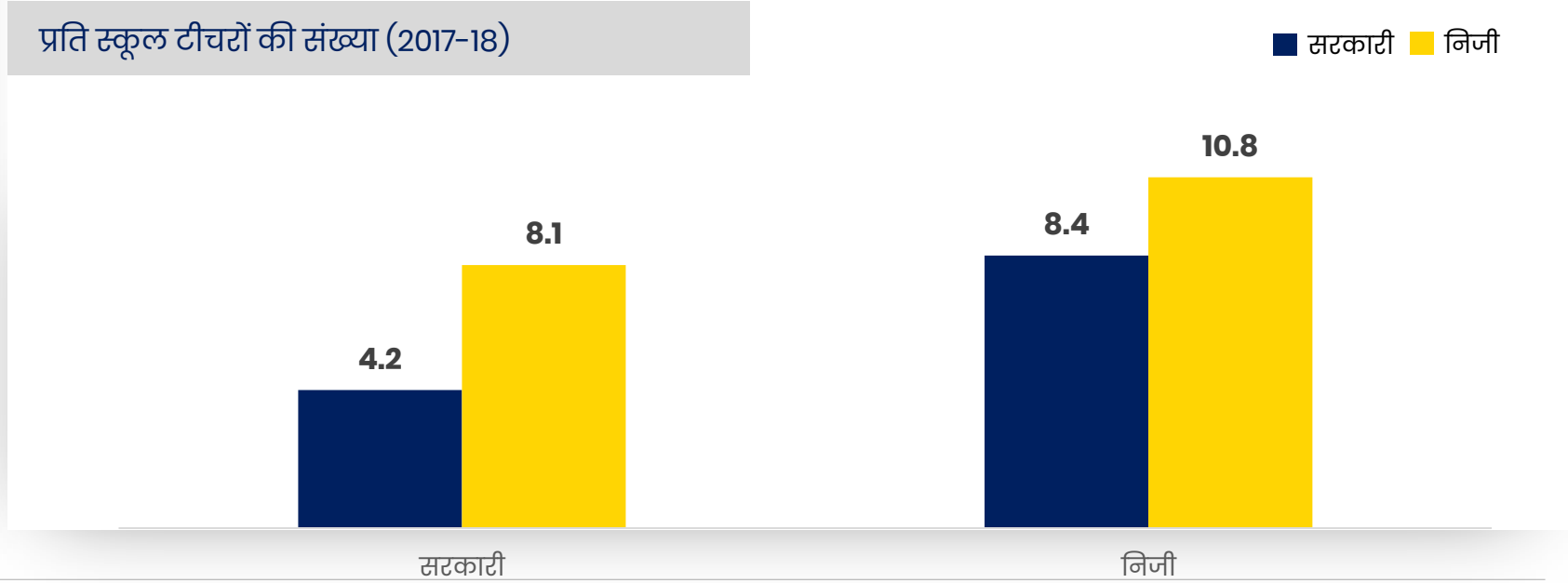

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source: DISE

पढ़ाई के नतीजे

प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर पढ़ाई के नतीजे लगातार निराशाजनक रहे हैं।

भारत में प्राथमिक शिक्षा के नतीजे लगातार निचले स्तर पर रहे हैं। हालांकि बच्चे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में तो जा रहे हैं लेकिन उनमें से कुछ ही बच्चों में अपनी कक्षा के स्तर के लिहाज़ से पढ़ाई की वैसी समझ होती है जैसी होनी चाहिए।

सभी ग्रामीण ज़िलों से लिए गए सैंपल पर आधारित ASER से पता चलता है कि ग्रामीण भारत के पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले 72 % बच्चे साधारण भाग के सवाल नहं हल कर पाते। 3 अंकों से लेकर 1 अंक का भाग कर सकने वाले बच्चों का प्रतिशत 2010 में 68% से घटकर 2018 में केवल 43% रह गया।

कक्षा 5 के लिए NAS साइकल के नतीजे बताते हैं कि 3 और 4 , दोनों सत्रों में भाग लेने वाले 31 में से 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सरकारी स्कूलों के भाषा और गणित के नतीजों में गिरावट दर्ज की गई।

हालांकि सभी श्रेणियों के स्कूलों के नतीजों में गिरावट दर्ज की गई है लेकिन सरकारी स्कूलों के मामले में ये समस्या ज्यादा गंभीर है। कम फीस लेनेवाले निजी स्कूलों का औसत प्रदर्शन कुछ बेहतर रहा। तो वहीं महंगी फीस लेने वाले निजी स्कूलों के नतीजे, अन्य दो प्रकार के स्कूलो से काफी बेहतर रहे लेकिन यहां भी नतीजे अंतर्राष्ट्रीय औसत से नीचे ही रहे।

*Rajagopalan and Agnihotri 2014

पहली कक्षा में छोटे बच्चों के मुकाबले बड़े बच्चों का प्रदर्शन बेहतर

- 4 और 5 साल के बच्चे ज्ञान या समझ संबंधी कई कार्य बड़े आराम से कर लेते हैं।
- पहली क्लास में बच्चों की भाषा और गणित की समझ के प्रदर्शन का उनकी उम्र से गहरा संबंध होता है।
- उदाहरण के तौर पर इस बात को ग्रेड टेबल से समझा जा सकता है। कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों में से 4-5 वर्ष की आयु के महज़ 5.7 % बच्चे कक्षा 1 के स्तर की पाठ्य पुस्तकें पढ़ पाते हैं। तो वहीं 6 वर्ष वाले 12.7% बच्चे , 7 और 8 वर्ष की उम्र के 26 % बच्चे कक्षा 1 केस्तर की किताबें पढ़ लेते हैं।

कक्षा 1 के वे बच्चे जो अपनी उम्र के अनुसार समझ से जुड़े कार्य सही तरीके से कर पाते हैं।

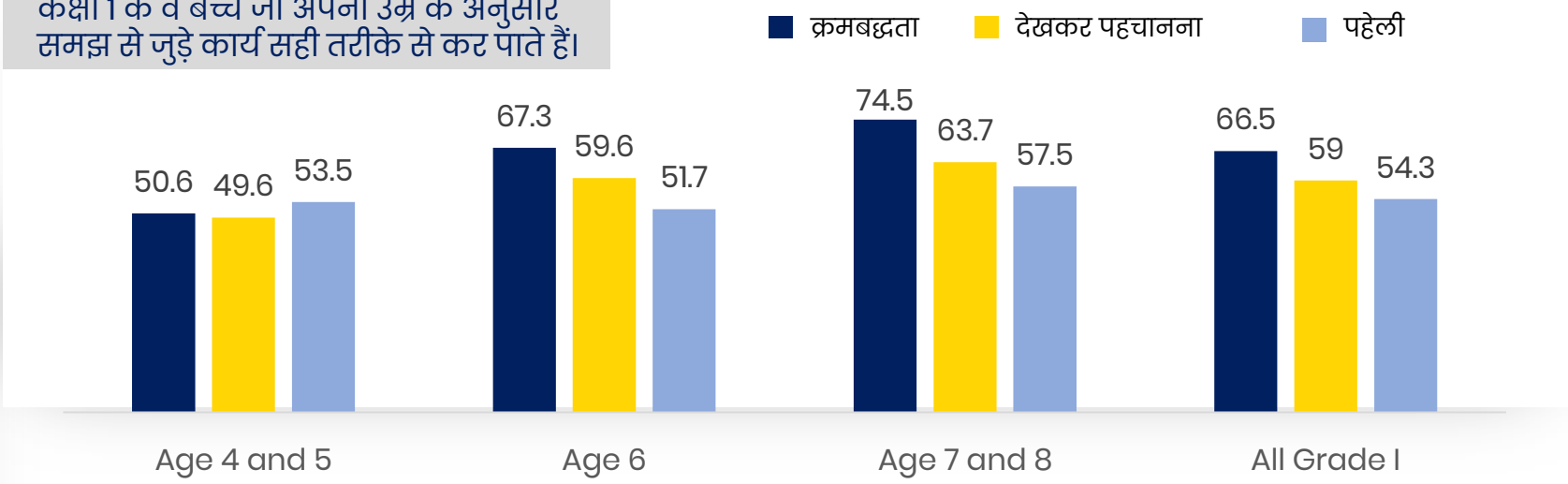

उम्र के अनुसार बच्चों की पढ़ने की क्षमता का वितरण (2019)

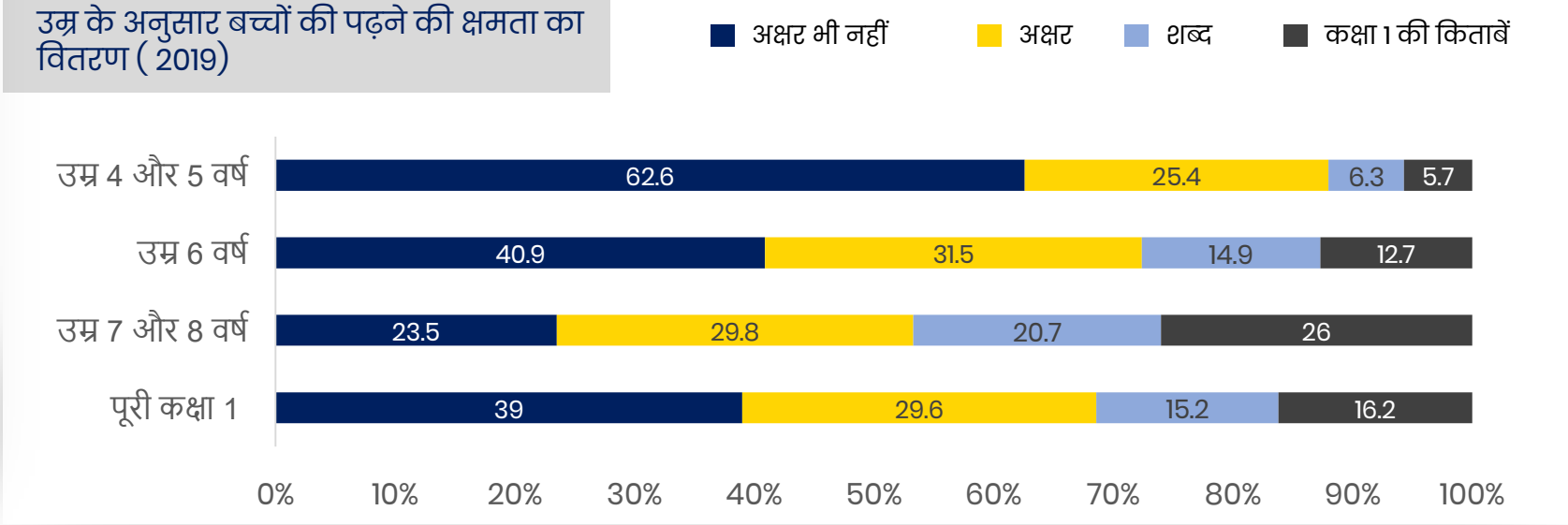

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source : ASER 2019

कक्षा 3 तक बच्चे, कक्षा के अनुसार अपनी क्षमताओं में पिछड़ने लगते हैं

- बच्चों का बुनियादी कौशल हर कक्षा के साथ बढ़ता जाता है। लेकिन कक्षा 3 में पहुंचने के बावजूद, बच्चों का एक बड़ा हिस्सा उतनी क्षमताएं अर्जित नहीं कर पाता जितनी कि उनमें पहली कक्षा के अंत तक आ जानी चाहिए।

- उदाहरण के तौर पर पहली कक्षा की किताब पढ़ने की क्षमता के मामले में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की क्षमता में 34.8% सुधार आता है जबकि तीसरी कक्षा के बच्चों में यह क्षमता 50.8% बहो जाती है। यानि पाठ्यक्रम के हिसाब से बच्चे पहले ही 2 साल पिछड़ चुके होते हैं।

- इसी तरह पहली कक्षा में केवल 41.1% बच्चे ही दो अंकों की संख्या पहचानते हैं। जबकि तीसरी कक्षा में यह प्रतिशत बढ़कर 72.2% हो जाता है।

कक्षानुसार बच्चों की संख्या पहचानने की क्षमता का वितरण

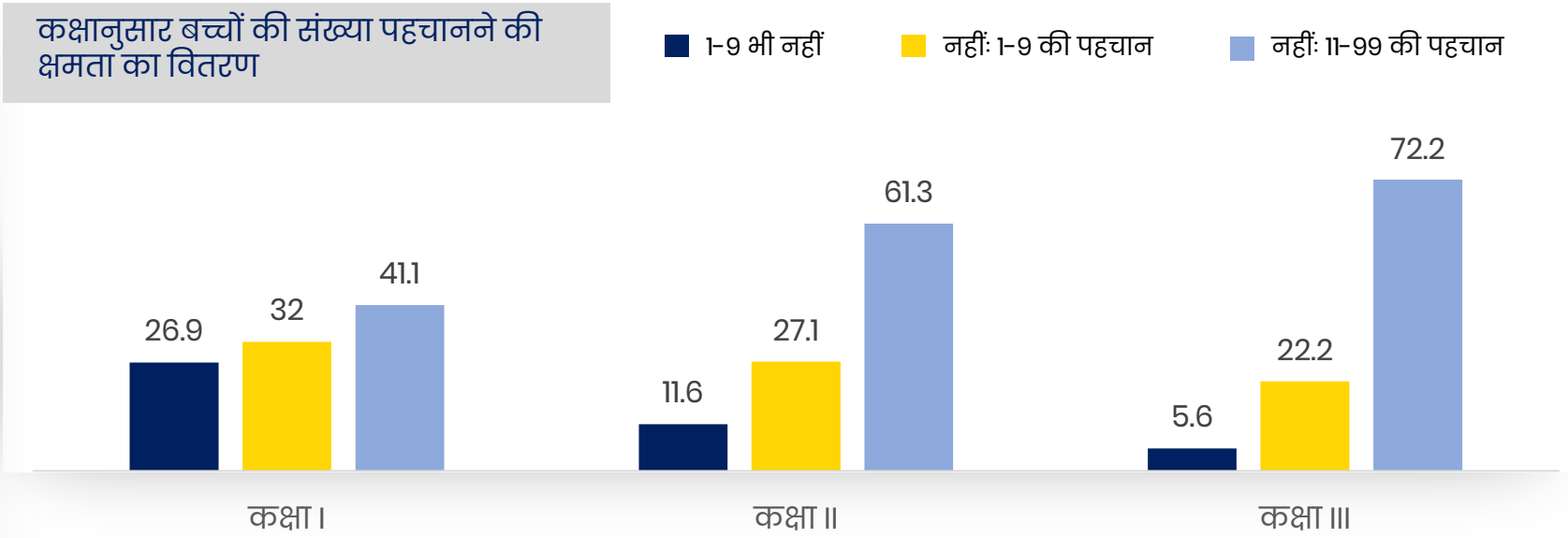

कक्षानुसार बच्चों की संख्या पहचानने की क्षमता का वितरण

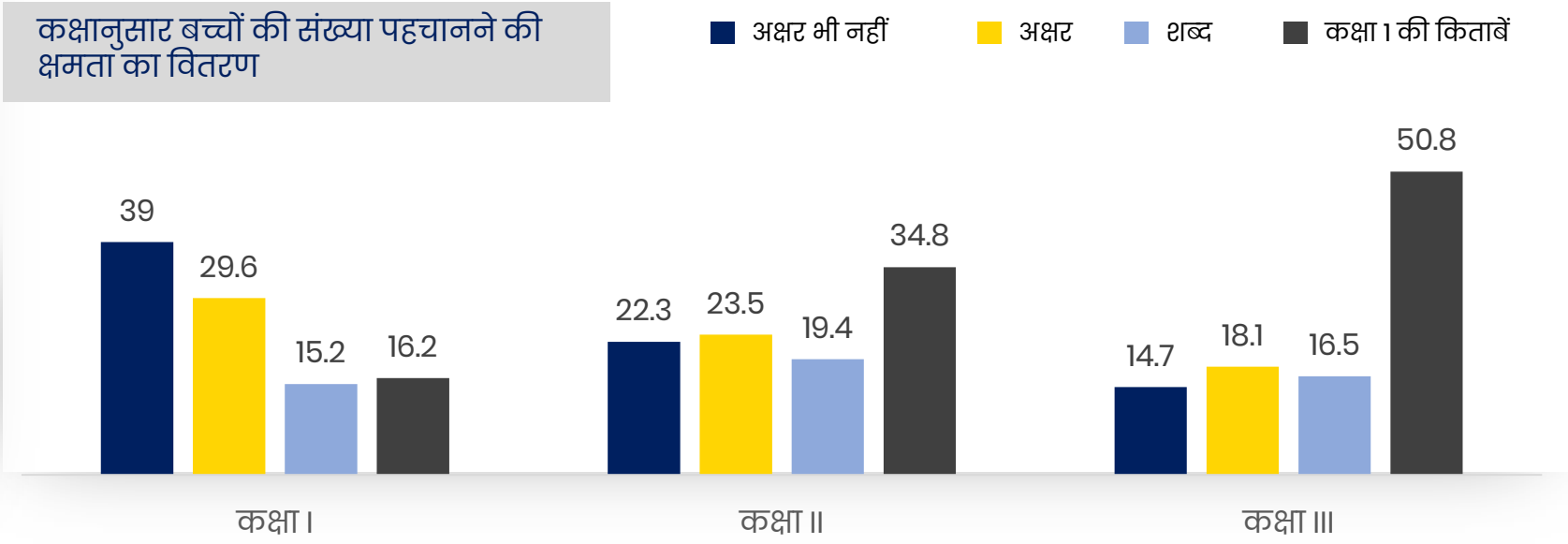

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source : ASER 2019

कक्षा 5 में पढ़ने वाले लगभग 50% बच्चे, कक्षा 2 की किताबें नहीं पढ़ सकते, 72% बच्चे विभाजन नहीं कर पाते।

- सरकारी स्कूलों के मुकाबले पढ़ने के मामले में निजी स्कूलों का प्रतिशत 20.9% ज्यादा है जबकि गणित के मामले में यह प्रतिशत 17% ज्यादा है।
- पांचवीं कक्षा में पढ़नेवाले आधे से ज्यादा बच्चे कम से कम कक्षा 2 की किताबें पढ़ सकते हैं। यह आंकड़ा 2016 में 47.9% था जो 2018 में बढ़कर 50.5% हो गया।
- देश भर में भाग कर पाने वाले बच्चों का प्रतिशत 2012 में 24.9% से बढ़कर 2018 में 27.9% हो गया। निजी और सरकारी दोनं ही स्कूलों में यह प्रतिशत बढ़ा है।

पांचवीं कक्षा के ऐसे बच्चों का % जो दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ सकते हैं

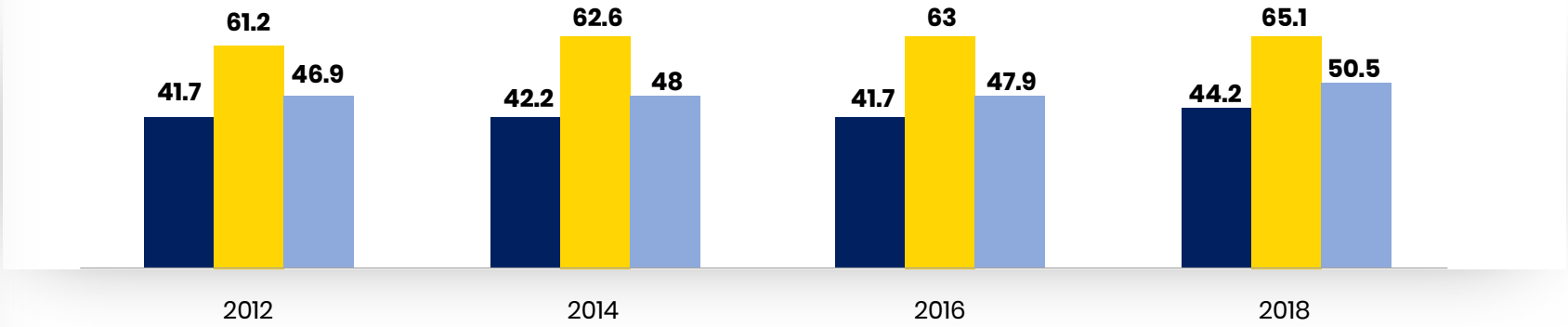

पांचवीं कक्षा के उन बच्चों का % जो भाग कर सकते हैं

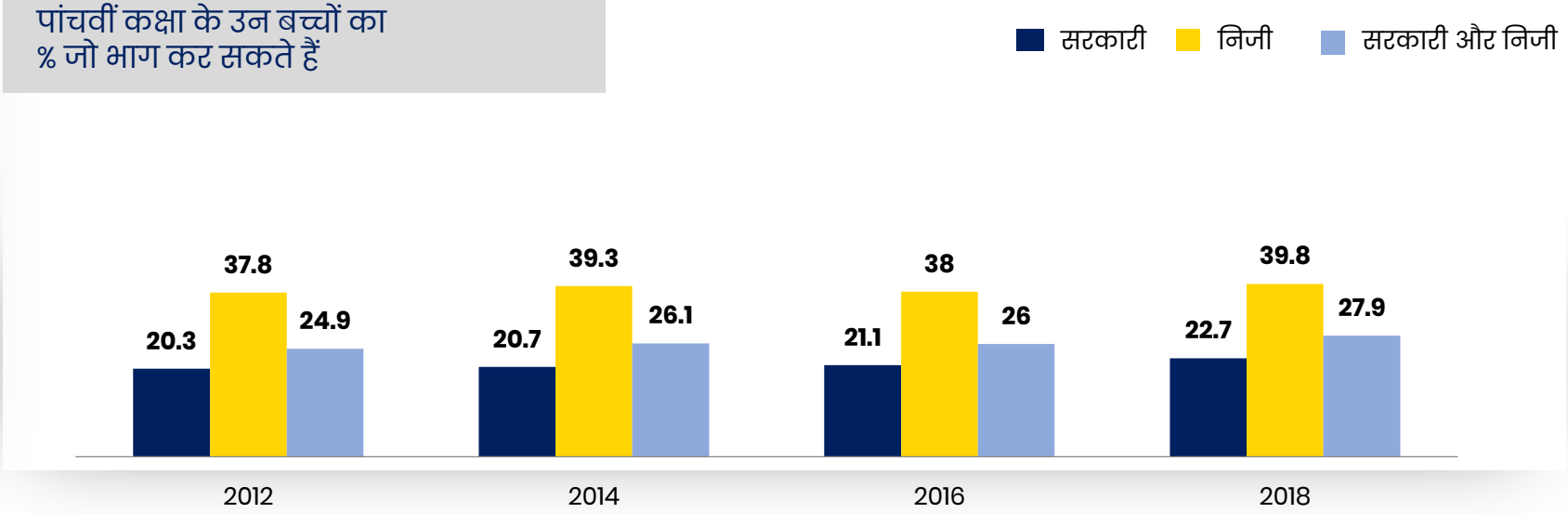

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source : ASER 2018

कक्षा 8 में जाकर ही अधिकांश बच्चे दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ पाते हैं

- आठवीं कक्षा तक आते –आते सरकारी और निजी स्कूलों के बीच का अंतर , पांचवीं कक्षा के मुकाबले काफी कम हो जाता है। पढ़ने और गणित दोनों में ही निजी स्कूलों का स्कोर सरकारी स्कूलों के मुकाबले 14 % अधिक है।
- भारत में कश्रा 8 में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जो कम से कम दूसरी कक्षा की किताब पढ़ सकें, उनकी संख्या 2012 में 76.5% से घटकर 2018 में 73% रह गई है। यह गिरावट निजी और सरकारी दोनों ही स्कूलों के प्रदर्शन में आई है।
- फिलहाल 8वीं कक्षा के लगभग 44% बच्चे , 3 अंकों को 1 अंक से भाग देने वाले सवाल सही ढंग से हल कर सकते हैं। यहां भी 2012 के मुकाबले निजी और सरकारी दोनों ही स्कूलों के प्रदर्शन में गिरावट आई है।

8वीं कक्षा के वे बच्चे जो दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ सकते हैं।

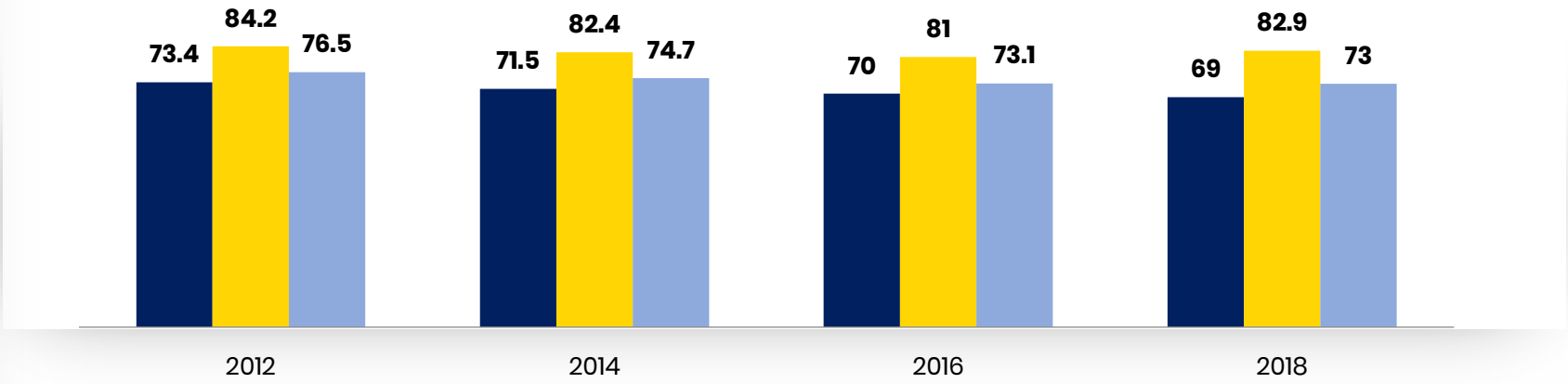

8वीं कक्षा के वे बच्चे जो भाग कर सकते हैं।

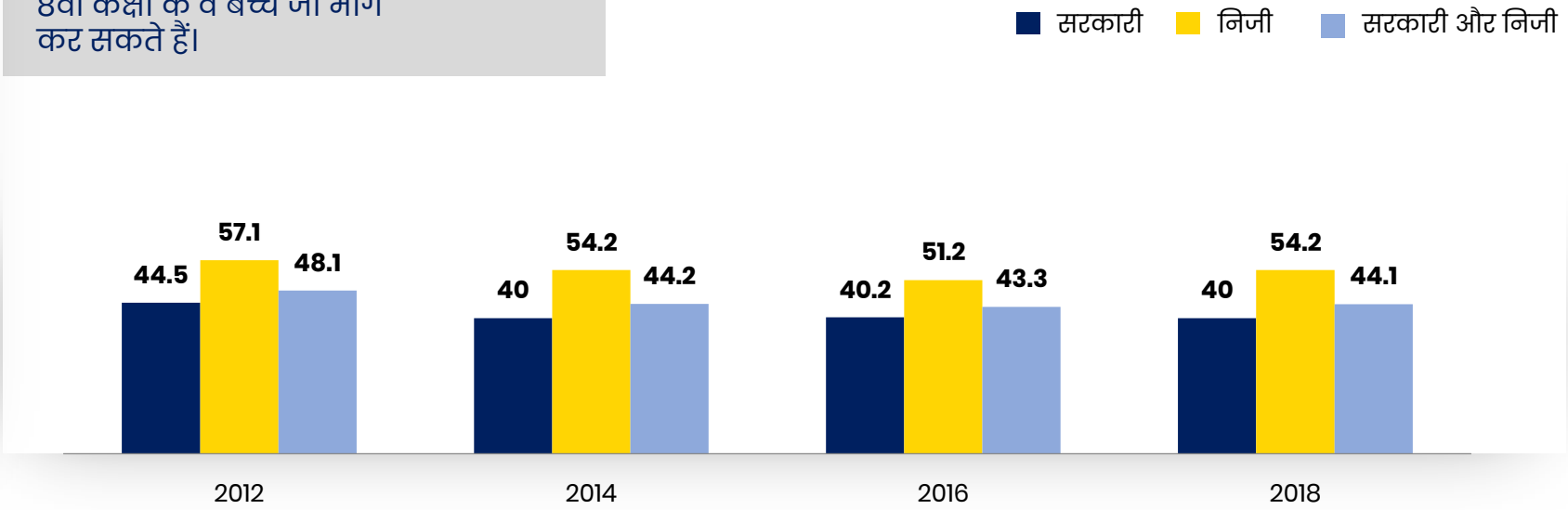

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source : ASER 2018

NAS डेटा के अनुसार 8वीं कक्षा के 54% बच्चे अपनी कक्षा के स्तर की किताबें पढ़ सकते हैं।

- कक्षा 3 में पढ़नेवाले 67% विद्यार्थी छोटे पाठ पढ़ और समझ सकते हैं। लेकिन कक्षा 8 तक पहुंचते-पहुंचते यह संख्या घटकर 54% रह जाती है।
- तीसरी कक्षा के 56% विद्यार्थी साधारण गणित का इस्तेमाल अपने रोज़-मर्रा के जीवन में कर सकते हैं।; लेकिन कक्षा 8 तक पहुंचते हुए यह संख्या घटकर 38% रह जाती है।
- 10वीं कक्षा के बच्चे भाषा मेंई विषयों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जबकि गणित और विज्ञान जैसे विषयों में उनका प्रदर्शन खराब रहता है।

विद्यार्थियों का औसत प्रदर्शन (कक्षा 10)

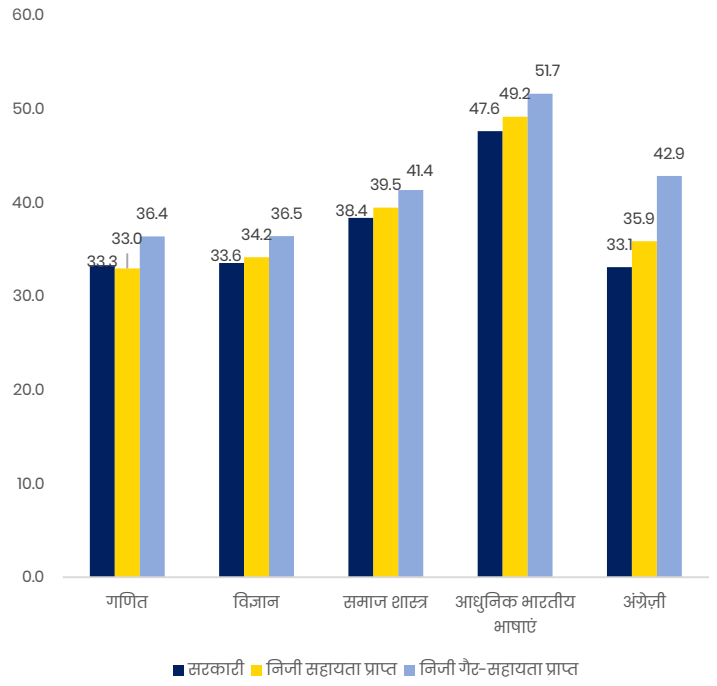

वो जो समझकर पढ़ते हैं

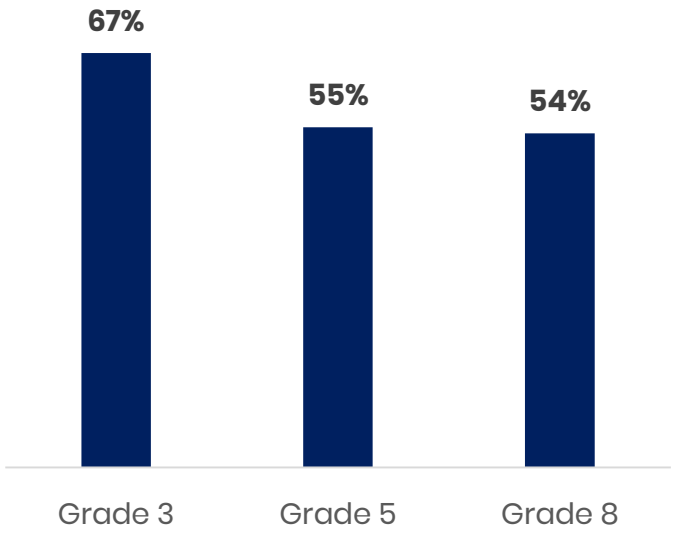

वो जो रोज़मर्रा के कामों में गणित का इस्तेमाल करते हैं

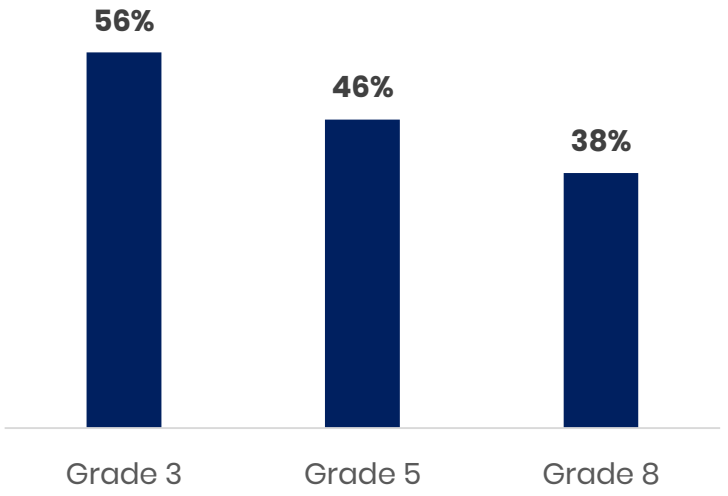

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source: DISE

बजट

2014 और 2017 के बीच शिक्षा क्षेत्र पर बजटीय खर्च में लगातार बढ़ोत्तरी

- 2014-15 में शिक्षा पर बजटीय खर्च 3.6 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2016-14 में 4.6 लाख करोड़ किया गया।
- शिक्षा पर बजटीय खर्च का 80% योगदान राज्यों ने वहम किया।

बजटीय खर्च

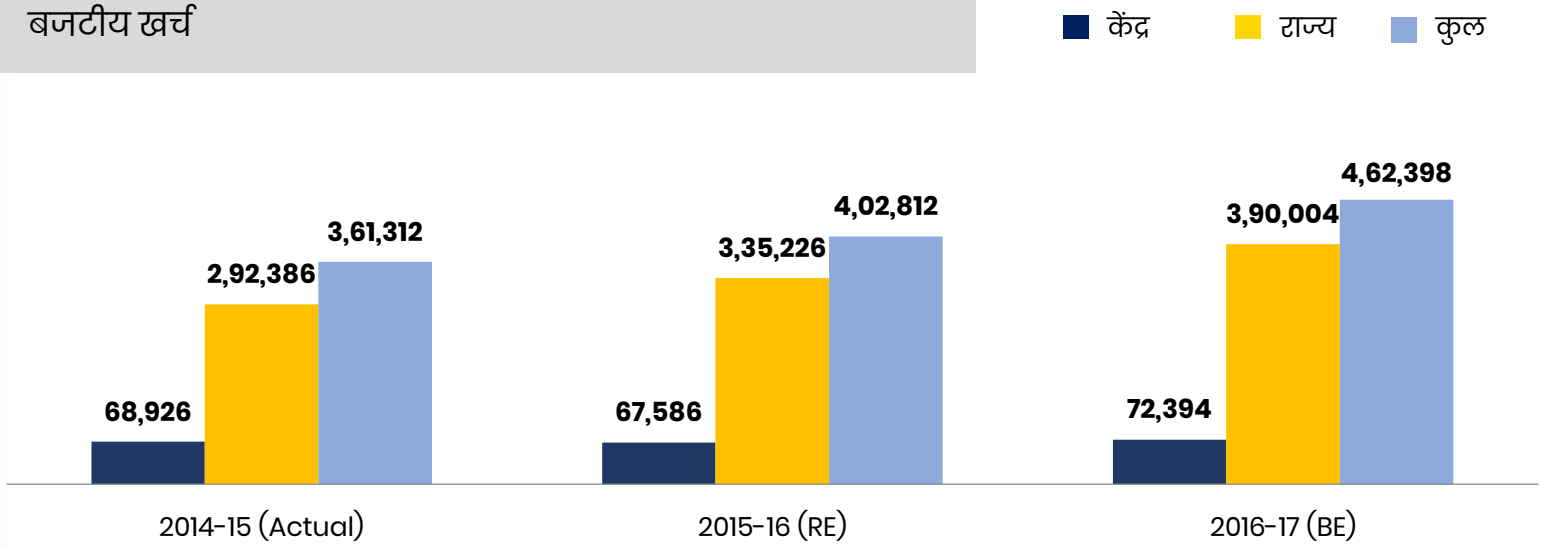

बजटीय खर्च में % योगदान (केंद्र बनाम राज्य)

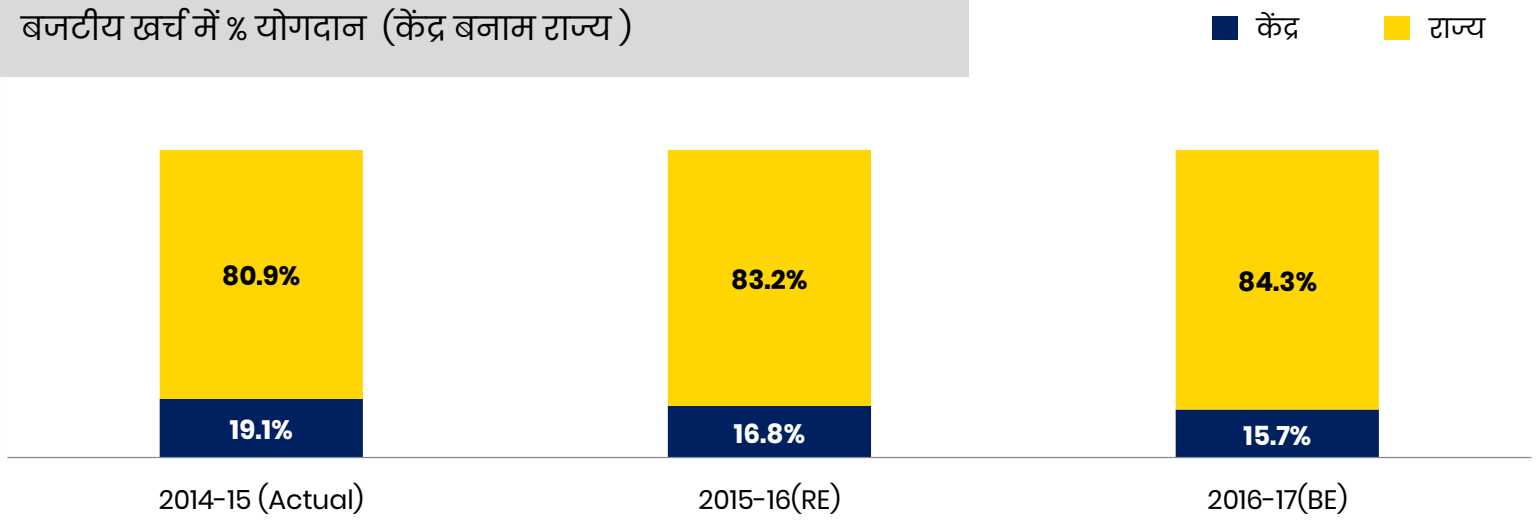

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source : Analysis of Budgeted Expenditure 2014-15 to 2016-17, MHRD 2018

2006 और 2016 के बीच जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर शिक्षा पर होने वाला खर्च बढ़ा

- जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर केंद्र की ओर से शिक्षा पर होने वाला खर्च एक समान ही रहा है।
- इसी अवधि में जीडीपी प्रतिशत के तौर पर शिक्षा पर होने वाले राज्यों के खर्च में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है।

जीडीपी के % के तौर पर शिक्षा पर होने वाला खर्च

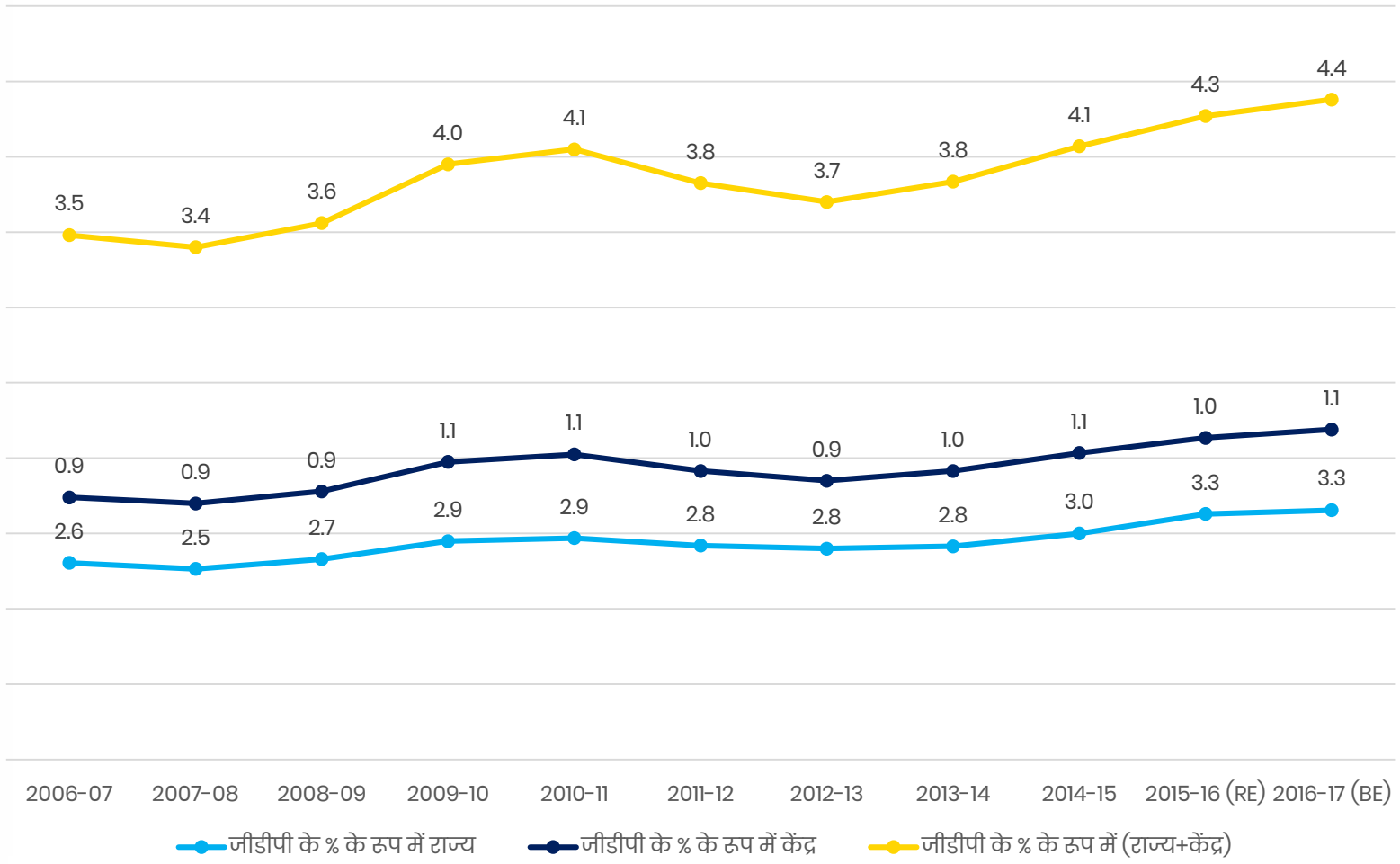

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source : Analysis of Budgeted Expenditure 2014-15 to 2016-17, MHRD 2018

बड़े राज्यों में असम जीएसडीपी के % के तौर पर शिक्षा क्षेत्र पर सबसे ज्यादा खर्च करता है।

- बड़े राज्यों मेंअसम, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश में जीएसडीपी का 5% शिक्षा पर खर्च किया गया।
- छोटे राज्यो में मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड ऐसे राज्य हैं जहां जीएसडीपी के प्रतिशत के तौर पर सबसे ज्यादा शिक्षा पर खर्च किया गया।

कुल जीएसडीपी में शिक्षा बजट का %

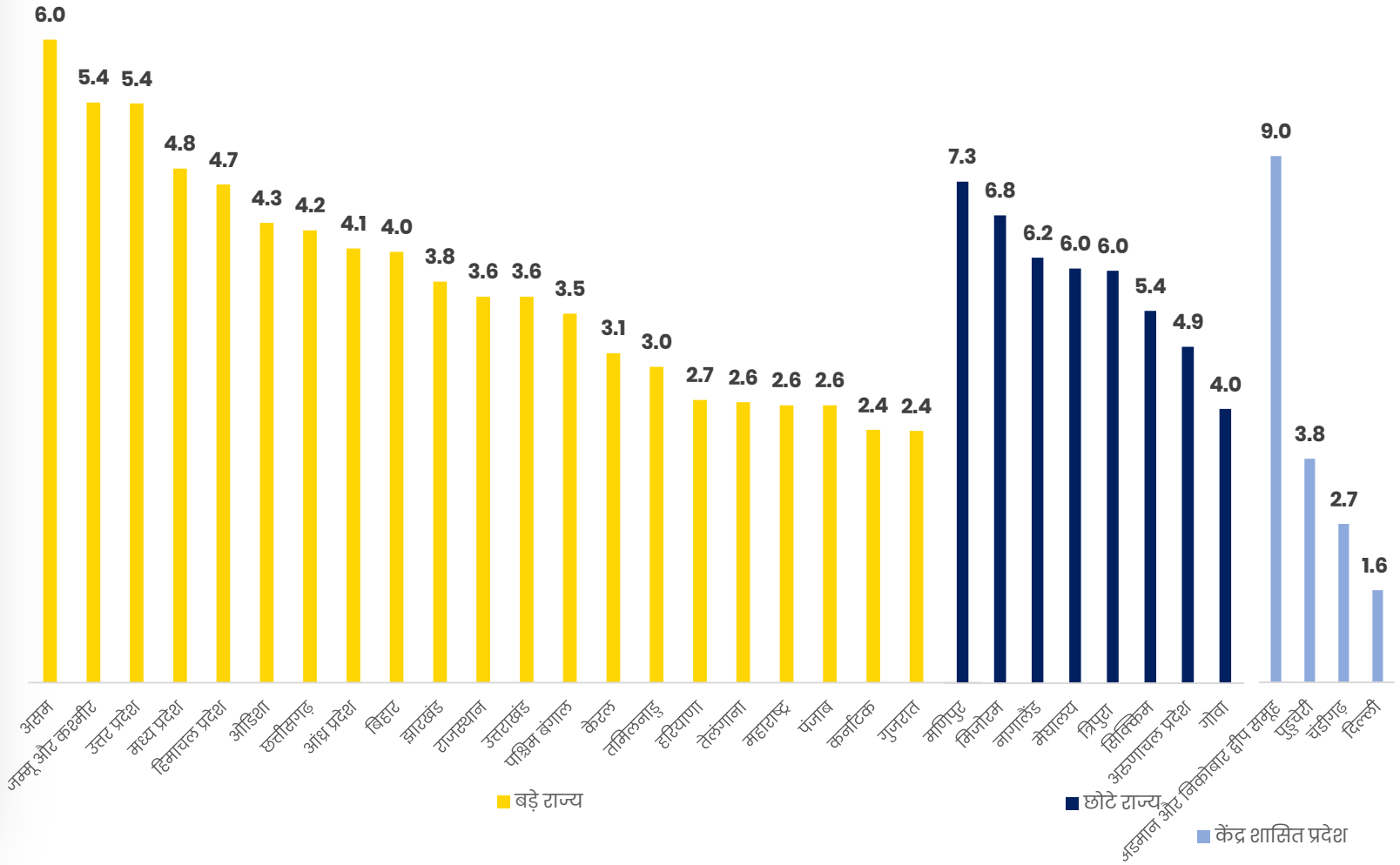

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

Source : Analysis of Budgeted Expenditure 2014-15 to 2016-17, MHRD 2018

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

नीतिगत विशिष्टताएं और पहल

पार्ट बी: नीतिगत विशिष्टताएं एवं पहल

भारतीय स्कूली शिक्षा के इस भाग में – डेटा, ट्रेन्ड्स और पॉलिसी रिपोर्ट्स के हवाले से , हाल के कुछ सालों में हुए महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों की समीक्षा, विषय पर साक्ष्य एवं समीक्षा की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शुरुआत करते हुए रिपोर्ट के इस भाग में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाओं और पहलुओं पर चर्चा की गई है।

जब रिपोर्ट के इस हिस्से पर काम चल रहा था, तब भारत में लॉकडाउन के 5 महीने बीत चुके थे। इसीलिए इस रिपोर्ट में कोविड 19 की वजह से स्कूल बंद होने का स्कूली शिक्षा पर प्रभाव, पढ़ाई में पड़ रही बाधा को दूर करने में एडटेक की भूमिका और इससे जुड़ी चुनौतियों और भारत के कुछ राज्यों द्वारा कोविड-19 के विषय में शिक्षा संबंधित प्रतिक्रिया पर भी चर्चा की गई है।

स्पष्टीकरण: यह रिपोर्ट पूर्णतया सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों के संबंध में की गई चर्चा सरकार का अधिकारिक मत हो और न ही इससे ऐसा कोई निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। यदि इसमें कोई गलती होती है है, तो यह हमारी ज़िम्मेदारी होगी।

नीतिगत विशिष्टताएं और पहल : एक झलक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं अन्य सुधार

भारत में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बीते 1 वर्ष में हुए प्रमुख नीतिगत सुधारों का विवरण

शिक्षा क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

बीते एक वर्ष के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की चर्चा

कोविड-19 के समय में शिक्षा

स्कूली शिक्षा पर कोविड-19 के प्रभाव और भारत की राज्य सरकारों की रणनीतिक प्रतिक्रिया पर चर्चा

विषय सूची

पॉलिसी विकास

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020- स्कूली शिक्षा
- स्कूली शिक्षा का गुणवत्ता इंडेक्स (SEQI)
- नो डिटेंशन पॉलिसी का निरस्तीकरण
- आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई को अनिवार्य करना
- प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट (PISA) में भारत की वापसी

स्कूली शिक्षा क्षेत्र में सरकार की पहल

- UDISE+
- ज्ञान के आदान प्रदान के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानि दीक्षा (DIKSHA) प्लेटफॉर्म
- नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट (NISHTHA)
- दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार
- उत्तर प्रदेश सरकार का 'मिशन प्रेरणा'

कोविड-19 के दौर में शिक्षा

1

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं अन्य सुधार

1

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)- स्कूली शिक्षा

01 बच्चों की शुरुआती देखरेख और शिक्षा (ECCE)

02 बुनियादी साक्षरता और गणना (FLN)

03 ड्रॉपआउट की दर कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करना

04 स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षा : सीखने की प्रक्रिया सर्वांगीण , संपूर्ण , मज़ेदार और दिलचस्प होनी चाहिए

05 शिक्षक

06 एक समान और समावेशी शिक्षा : सभी के लिए शिक्षा

07 स्कूल कॉम्प्लेक्स / क्लस्टर के ज़रिए प्रभावी तरीके से साधन जुटाने और संचालन में मदद

08 स्कूली शिक्षा का प्रमाणन और मानक स्तर तय करना

बच्चों की शुरुआती देखरेख और शिक्षा (ECCE)

"बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शुरुआती विकास, देखभाल और शिक्षा की व्यापक व्यवस्था जल्द से जल्द या 2030 तक किसी भी हाल में कर दी जानी चाहिए। ताकि पहली कक्षा में जाने वाले बच्चे स्कूल के लिए तैयार हों।"

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति , 2020

ECCE इतना महत्वपूर्ण क्यों है ?

- कई रिसर्च में यह बात सामने आयी है कि बच्चे के जीवन के पहले कुछ साल उसके भविष्य के विकास के लिए नींव का काम करते हैं।
- न्यूरोसाइंस से जुड़ी रिसर्च में इस बात के पुख्ता सबूत मिलते हैं कि जीवन के शुरुआती सालों में दिमाग काफी तेज़ी से विकसित होता है।
- 6 साल की उम्र तक बच्चे का दिमाग 90% तक विकसित हो चुका होता है। (Karoly et al., 1998)
- इसीलिए अगर शुरुआत से ही छोटे बच्चों को सही देखभाल दी जाए तो इसके कइयों फायदे मिल सकते हैं। (Ludwig & Miller, 2007)
- CECED और ASER ने 5 साल की लंबी अवधि में 13000 बच्चों का अध्ययन किया। इस अध्ययन में ये देखा गया कि ECCE के कारण गणित और भाषा में बच्चों के औसत टेस्ट स्कोर में काफी सुधार आया। (Kaul et al., 2014)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP),2020 की महत्वपूर्ण बातें

- अलग-अलग चरणों में देश के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों को वरीयता देते हुए उच्च गुणवत्ता वाले ECCE की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करना
- NCERT द्वारा 8 साल तक के बच्चों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण का खाका विकसित किया जाएगा।
- इन 4 तरीकों अलग-अलग साधनों के जरिए बच्चों को शुरुआती सलों में शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सकती है :
  - स्वतंत्र रूप से संचालित आंगवाड़ी केंद्र
  - प्राथमिक स्कूलों के साथ स्थित आंगनवाड़ी केंद्र
  - प्रथमिक स्कूलों के साथ स्थित पूर्व-प्राथमिक स्कूल
  - स्वतंत्र रूप से संचालित पूर्व प्राथमिक स्कूल
- उच्च गुणवत्ता और क्षमता वाले ECCE टीचरों का शुरुआती काडर तैयार करने के लिए टीचरों को ही प्रशिक्षित किया जाएगा।

सीमित ECCE → **स्कूल और कक्षा के लिए तैयारी में कमी** → **FLN की प्राप्ति में असफलता** → **क्लास में पिछड़ना और ड्रॉपआउट होना**

बचपन की शुरुआती शिक्षा के बड़े फायदे ...

"कौशल निर्माण एक गतिशील प्रक्रिया है जो कई तत्वों के साथ मिलकर काम करती है। कौशल से कौशल बनता है। शुरुआती निवेश, भविष्य में निवेश को बढ़ावा देता है।"

– जेम्स हेकमन, नोबेल पुरस्कार विजेता, अर्थशास्त्र

- जेम्स हेकमैन ने दिखाया है कि बाद के सालों और शिक्षा पर किए गए निवेश के मुकाबले बचपन के शुरुआती चरणों में किया गया निवेश बेहतर नतीजे दे सकता है। हालांकि हाल के वर्षों में की गई रिसर्च बताती है कि बाद के चरणों में किए गए प्रयास भी फायदेमंद हो सकते हैं। (Rea & Burton, 2020)
- 3 भारतीय राज्यों में 13 हजार बच्चों पर 5 साल तक किया गया लंबा अध्ययन यह दिखाता है कि गुणवत्तापरक ECCE विद्यार्थियों के गणित और भाषा के औसत अंकों में काफी सुधार देखने को मिला। (Kaul et al, 2014)
- वर्ष 1973 में जमैका के किंगस्टन में ECCE प्रोग्राम को अमल में लाया गया। साक्ष्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस प्रोग्राम से ज्ञान, सामाजिक, शैक्षणिक और मानसिक स्वास्थ्य और वेतन बढोत्तरी समेत बहुआयामी लाभ देखने को मिले। (Walker et al., 2011; Gertler et al., 2014)
- कोलंबिया में ECCE को औपचारिक तौर पर अपनाकर ट्रांजीशन ग्रेड (5 साल के बच्चों के लिए ग्रेड-0) सभी बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। ECCE प्रेशिडेंशियल प्रायोरिटी बनाकर एक व्यापक ECCE नीति – जीरो से हमेशा के लिए अपनाई गई। (OECD, 2016)

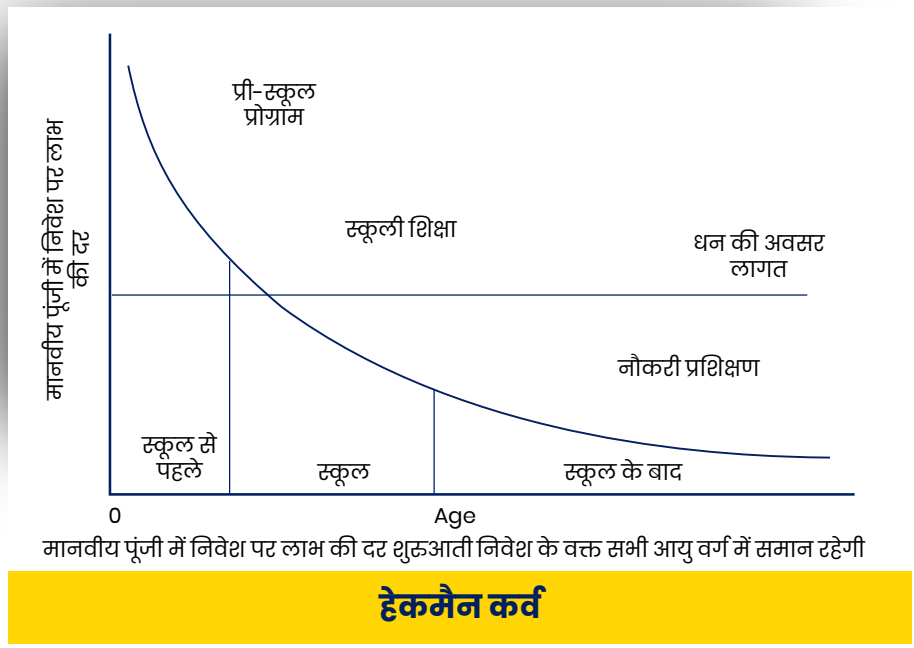

मानवीय पूंजी में निवेश पर लाभ की दर शुरुआती निवेश के वक्त सभी आयु वर्ग में समान रहेगी

हेकमैन कर्व

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

बुनियादी साक्षरता और गणना (FLN)

"विभिन्न सरकारी और गैर- सरकारी सर्वे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि फिलहाल हम पढ़ाई के संकट से जूझ रहे हैं। प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 5 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों में से एक बड़ा वर्ग बुनियादी साक्षरता और गणना नहीं कर पाता।"

– राष्ट्रीय शिक्षा नीति , 2020

FLN यानि तीसरी कक्षा तक बच्चों में उस क्षमता का विकास जिसके तहत वे जो पढ़ें उसका मतलब समझें और बुनियादी गणना भी कर लें।

भारत में FLN की स्थिति

तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 70% से ज्यादा बच्चे साधारण गणना नहीं कर पाते और 50% बच्चों को वाचन (बोलकर पढ़ना) नहीं आता।

50.8 **100**

भारत के ग्रामीण स्कूलों में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले केवल 50.8 **%** बच्चे, पहली कक्षा की किताब पढ़ पाते हैं।

30.6 **100**

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलो में तीसरी कक्षा के केवल 30.6**%** बच्चे, 2 अंकों का घटाना कर पाते हैं ।

Source: Annual status of education report (ASER) 2018

बुनियादी साक्षरता और गणना (FLN)

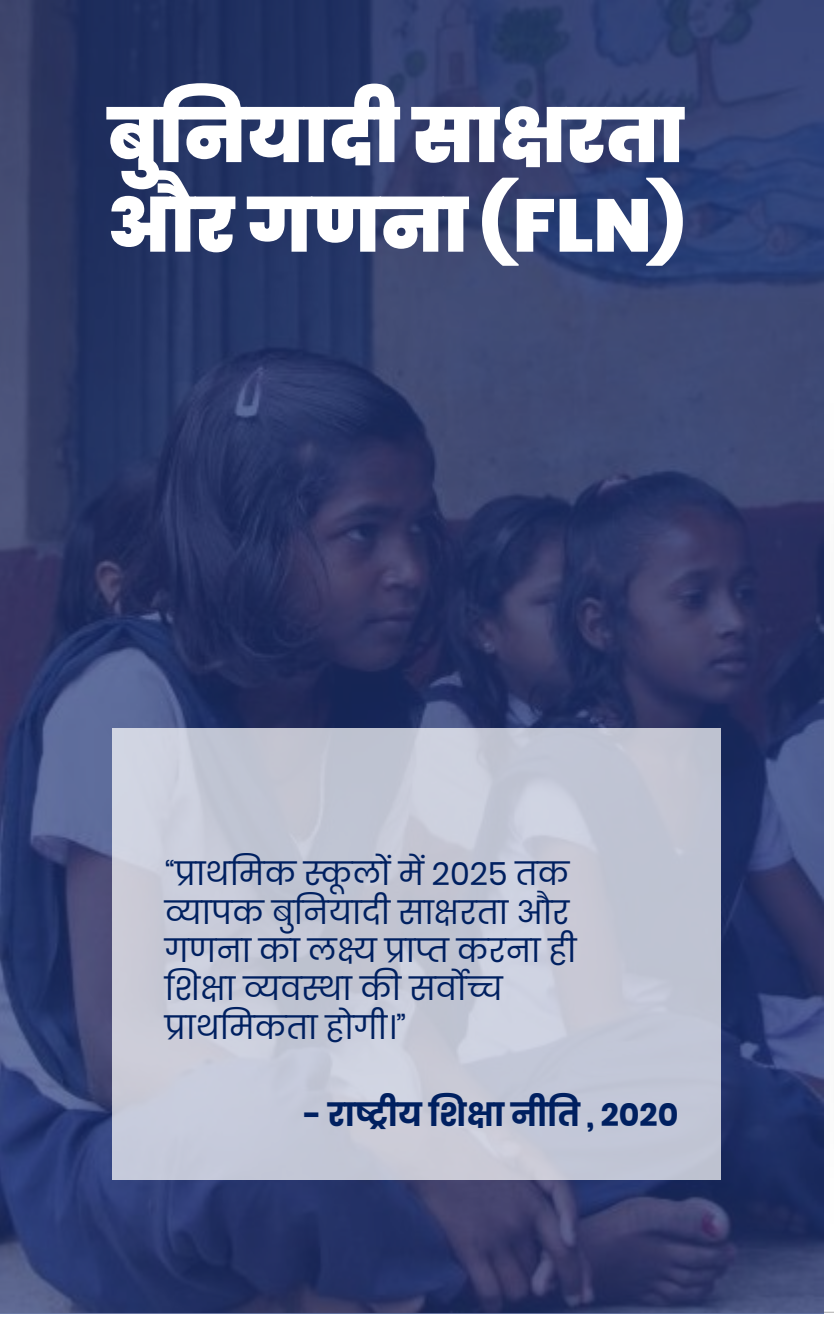

"प्राथमिक स्कूलों में 2025 तक व्यापक बुनियादी साक्षरता और गणना का लक्ष्य प्राप्त करना ही शिक्षा व्यवस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।"

– राष्ट्रीय शिक्षा नीति , 2020

FLN इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

- बुनियादी पढ़ाई, भविष्य की शिक्षा का आधार बनती है।
- तीसरी कक्षा तक जो बच्चे बुनियादी साक्षरता और गणना कौशल विकसित नहीं कर पाते, उनके लिए आगे की कक्षाओं का पाठ्यक्रम काफी मुश्किल होता जाता है और ऐसे बच्चे पढ़ाई में पिछड़ने लगते हैं। (NEP, 2020)
- FLN कौशल की कमी के चलते ऐसे बच्चों का स्कूल व्यवस्था से बाहर होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। (Nakajima & Otsuka, 2018)

NEP के मुख्य बिंदु , 2020

- शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक राष्ट्रीय FLN मिशन की स्थापना की जाएगी। और सभी राज्य सरकारें/ केंद्र शासित प्रदेश सभी प्राथमिक स्कूलों में व्यापक रूप से FLN के लक्ष्य प्राप्त करने संबंधी योजना को लागू करेंगे।
- जिन जगहों पर विद्यार्थी- शिक्षक अनुपात ज्यादा है या असाक्षरता की दर ज्यादा है, वहां विशेष ध्यान देते हुए टीचरों के खाली पदों को तुरंत भरा जाए।
- प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूलों के पाठ्यक्रम में FLN पर विशेष ध्यान देते हुए लगातार बच्चों का असेसमेंट किया जाए ताकि हर बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दिया जा सके।

NEP, 2020 में FLN में सुधार संबंधी अन्य कदम

- पहली क्लास के सभी बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए NCERT और SCERT द्वारा 3 महीने का आंतरिक प्ले आधारित स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल विकसित किया जाएगा।
- दीक्षा (DIKSHA) प्लेटफॉर्म पर FLN आधारित उच्च गुणवत्तापूर्ण संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा।
- राज्यों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे पढ़ाई के लिए उपयुक्त माहौल बनाने की दिशा में नवीनतम मॉडल विकसित करें और पीयर ट्यूटरिंग सहित स्वयंसेवी गतिविधियों को बढ़ावा दें।
- पढ़ाई के लिए सही पोषण के साथ बच्चों का शारीरीक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। इस लक्ष्य को स्कूलों में स्वस्थ्य भोजन के प्रावधान के साथ सही प्रशिक्षण प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता, काउंसेलर्स और सामुदायिक भागीदारी के ज़रिए प्राप्त किया जा सकता है।

भारत में FLN का आंकलन

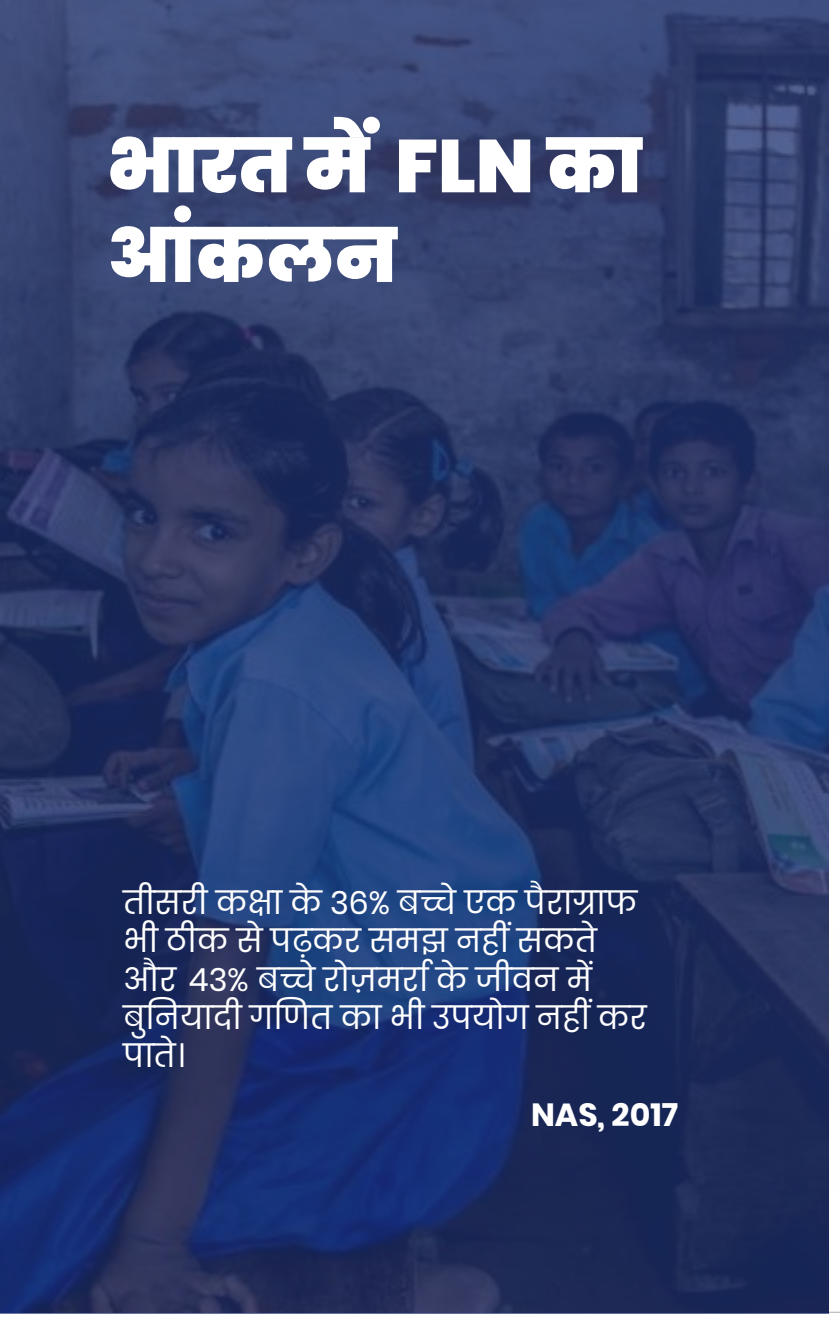

तीसरी कक्षा के 36% बच्चे एक पैराग्राफ भी ठीक से पढ़कर समझ नहीं सकते और 43% बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में बुनियादी गणित का भी उपयोग नहीं कर पाते।

NAS, 2017

FLN के घटक

बुनियादी साक्षरता : क्या तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे जो पढ़ते हैं वो समझ भी पाते हैं जैसे -

- अक्षर पहचानना
- शुरुआती या आखिरी शब्दों की पहचान
- ऐसे शब्द जो ध्वनि में प्रयुक्त होते हों
- जाने-पहचाने शब्द पढ़ना
- समझकर सुनना
- एक लय में समझकर पढ़ना

बुनियादी गणना : क्या तीसरी कक्षा में पढ़नेवाले बच्चे गणित में साधारण गणना कर पाते हैं। जैसे -

- अंकों की पहचान
- अंकों के बीच फर्क कर पाना
- खोए हुए अंक ढूंढना
- जोड़ना
- घटाना
- प्रश्न हल करना

भारत में FLN का आंकलन कैसे किया जाता है ?

- ऐनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER)और नेशनल अचीवमेंट सर्वे (NAS) जैसे दो नेशनल लर्निंग असेसमेंट के ज़रिए जो एक निश्चित अवधि पर होते हैं।
- NAS में शहरी और ग्रामीण दोंनों क्षेत्रों का समावेश होता है जबकि ASER के तहत केवल ग्रामीण इलाके आते हैं।
- इकट्ठा किए गए सैंपल और कॉन्टेन्ट असेसमेंट में अंतर के कारण ASER और NASके नतीजों की तुलना नहीं की जा सकती।

NAS और ASER : लर्निंग असेसमेंट सर्वे

मापदंड	नेशनल अचीवमेंट सर्वे (NAS)	ऐनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER)
विवरण	• 2001-02 में शुरुआत • 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में NCERT द्वारा संचालित	• 2005 में शुरुआत • भारत के 15,000 गांवों में प्रथम, जो कि एक अग्रणी स्वयं सेवी संस्था है, द्वारा संचालित
किनका आंकलन किया जाता है ?	• कक्षा 3, 5 और 8 • केवल सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में • ग्रामीण और शहरी इलाकों में	• 5-16 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चे (सरकारी, निजी, गैर-स्कूली) • केवल ग्रामीण जिलों में
क्या आंकलन किया जाता है?	कक्षा स्तरीय योग्यता : • कक्षा 3: भाषा और गणित • कक्षा 5 : भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन • कक्षा 8: भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान	• बुनियादी पठन और अंकगणित • पिछली कक्षा संबंधी योग्यताएं (पहली के विद्यार्थियों को छोड़ कर)
आवृत्ति	• पहले तीन साल में एक बार हर कक्षा का आंकलन किया जाता था। 2017 से सभी कक्षाओं का आंकलन एक साथ किया जा रहा है।	• वार्षिक
टेस्ट का प्रारूप और संचालन	• स्कूल आधारित पढ़ाई • अतिरिक्त लेखन कार्य के साथ MCQ प्रारूप • कलम और कागज़ वाली परीक्षा • SCERTs, SIEs, DIETs जैसी सरकारी एजेंसियों द्वारा समन्वयन	• घर पर आधारित पढ़ाई • हर बच्चे को आमने- सामने बिठाकर मौखिक परीक्षा • साथी संस्थाओं के 30000 स्वयंसेवकों द्वारा संचालन

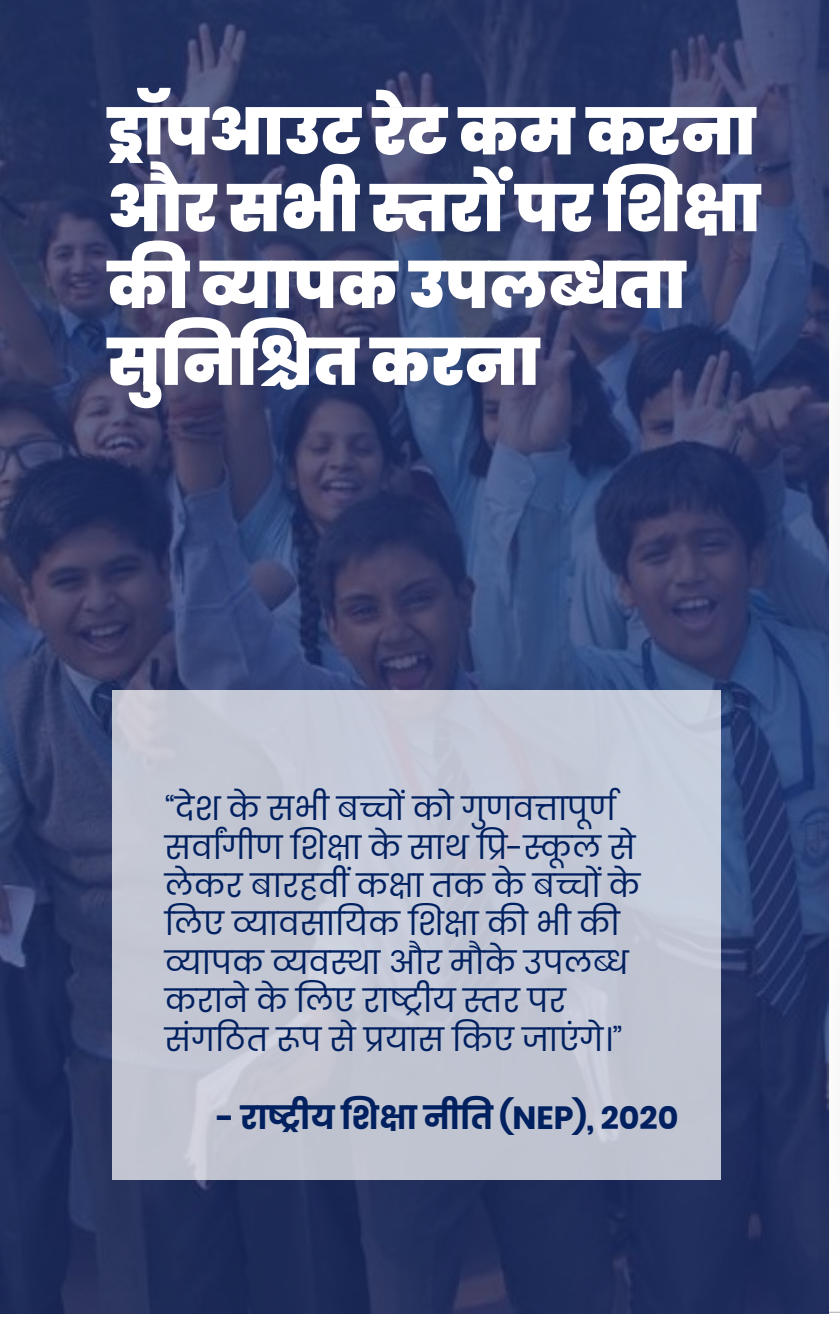

ड्रॉपआउट रेट कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करना

"देश के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण सर्वांगीण शिक्षा के साथ प्रि-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की भी की व्यापक व्यवस्था और मौके उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संगठित रूप से प्रयास किए जाएंगे।"

– राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020

ड्रॉपआउट दर बढ़ने के संभावित कारण

- ECCE और FLN में कमीका सीधा अर्थ यह है कि कई बच्चे लर्निंग कर्व में पिछड़ जाते हैं। और आगे चलकर वे स्कूल से ड्रॉपआउट हो जाते हैं। (NEP, 2020)
- माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की सीमित उपलब्धता (ibid)
- सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक समस्याएं-कम उम्र में शादी या बाल विवाह, किसी लिंग या जाति की मान्य भूमिका, बाल मजदूरी या बच्चों/नवयुवकों पर काम करने और पैसे कमाने का दबाव (Sajjad et al, 2012)
- अभिभावकों की विशिष्टता , खासकर उनकी साक्षरता (M., Sateesh & Sekher, T V., 2014)
- संसाधनों की कमी और सुरक्षा का अभाव (Bandhopadhyay, 2015)

NEP, 2020 के मुख्य बिंदु

- स्कूली व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे न सिर्फ स्कूल में दाखिला लें बल्कि स्कूल पढ़ने भी आएं
- विभिन्न कदमों के द्वारा भारत ने प्राथमिक स्कूलों में दाखिले की दर का व्यापक लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया है। 2016-17 में देश में कक्षा 1- 5 तक सकल दाखिला अनुपात (GER) **95.1%** रहा।(UDISE data)
- लेकिन इन बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने में काफी समस्याएं आ रही हैं। कक्षा 6-8 का GER **90.7% था। जबकि कक्षा** 9-10 और 11-12 के मामले में यह अनुपात घटकर महज़ 79.3% और 51.3% रह गया। ये आंकड़े साफ तौर पर ड्रॉपआउट की ओर इशारा करते हैं।

ड्रॉपआउट हुए बच्चों को वापस स्कूल कैसे लाया जाए और आगे बच्चों को ड्रॉपआउट होने से कैसे बचाया जाए?

NEP, 2020, में यह दो आधारभूत कदम उठाने की सलाह दी गई है :

- प्रभावी और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं ताकि सभी स्तरों पर बच्चों को सुरक्षित और दिलचस्प स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो सके। (पूर्व –प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक)
- स्कूलों में बच्चों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी बच्चों और उनकी पढ़ाई के स्तर की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी बच्चे स्कूल आएं और अगर कोई बच्चा पिछड़ रहा हो या इससे ड्रॉपआउट हो तो उसके प्रदर्शन को सुधारकर उसे दोबारा स्कूली व्यवस्था में लाया जा सके।

स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण : पढ़ाई समग्र, संपूर्ण , मज़ेदार और दिलचस्प होनी चाहिए

"स्कूली शिक्षा में पाठ्यक्रम और शिक्षण को पुनर्रूपित किया जाएगा। ताकि शिक्षा को बच्चों के विकास के अलग-अलग स्तर की ज़रूरतों के अनुरूप बनाया जा सके।"

– राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020

मौजूदा पाठ्यक्रम और शिक्षण की समस्याएं

- भारत में बच्चों में पढ़ाई का कौशल, उनकी किताब के लिहाज़ से दो कक्षा नीचे ही रहता है। (Bhattacharjea, Wadhwa, Banerji; 2011)
- शिक्षण की मौजूदा पद्धति रटंत विद्या पर आधारित है। (NEP, 2020)
- भारत में स्थानीयता से संबद्ध TLM की कमी है। खासतौर पर समाज के निचले तबके के लिए। (Kidwai et al, 2013)
- शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में मतलब बनाने और उन्नत सोच कौशल विकसित करने पर कम ध्यान दिया जाता है। (Menon, 2014)
- आंकलन का खाका सीखने और सुधार पर केंद्रित न होकर दंडात्मक है, जिसमें काफी कुछ दांव पर होता है। (NEP, 2020)

NEP, 2020 के मुख्य बिंदु

- मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को रटंत विद्या की संस्कृति से दूर ले जाकर वास्तविक समझ विकसित करना ही नए पाठ्यक्रम और शिक्षण का लक्ष्य होगा।
- हर विषय के तहत अनुभव आधारित पढ़ाई को ही मानक शिक्षण के तौर पर अपनाया जाएगा।
- बच्चों को विषय का चुनाव करने की व्यवस्था को और लचीली बनाया जाएगा विशेष रूप से माध्यमिक स्कूलों में।
- मातृभाषा / घर की भाषा ही पढ़ाई की भाषा होगी। कम से कम 5वीं कक्षा तक और जहां संभव हुआ वहां 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा में ही कराने को वरीयता दी जाएगी।
- सही समय आने पर बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) , डिज़ाइन थिंकिंग जैसे समसामयिक विषयों की भी जानकारी दी जाएगी।
- परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदलकर एक ऐसी व्यवस्था लागू की जाएगी जो ज्यादा नियमित,रचनात्मक, प्रतिस्पर्धा- आधारित और ऊंचे स्तर के कौशल को परखने वाली हो।

NEP, 2020 में इन समस्याओं को दूर करने संबंधी सुझाव

- स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षण की नए तरीके से पुनर्रचना की जाएगी (5+3+3+4)
- पाठ्यक्रम घटाना और महत्वपूर्ण कौशल को शामिल करना
- पाठ्यपुस्तकों को स्थानीय भाषा और परिवेश के अनुसार ढालना
- स्कूली शिक्षा के लिए नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2020 का खाका तैयार करना

पाठ्यक्रम में सुझाए गए सुधार पर सबूत

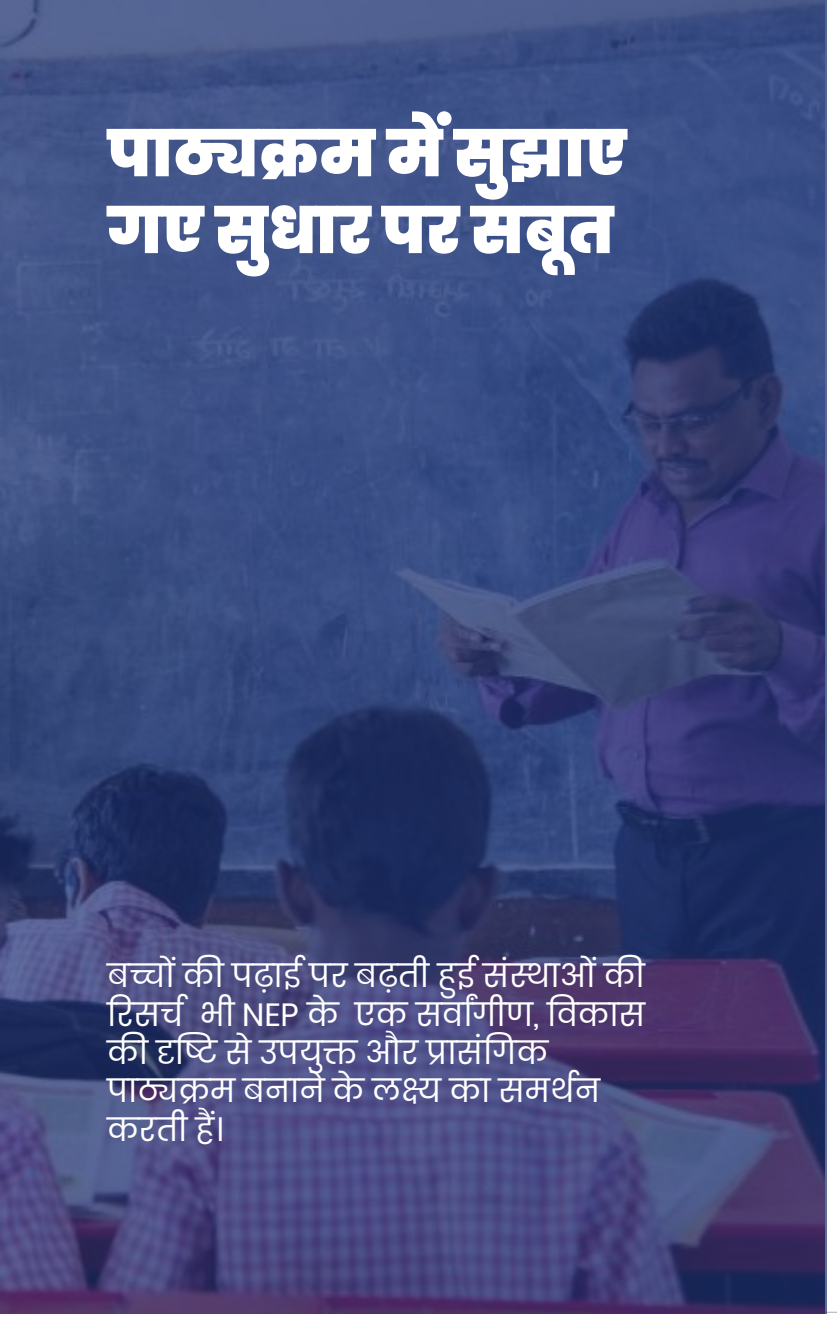

बच्चों की पढ़ाई पर बढ़ती हुई संस्थाओं की रिसर्च भी NEP के एक सर्वांगीण, विकास की दृष्टि से उपयुक्त और प्रासंगिक पाठ्यक्रम बनाने के लक्ष्य का समर्थन करती हैं।

रिसर्च के आधार पर पाठ्यक्रम सुधार के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश

बच्चों की किताबों और लर्निंग मटेरियल में स्थानीय प्रसंगों का उल्लेख	उचित सीख को बढ़ावा, मातृभाषा में पढ़ाई से बच्चों में मौलिक या उच्च स्तरीय चिंतन, विवेकबुद्धि और अभिव्यक्ति जैसे कौशल के विकास को बढ़ावा मिलता है। (UNICEF-LLF: Guidelines for Design and Implementation of Early Learning Programmes, 2019)
रचनात्मकता और परस्पर प्रभाव	परस्पर बातचीत या प्रभाव पर आधारित पढ़ाई , बच्चों की समझबूझ और सर्वांगीण विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। (Vygotsky, 1978)। इससे बच्चों को वह अनुभव, ज्ञान और कौशल मिलता है जिसका इस्तेमाल नए कॉन्सेप्ट्स (अवधारणाओं) को सीखने में किया जा सकता है।
विकास की दृष्टि से उपयुक्त शिक्षण	इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि पाठ्यक्रम को बच्चों की समझ के स्तर के लिहाज़ से बढ़ाया जाए। क्योंकि पाठ्यक्रम तीव्र गति से आगे बढ़ने पर बच्चे कुछ महत्वपूर्ण कौशल की अवधारणाएं नहीं सीख पाते और इससे उन्हें नुकसान होता है। (Menon et al., 2017)
उच्च स्तरीय चिंतन का कौशल विकसित करने का लक्ष्य	स्वेच्छापूर्ण कौशल , जहां बच्चे चीज़ों का मतलब समझकर उनका निष्कर्ष निकालते हैं, वह उन्हें सिलसिलेवार ढंग से अर्जित की गई कुशलता से कहीं आगे ले जाता है।, यह कौशल आगे चलकर उन्हें और ज्यादा सीखने और समझने में मदद करता है। (Levya et al., 2015)।
रचनात्मक आंकलन	रचनात्मक आंकलन के तहत नरंतर सीखने और सुधार पर केंद्रित समीक्षा और फीडबैक की एक प्रक्रिया विकसित की जाती है। साथ ही इससे शिक्षकों को कक्षा में बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक पढ़ाने का तरीका बदलने में भी मदद मिलती है। (Gove et al., 2016)
मातृभाषा बने शिक्षण की भाषा	बच्चों को स्कूल के पहले कुछ सालों में उनकी मातृभाषा में पढ़ाना, पढ़ाई में उनके प्रदर्शन को सुधारने और बेहतर बनाने में काफी कारगर साबित होता है। (Thomas & Collier, 2002)

शिक्षक

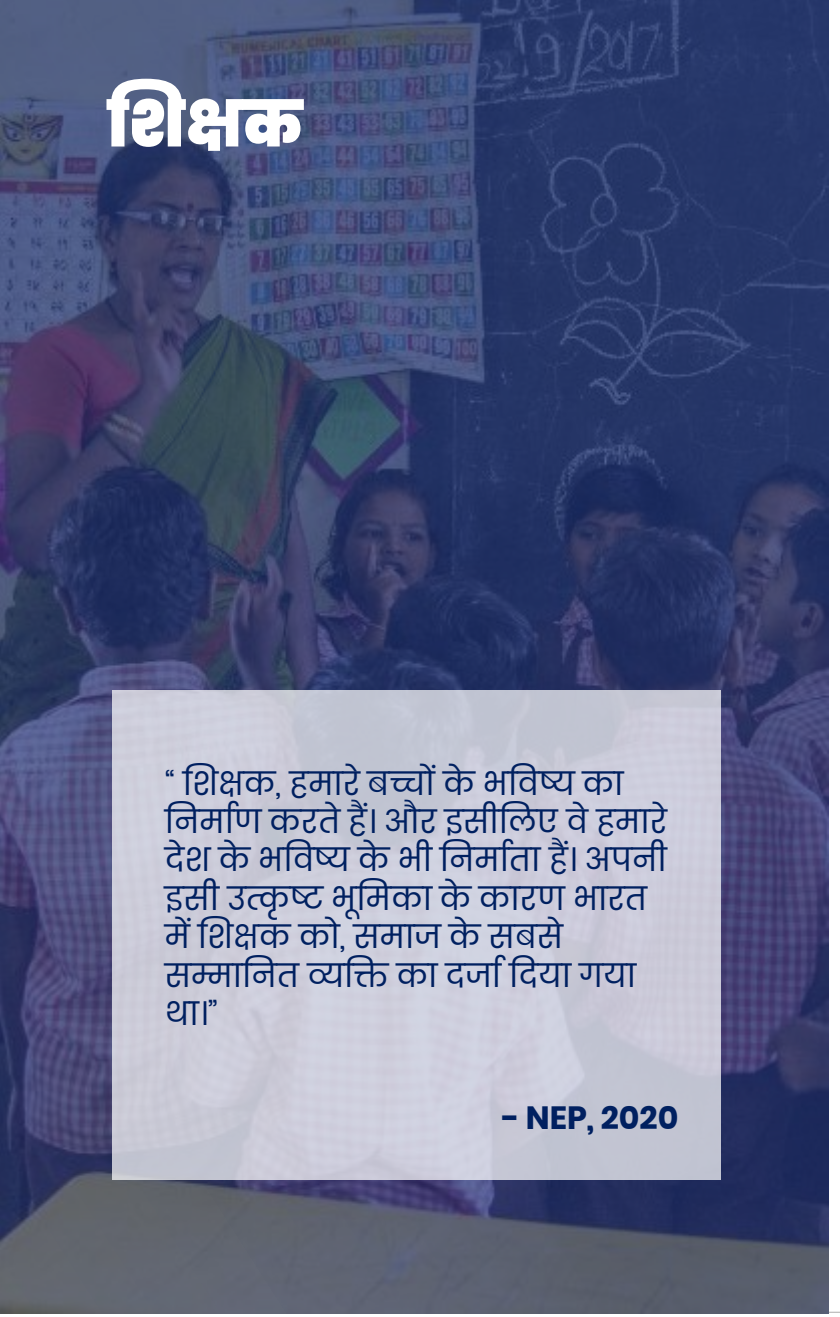

"शिक्षक, हमारे बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसीलिए वे हमारे देश के भविष्य के भी निर्माता हैं। अपनी इसी उत्कृष्ट भूमिका के कारण भारत में शिक्षक को, समाज के सबसे सम्मानित व्यक्ति का दर्जा दिया गया था।"

– NEP, 2020

शिक्षकों और उनके शिक्षण को प्रभावित करने वाले कुछ मुद्दे

- शिक्षकों की शिक्षा – पाठ्यक्रम और कार्यक्रम के ढांचे का अकाल (Justice Verma Commission Report, 2012; Young Lives, 2013)
- स्कूलों में ज़रूरत से बेहद कम शिक्षकों की नियुक्ति (Young Lives, 2013)
- शिक्षकों का ज्यादातर समय गैर-शैक्षणिक कामों में खर्च होता है (Puppala, 2018)
- शिक्षकों को पेशेवर उन्नति के सीमित मौके मिलते हैं। साथ ही उनके करीयर में क्रमिक प्रगति का आधार भी औपचारिक रूप से योग्यता आधारित नहीं होता। (NEP, 2020)

NEP, 2020 के मुख्य बिंदु

- भारत में शिक्षकों की गुणवत्ता और प्रेरणा कभी उस मानक स्तर तक नहीं पहुंच पाती, जहां कि उसे होना चाहिए। इसके पीछे प्रशिक्षण की गुणवत्ता, भर्ती, तैनाती, सेवा की शर्तें और सशक्तिकरण समेत कई अन्य कारण हैं।
- शिक्षकों के चयन से लेकर उनके करीयर मैनेजमेंट तक शिक्षकों पर असर डालने वाले सभी कारकों में बदलाव का प्रस्ताव
- NCTE द्वारा 2021 तक शिक्षकों के शिक्षण की दिशा तय करने के लिए एक समग्र राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का खाका तैयार किया जाएगा।
- स्कूली शिक्षा में कुछ खास क्षेत्रों जैसे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की ज़रूरत तुरंत पूरी करने पर ज़ोर

शिक्षकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को कैसे हल किया जाए?

NEP, 2020, इन संरचनाओं में पूर्ण बदलाव की बात कहती है :

- शिक्षकों की शिक्षा, भर्ती और तैनाती
- स्कूल का माहौल और संस्कृति, पेशवर विकास और करीयर मैनेजमेंट

NEP, 2020 में प्रस्तावित कुछ शिक्षक सुधार

भर्ती और नियुक्ति

- 4 वर्षीय बी.एड कार्यक्रम के लिए योग्यता आधारित छात्रवृत्ति
- ग्रामीण इलाकों में स्थानीय नियुक्तियों में बी. एड की पढ़ाई पूरी करने वाले स्थानीय विद्यार्थियों को वरीयता दी जाए
- शिक्षकों का अत्याधिक ट्रांसफर बंद हो
- शिक्षक योग्यता परीक्षा (TETs) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के शिक्षकों पर लागू हो
- स्कूलों और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में विभिन्न विषयों के लिए 'मास्टर इन्स्ट्रक्टर्स' (विशिष्ट प्रशिक्षकों) की नियुक्ति
- शिक्षको की आवश्यकता का तकनीक आधारित पूर्वानुमान

परिवेश एवं संस्कृति

- स्कूलों में पर्याप्त और सुरक्षित रूप से मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता
- पढ़ाने के सबसे प्रभावी तरीके का चुनाव करने के मामले में शिक्षकों को ज्यादा स्वतंत्रता मिले
- शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले गैर-शैक्षणिक कार्यों में कमी लाकर उन्हें तर्कसंगत बनाया जाए।
- स्कूल में ध्यान रखने वाला और समावेशी संस्कृति का निर्माण करने की ज़िम्मेदारी में प्रिंसिपल और शिक्षकों की बड़ी भूमिका होगी।
- बच्चों की पढ़ाई के नतीजों को सुधारने के लिए नए तरीके अपनाने वाले टीचरों को सम्मानित किया जाएगा।

निरंतर पेशेवर विकास (CPD)

- टीचिंग के क्षेत्र में नवीनतम अविष्कारों और विकसित तरीकों को सीखने के लिए निरंतर मौके दिए जाएं।
- शिक्षकों को पढ़ी के नए तरीके और आइडिया दूसरों के साथ बांटने के लिए प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा।
- शिक्षकों की रुचि के आधार पर हर वर्ष उन्हें कम से कम 50 घंटे के निरंतर पेशेवर विकास यानि CPD का मौका मिलेगा।
- CPD में FLN, रचनात्मक और अनुकूल आंकलन, प्रतिस्पर्धात्मक पढ़ाई से संबंधित शिक्षण समेत शिक्षण के नवीनतम तरीके शामिल होगे।
- स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल कॉम्प्लेक्स का नेतृत्व करने वालों के लिए भी ऐसी ही वर्कशॉप और ऑनलाइन डेवलपमेंट के मौके उपलब्ध होंगे। ताकि वे भी अपने नेतृत्व और प्रबंधन कौशल को बेहतर बना सकें।

करियर मैनेजमेंट और उन्नति

- अवधि, पदोन्नति और वेतन की एक योग्यता आधारित संरचना तैयार की जाएगी जिससे बेहतरीन शिक्षकों को सम्मानित और प्रोत्साहित किया जा सके।
- राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा एक अनुकूल और कठिन प्रदर्शन आंकलन की व्यवस्था विकसितकी जाएगी।
- सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षकों को एक स्कूल के चरण में ही करीयर में उनन्ति का मौका मिले।
- बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ऐसे शिक्षक जिनमें अच्छी नेतृत्व क्षमता और प्रबंधन कौशल हो, उन्हें कुछ अंतराल पर प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे आगे चलकर स्कूल और अन्य जगहों पर शिक्षा से संबंधित प्रमुख पद ग्रहण कर सकें।

शिक्षक गुणवत्ता और विद्यार्थियों का प्रदर्शन; साक्ष्य, जो NEP 2020 में प्रस्तावित टीचर सुधारों का समर्थन करते हैं।

एक अच्छे शिक्षक की परिभाषा क्या है ?

"…. साधारण शब्दों में एक अच्छा शिक्षक वहीं जिसके विद्यार्थी निरंतर रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। (विद्यार्थियों के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों जैसे परिवारिक प्रभाव, पूर्व शिक्षक जैसे कारकों को नियंत्रित करने के बाद)"

(Hanushek and Rivkin, 2012)

शिक्षक की गुणवत्ता अतिमहत्वपूर्ण है और इसके कई घटक होते हैं।

- स्कूलों में शिक्षक की गुणवत्ता, विद्यार्थियों के भविष्य पर गहरा प्रभाव डालती है और इसके नतीजे उनके वस्क जीवन में सामने आते हैं- जैसे कॉलेज अटेंडेंस, जिस कॉलेज से वे पढ़ते हैं उसकी गुणवत्ता और तनख्वाह (Chetty, Friedman & Rockoff, 2014)
- भारत में, टीचरों को सेवा में आने से पहले मिली टीचर ट्रेनिंग और उनकी स्नातकोत्तर स्तर की योग्यता और विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बीच काफी गहरा संबंध देखने को मिला। (Kingdon, 2006)
- ग्लिउ एट अल ने (Glewwe et al. (2011) विकासशील देशों पर की गई एक मेटा समीक्षा में पाया कि सेवा के दौरान की गई टीचर ट्रेनिंग और बच्चों के प्रदर्शन में सकारात्मक लेकिन कमज़ोर संबंध है।
- ग्लिउ एट अल ने (Glewwe et al। (2011) विकासशील देशों के परिपेक्ष्य में पढ़ाने की अवधि का बच्चों के प्रदर्शन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे इस तर्क को बल मिलता है कि भारत में शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों की अवधि को तर्कसंगत बनाए जाने की ज़रूरत है।
- स्कूली परिपेक्ष्य – जिसमें स्कूल का नेतृत्व और गवर्नेंस भी शामिल है – का टीचरों की क्लासरूम गतिविधियों पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए आगे चलकर इसका प्रभाव बच्चों के प्रदर्शन पर भी पड़ता है।
- शिक्षा प्रबंधन सूचना व्यवस्था (EMIS) से मिले डेटा का उपयोग करके शिक्षकों की और भी प्रभावी ढंग से तैनाती की जा सकती है। (Barrett et al. 2007)
- शिक्षक समूह में पढ़नेवालों की झलक मिले, यह सुनिष्चित करना बेहद ज़रूरी है। लॉयड (2009) ने पाया कि स्कूलों में पर्याप्त संख्या में महिला शिक्षकों की नियुक्ति ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के लिए बुनियादी शिक्षा उपलब्ध करवाने की दिशा में एक प्रभावी रणनीति साबित हो सकती है।
- ऐसा देखा गया है कि पढ़नेवालों के ही समान लिंग और समान पृष्ठभूमि का शिक्षक होने से बच्चों के प्रदर्शन पर बढ़िया असर पड़ता है। (Aslam and Kingdon 2011)

समान एवं समावेशी शिक्षा : सभी के लिए शिक्षा

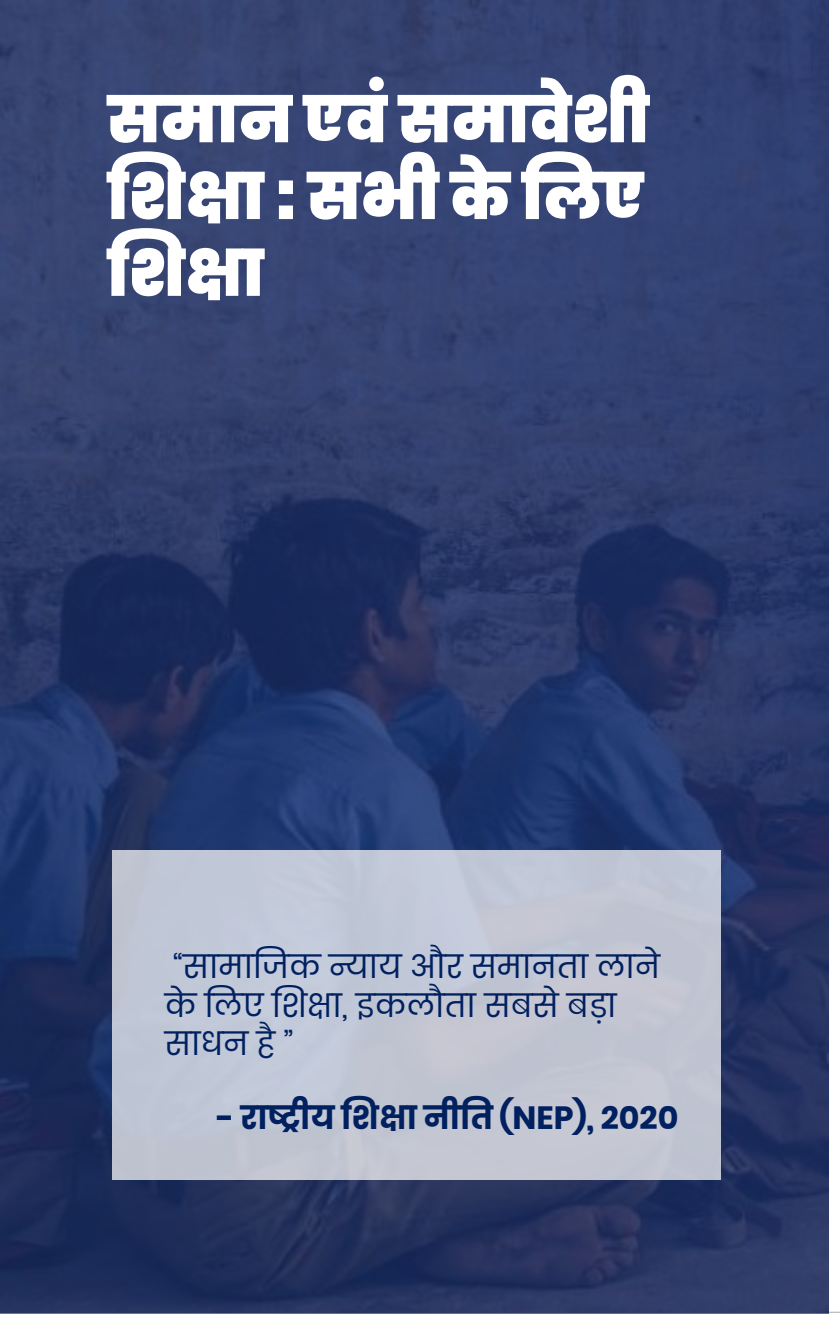

"सामाजिक न्याय और समानता लाने के लिए शिक्षा, इकलौता सबसे बड़ा साधन है "

– राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020

शैक्षणिक बहिष्कार और भेदभाव के कारण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020, में ऐसे कई घटकों की पहचान की गई है, जो शैक्षिणिक बहिष्कार और भेदभाव का कारण हैं।

- पिछड़े तबकों (URGs) के बच्चों के लिए अक्सर अच्छे स्कूल उपलब्ध नहीं होते।
- संसाधनों की कमी के कारण, उपलब्धता के बावजूद गरीब परिवार अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते।
- भेदभावपूर्ण व्यवहार के पीछे सामाजिक सोच भी काफी हद तक जिम्मेदार है।
- अच्छे स्कूलों की कमी, गरीबी, सामाजिक रीति-रिवाज और संस्कृति और भाषा जैसे कारण भी पिछड़े तबकों के बच्चों के स्कूल में दाखिले और आगे की पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव डालते हैं।
- आदिवासी या जनजातीय समूहों के बच्चे अक्सर स्कूली शिक्षा से सरोकार नहीं रख पाते क्योंकि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था उनकी संस्कृति और जीवन से कोई मेल नहीं रखती।

NEP, 2020 के मुख्य बिंदु

- बीते तीन दशकों में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक और सामाजिक दूरी को कम करने में अच्छी सफलता मिली है।
- लेकिन माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर अब भीकाफी असमनातएं हैं। यब बात उन तबकों पर ज्यादा लागू होती है जो शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से सही प्रतिनिधित्व हासिल नहीं कर पाए हैं।
- कम प्रतिनिधित्व वले तबकों के बच्चों के दाखिले की दर काफी ज्यादा है। और तबकों के लिहाज़ से लड़कियों के दाखिले की दर तो और भी कम है।
- केंद्र सरकार की ओर से एक लैंगिक समावेशी फंड की स्थापना की जाएगी। ताकि देश में लड़कियों और ट्रांसजेंडर्स को भी समान रूप से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल सके।
- ECCE और स्कूली व्यवस्था में दिव्यांग बच्चों को शामिल कर उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने को उच्च वरीयता दी जाएगी।

स्कूली शिक्षा को पूरी तरह समान एवं समावेशी कैसे बनाया जाए ?

NEP 2020 की कुछ यथार्थवादी प्रस्तावनाएं :

- नीतियों, योजनाओं, और प्रयासों को शैक्षणिक रूप से पिछड़े तबकों और हर तबके में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने पर लक्षित होना चाहिए।
- देशभर के पिछड़े इलाकों में स्पेशल एजुकेशन ज़ोन (SEZs) स्थापित किए जाएंगे। इन इलाकों की पहचान सामाजिक विकास और सामाजिक- आर्थिक संकेतों के आधार पर की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकारों से अतिरिक्त संसाधन लेकर ऊपर दी गई परियोजनाओं को इन SEZs में लागू किया जाएगा।

भारत में शिक्षा क्षेत्र में कम प्रतिनिधित्व रखने वाले वर्ग (URGs)

- पहली कक्षा से 12 कक्षा तक हुए सभी दाखिलों में स्थाई रूप से गिरावट देखने को मिलती है लेकिन **URGs** के मामले में यह गिरावट कहीं ज्यादा होती है।

- U-DISE 2016–17 के आंकड़ों के मुताबिक प्राइमरी कक्षाओं में स्कूल से ड्रॉपआउट होने वाले सभी बच्चों में से 19.6% बच्चे अनुसूचित जाति के होते हैं। हालांकि उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर यह आंकड़ा घटकर 17.3% हो जाता है। लेकिन दाखिले में कमी का यह स्तर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के मामले में और भी गंभीर होकर (10.6% से 6.8%), तक आ जाता है। मुस्लिम विद्यार्थियों के मामले में यह आंकड़ा (15% से 7.9%), और दिव्यांग बच्चों के मामले में यह दर (1.1% से 0.25%), है। वहीं इन सभी वर्गों में लड़कियों की ड्रॉपआउट दर और भी ज्यादा है। तो वहीं उच्च शिक्षा के मामले में इन वर्गों से आनेवाले बच्चों के दाखिले की दर में ज़बरदस्त गिरवाट देखने को मिलती है।

लैंगिक पहचान	महिलाएं	ट्रांसजेन्डर व्यक्ति			
सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछडे समुदाय (OBC)	मुसलमान	प्रवासी समुदाय
सामाजिक-आर्थिक स्थितियां	शहरी गरीब				
विशेष ज़रूरतें	पढ़ाई में असमर्थता	शारीरिक असमर्थता			

(कुछ) वंचित वर्गों में शैक्षिक असमानता को दूर करने के लिए उठाए गए साक्ष्य आधारित कदम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस रिसर्च पर विचार करने को कहा गया है जो पक्के तौर पर यह बता सके कि किसी खास वंचित वर्ग के लिए कौन सा उपाय ज्यादा प्रभावी रहेगा। उदाहरण के लिए:

- स्कूल जाने के लिए साइकिल देने के साथ साथ साइकलिंग और पैदल चलने वाले ग्रुप्स का संगठन बनाना, छात्राओं की स्कूल में भागीदारी बढ़ाने का काफी कारगर उपाय साबित हुआ है। यह तरीका छोटी दूरी के स्कूलों के मामले में भी काफी असरदार रहा है। क्योंकि इससे छात्राओं में सुरक्षा और अभिभावकों में निश्चिंतता का भाव आता है। (Muralidharan & Prakash, 2017)

- विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए समकक्ष शिक्षण, ओपन स्कूलिंग और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाना, उनके लिए काफी प्रभावी हो सकता है। (Mahapatra, 2016)

- जिन स्कूलों में बच्चों के लिए बचपन में अच्छी देखभाल और शिक्षा की सुविधा होती है, उनमें पढ़ने वाले सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों को काफी लाभ मिलता है। (Heckman, 2012)

महिलाएं विशेष रूप से वंचित रहती हैं

- NEP खास तौर से इस बात की ओर इंगित करती है कि सभी पिछड़े या वंचित वर्गों में सबसे ज्यादा वंचित महिलाएं ही होती हैं। और अन्य सभी URGs में इनकी संख्या लगभग आधी होती है।
- URGs के भीतर भी महिलाएं अत्याधिक वंचित होती हैं और उन्हें सबसे ज्यादा असमानता झेलनी पड़ती है।
- NEP इस बात को स्वीकार करती है कि समाज और सामाजिक रीति रिवाजों को संवारने में महिलाएं सबसे बड़ी और विशेष भूमिका निभाती हैं- न सिर्फ उनकी अपनी पीढ़ी में बल्कि अगली पीढ़ी में भी।
- लड़कियों को अच्छी शिक्षा देना सबसे अच्छा तरीका है सभी वंचित तबकों में मौजूदा और भविष्य की पीढ़ी के शिक्षा के स्तर को सुधारने का।
- इसीलिए NEP इस बात की सिफारिश करता है कि वंचित या कम प्रतिनिधित्व वाले वर्गों में विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए बनाई गई नीतियों और योजनाओं का लक्ष्य खासतौर पर इन वर्गों की लड़कियां होनी चाहिए।

स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर्स के माध्यम से कुशल एवं प्रभावी प्रबंधन

"हालांकि स्कूलों का एकीकरण एक ऐसा विकल्प है जिसकी हमेशा चर्चा होती है। लेकिन यह काम बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से तभी किया जाना चाहिए जब यह सुनिश्चित हो जाए कि करने से स्कूलों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।"-

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020

स्कूलों के एकीकरण का औचित्य

NEP, 2020 के मुताबिक :

- स्कूल के छोटे आकार के कारण उसका संचालन जटिल और आर्थिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। इस कारण स्कूल को अच्छी तरह से चलाने के लिए टीचरों की नियुक्ति और अन्य ज़रूरी संसाधनों का स्तेमाल कर पाना कठिन हो जाता है।
- बहुत ज्यादा संख्या में छोटे स्कूलों का गवर्नेंस और प्रबंधन संबंधी व्यवस्था कर पाना भी चुनौतीपूर्ण होता है।
- कम विद्यार्थियों और शिक्षकों वाले स्कूलों को चलाना शैक्षिक दृष्टि से बेहतर नहीं होता क्योंकि :
  - पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने के लिए कक्षा में एक ही उम्र के कम से कम 15 बच्चों का होना ज़रूरी होता है।
  - टीचर भी अपना बेहतर तभी दे पाते हैं जब वे टीम में काम करते हैं। फिलहाल 80% प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहां टीचरों की संख्या **3** से कम है।

NEP, 2020 के मुख्य बिंदु

- भारत में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के दाखिले की दर लगभग पूर्णता के करीब है। इसकी प्रमुख वजह है सर्व शिक्षा अभियान समेत विभिन्न अभियानों के तहत देश भर में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना (SSA)
- भारत के लगभग **28%** सार्वजनिक प्रथमिक स्कूलों और **14.8%** उच्च प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 30 से भी कम है। (UDISE 2016-17 data)
- स्कूलों के विस्तार की नीति से भले ही उनकी उपलब्धता बढ़ी हो लेकिन इसका नतीजा यह है कि बहुत से स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या ज़रूरत से कम है।
- NEP 2020 में स्कूल कॉम्प्लेक्स के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि एक बड़े भूभाग में सार्वजनिक स्कूलों का एक ऐसा क्लस्टर होंगे जहां फाउंडेशन स्तर से लेकर बारहवीं तक की शिक्षा दी जाएगी।
- ये स्कूल कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस और प्रबंधन के लिहाज से बुनियादी इकाई की तरह काम करेंगे।

NEP, 2020 के मुताबिक स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की प्रस्तावित संरचना

- एक अर्ध-स्वायत्त इकाई जहां बच्चों को फाउंडेशनल स्टेज (3 साल की उम्र से 8 साल के बीच) से लेकर बारहवीं कक्षा (उम्र 18 वर्ष) तक की शिक्षा मिलेगी।
- इसमें शुमार होंगे आस-पास के सभी सार्वजनिक स्कूल जहां पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर 8वीं कक्षा तक और एक सेकंडरी स्कूल जहां 9वीं से 12वीं कक्षा तक शिक्षा दी जाती है।)
- वे सभी स्कूल जो इस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होंगे, उनका चुनाव एक- दूसरे से नज़दीकी के आधार पर किया जाएगा।
- इन कॉम्प्लेक्सेस में आंगनवाड़ी, रोज़गार शिक्षा सुविधाएं और वयस्क शिक्षा केंद्र (AEC) आदि भी होंगे जो उनसे संबद्ध होंगे।

केस स्टडी: राजस्थान में स्कूलों का एकीकरण

- बड़ी संख्या में स्कूलों की पुनर्संस्थापना नुकसायनदायक हो सकती है, खासकर छोटी अवधि में। (Beuchert et al, 2018)। उपलब्ध शिक्षकों की संख्या, प्रशासन और निरीक्षण ढांचे और संसाधनों के उपयोग आदि में किए गए बदलावों के ज़रिए एकीकरण का लंबी अवधि में शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है। (Shukla, 2019)
- 2014-15 और 2018-19 के बीच, राजस्थान में करीब 19,500 सरकारी स्कूलों का एकीकरण किया गया।
- आदर्श स्कूल या बड़े स्कूल बनाने के लिए प्राथमिक स्कूलों (कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8, या कक्षा 6 से 8) को बंद कर दिया गया। या फिर उन्हें माध्यमिक स्कूलों (कक्षा 9 से 12 तक किसी भी कक्षा वाले), के साथ एकीकृत कर दिया गया, विशेषरूप से साल 2014 में। हालांकि साल 2016-17 में माध्यमिक स्कूलों को भी माध्यमिक स्कूलों के साथ मिला दिया गया (Bordoloi & Shukla, 2019)
- राजस्थान में बोर्दोलोई और शुक्ला (2019) ने पाया कि एकीकृत किए गए स्कूलों में दाखिलों की संख्या में , पूरे राज्य के अन्य सरकारी स्कूलों के मुकाबले काफी गिरावट आई.; इसमें सबसे ज्यादा गिरावट दिव्यांग बच्चों, अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति के बच्चों के दाखिले में देखी गई। हालांकि एकीकरण के बाद शिक्षकों की उपलब्धता और सुविधाओं में सुधार देखने को मिला।
- इसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी राजस्थान का अनुसरण करते हुए सरकारी स्कूलों का एकीकरण किया गया।

राजस्थान में सभी श्रेणियों के सरकारी स्कूलों की कुल संख्या : 2013-14 बनाम 2016-17

Source: Bordoloi & Shukla, 2019

स्कूली शिक्षा के लिए मानदंड और प्रमाणन स्तर तय करना

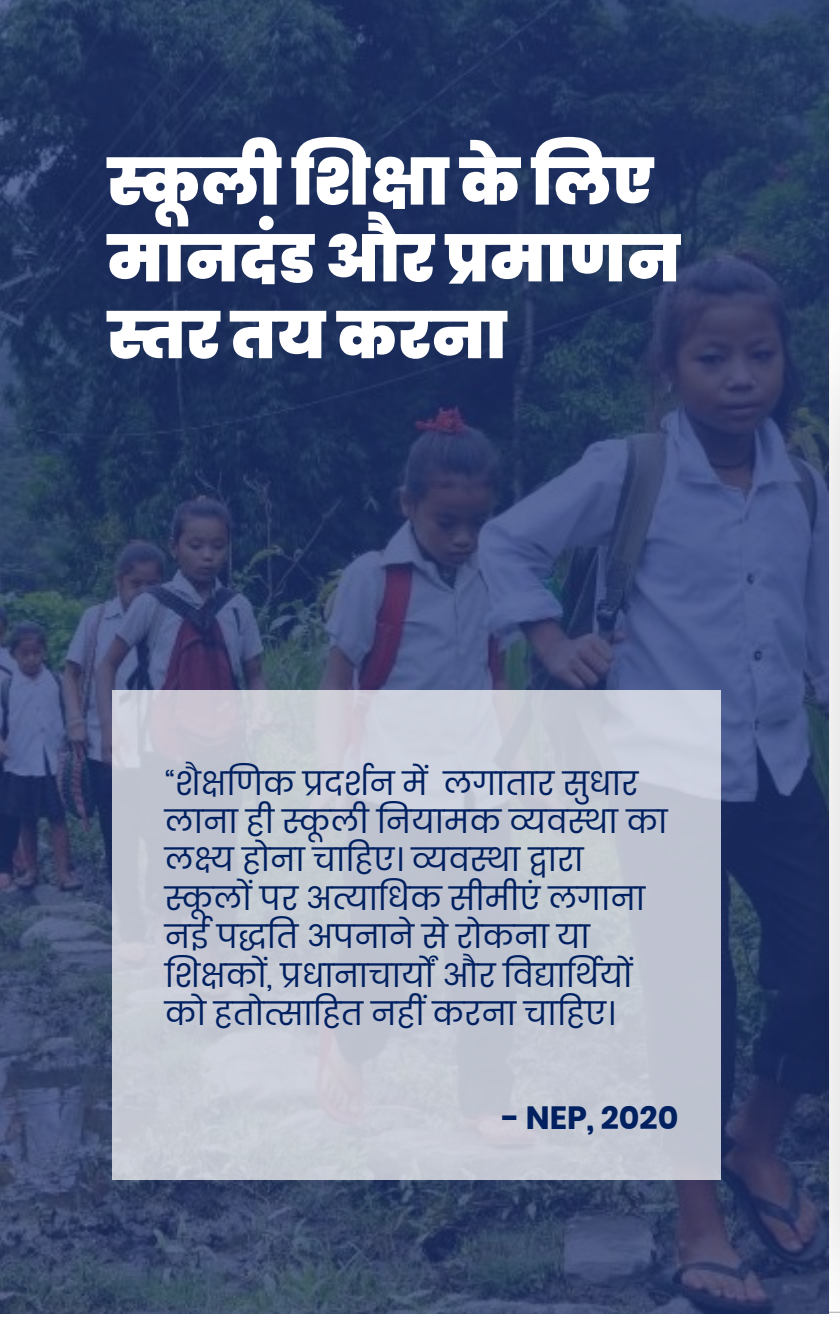

"शैक्षणिक प्रदर्शन में लगातार सुधार लाना ही स्कूली नियामक व्यवस्था का लक्ष्य होना चाहिए। व्यवस्था द्वारा स्कूलों पर अत्याधिक सीमीएं लगाना नई पद्धति अपनाने से रोकना या शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और विद्यार्थियों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए।

– NEP, 2020

NEP, 2020 के मुख्य बिंदु

- भारत में स्कूली शिक्षा के नियमन और प्रशासन की व्यवस्था का स्वरूप कठोर और कमज़ोर बनाने वाला है।
- मौजूदा संरचना में सारवजनिक शिक्षा के प्रावधान, सभी स्कूली संस्थाओं के नियमन और इनसे संबंधित नीतियां बनाने जैसे तीनों महत्वपूर्ण कार्य डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन या इसकी शाखाओं द्वारा किया जाता है। जो शक्ति के संचय और हितों के टकराव की वजह बनता है।
- सार्वजनिक और निजी स्कूलों के नियमन के तरीकों में बहुत ज्यादा असमानताएं हैं।
- स्कूल फीस में मनमानी बढ़ोत्तरी से अभिभावकों का बचाव करते हुए , अच्छी शिक्षा के लिए निजी रूप से समाज सेवा के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- सरकारी और निजी स्कूलों के आंकलन और प्रमाणन की शर्तें, मानदंड और प्रक्रिया समान होगी।
- मौजूदा नियमन व्यवस्था में इनपुट पर अत्याधिक ज़ोर दिया जाता है। इसकी समीक्षा कर इसमें सुधार किया जाएगा।

NEP, 2020 में राज्यों की स्कूली व्यवस्था की प्रस्तावित संरचना

डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन

- स्कूली शिक्षा की निगरानी और नीति निर्धारण की ज़िम्मेदारी एक राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्था को दी जाएगी।
- यह संस्था स्कूलों के प्रावधान, संचालन और नियमन का कम नहीं करेगी।

डिरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन

- पूरे राज्य में सार्वजनिक स्कूलों की व्यवस्था, शैक्षणिक संचालन, और सेवा प्रबंधन की ज़िम्मेदारी
- स्वतंत्र रूप से कार्यकरते हुए संबंधित नीतियों लागू करेंगे।

स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी (SSSA)

- आधारभूत मानकों के आधार पर न्यूनतम मापदंड तय करना जिनका सभी स्कूल पालन कर सकें।

स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT)

- राज्य में शिक्षा और पाठ्यक्रम के स्तर समेत सभी शैक्षणिक मसलों पर राय देना।
- सभी संबंधित पक्षों और हितधारकों के साथ बातचीत के आदार पर स्कूलों की गुणवत्ता आंकलन और प्रमाणन का खाका (SQAAF) विकसित करना

नो डिटेन्शन पॉलिसी (फेल न करने की नीति) का त्याग

बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून (RTE) 2009 और फेल न करने की नीति (नो डिटेन्शन पॉलिसी)

RTE कानून 2009

6-14 साल की उम्र तक के बच्चों को नज़दीकी स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से कक्षा 8 तक) का अधिकार

नो डिटेन्शन पॉलिसी : कक्षा 8 की समाप्ति तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता। भले ही उनकी पढ़ाई, उनकी कक्षा के स्तर के अनुसार नहीं है।

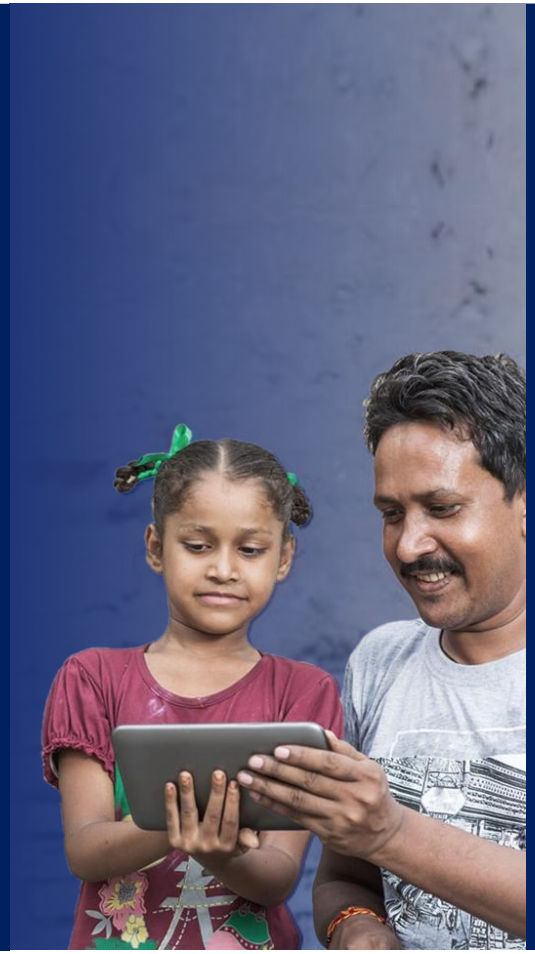

RTE में संशोधन 2017

कक्षा 5 और 8 में नियमित रूप से परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। अगर कोई बच्चा इन परीक्षाओं में फेल होता है तो उसे अतिरिक्त शिक्षण देकर दो महीनों के भीतर दोबारा परीक्षा ली जाएगी। अगर बच्चा इस परीक्षा में दोबारा फेल हो, तो राज्य सरकार के पास उस बच्चे को उसी कक्षा में रोकने का अधिकार होगा।

(भारतीय संसद (लोक सभा) विधेयक संख्या 166, वर्ष 2017)

नो डिटेन्शन पॉलिसी

समर्थन पक्ष

- फेल होने से बच्चे हतोत्साहित होते हैं। और इसका नतीजा होता है ड्रॉपआउट।
- डिटेन्शन से उन पहलुओं से ध्यान हटता है जो पढ़ाई को प्रभावित करते हैं।

विपरीत पक्ष

- अपने आप प्रमोट होने से बच्चों में पढ़ाई और शिक्षकों में पढ़ाने के प्रति उत्साह कम होता है।

नो डिटेन्शन पॉलिसी पर विभिन्न राज्यों का मत

समर्थन करने वाले राज्य

" इस नीति की वजह से बच्चों का खुद पर विश्वास बढ़ा है और स्कूलों का ड्रॉपआउट रेट भी कम हुआ है। कौन सी नीति अपनानी है इसका फैसला करने की स्वतंत्रता राज्यों को दी जानी चाहिए।"

महाराष्ट्र

"इस नीति के कारण बच्चे फेल होने, रोके जाने या बदनामी के डर के बिना बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं। CCE को मज़बूत बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह रटंत विद्या पर केंद्रित नहीं है।

तेलंगाना

" शिक्षा में बच्चों के हित को बनाए रखना ज़रूरी है। परीक्षाएं साल के अंत में लेकर कमज़ोर बच्चों की सहायता की जानी चाहिए।"

कर्नाटक

पश्चिम बंगाल, गुजरात और ओडीशा ऐसे पहले राज्य रहे जिन्होंने नो डिटेन्शन पॉलिसी का त्याग किया।

विरोध करने वाले राज्य

"किसी बच्चे को एक ही कक्षा में चीज़ें बेहतर ढंग से सीखने का दूसरा मौका देना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि उसे बिना तैयारी के अगली कक्षा में भेज दिया जाए। "

केरल

" इस नीति से हितधारकों की प्रतिबद्धता के स्तर में कमी आती है। परीक्षाओं/टेस्ट से बच्चों को प्रतिस्पर्धा का मौका तो मिलता ही है। साथ ही वे अच्छी तरह पढ़ाई करने के लिए भी प्रोत्साहित होते हैं। "

हरियाणा

"इस नीति से बच्चों में अनुशासन की कमी आती है और ड्रॉपआउट्स बढ़ते हैं। नो डिटेन्शन पॉलिसी को कक्षा तीन तक सीमित किया जाना चाहिए।"

दिल्ली

Source: Ritika Chopra , Uma Vishnu, Indian Express, 2016

क्या कहते हैं आंकड़े ?

स्कूलों में ड्रॉपआउट की दर –लिंगानुसार (2014-15)

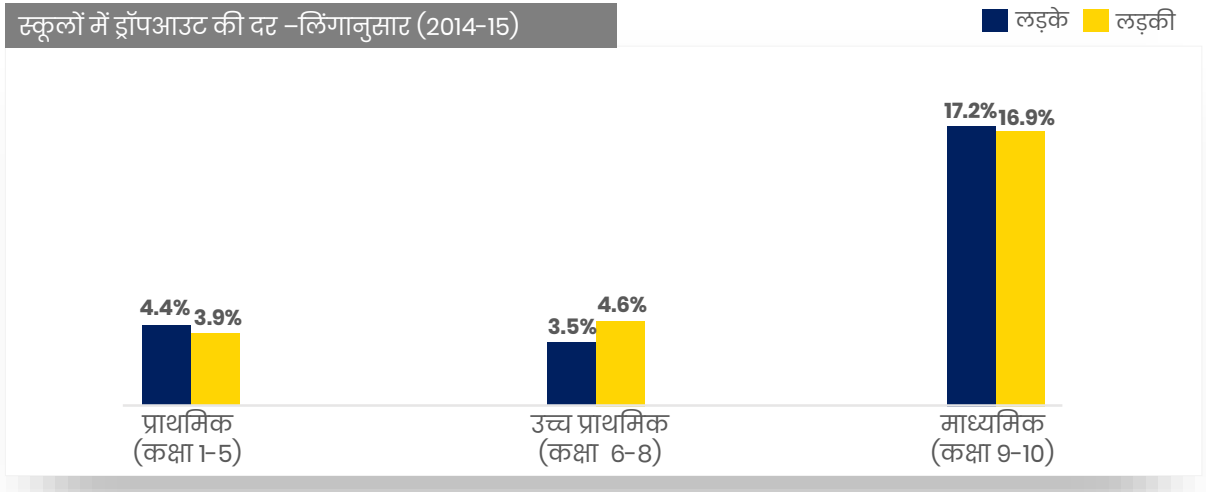

स्कूलों में ड्रॉपआउट दर – उपवर्ग वार (2014-15)

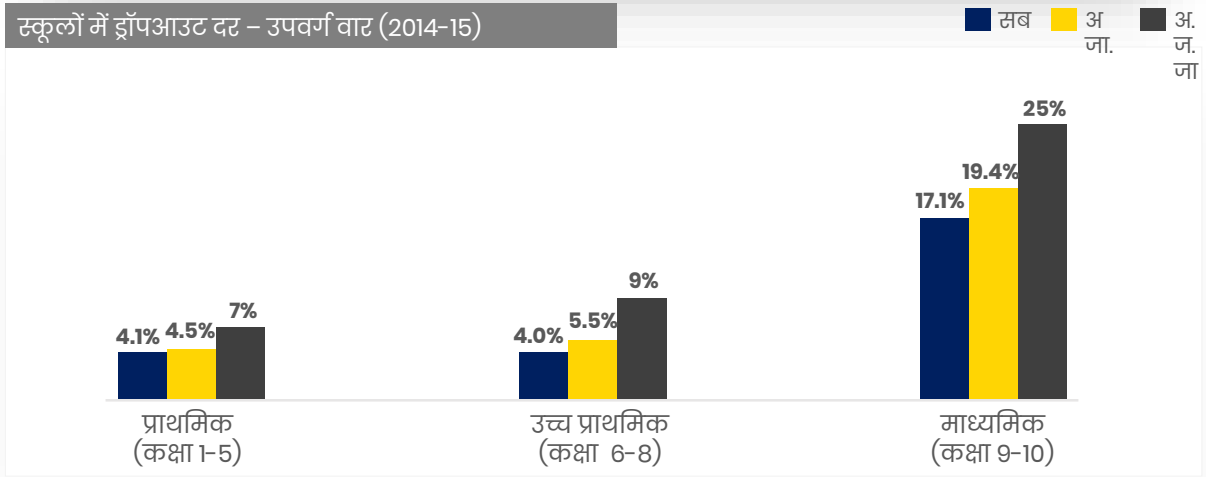

Source: Education statistics at a glance

हालांकि प्राथमिक स्कूलों के स्तर पर दाखिले की दर लगभग पूर्णता के करीब है। लेकिन ऊपर की कक्षाओं की ओर बढ़ते हुए विद्यार्थियों की संख्या लगातार घटती जाती है।

इस वजह से माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर ड्रॉपआट दर काफी ज्यादा हो जाती है। **कक्षा 9–10** के बीच ड्रॉपआउट दर सबसे ज्यादा बढ़कर **17%**पर पहुंच जाती है।

हालाकि लिंग अनुसार ड्रॉपआउट रेट में कुछ विविधता है। लेकिन उप वर्ग वार यह आंकड़ा ज्यादा है। खासकर अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की ड्रॉपआट दर सबसे ज्यादा है।

बच्चों को स्वत: प्रमोट करने और क्लास में न रोकने की बाध्यता भी प्राथमिक स्कूलों के स्तर पर कम ड्रॉपआउट दर में कमी की एक वजह है।

माध्यमिक स्कूल के स्तर पर ऐसी कोई बाध्यता न होने के कारण इस कक्षाओं में ड्रॉपआउट की दर में तेजी देखने को मिलती है।

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा अनिवार्य

आंध्र प्रदेश के स्कूलों में अंग्रेज़ी भाषा को शिक्षण की भाषा बनाना

नीतिगत बदलाव

- आंध्र प्रदेश सरकार की शैक्षणिक सत्र 2020-21 से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेज़ी में पढ़ाई करवाने की योजना भाषा को (Business standard, 2019)
- शैक्षणिक 2020-21 से, सभी स्कूलों में पहली से लेकर छठवीं कक्षा तक तेलुगू की जगह अंग्रेज़ी में पढ़ाई कराई जाएगी। (Economic Times, 2019)
- उर्दू या तेलुगू अनिवार्य विषय होंगे। कक्षा 7 से धीरे – धीरे अंग्रेज़ी को पढ़ाई की भाषा बनाया जाएगा। (*ibid*)

अंग्रेज़ी को शिक्षण की भाषा बनाने की वजह

- सामान्यतौर पर माना जाता है कि अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल से पढ़ाई करने वाले बच्चों को अच्छी नौकरी मिलने में मदद मिलती है। यही वजह है कि भारत में हाल के सालों में अंग्रज़ी माध्यम स्कूलों की मांग और उपलब्धता काफी तेज़ी से बढ़ी है। (Mody, 2019)
- आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार भी अब अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की बजाय अंग्रेज़ी स्कूलों में भेज रहे हैं। इससे सरकारी टीचरों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। (*ibid*)
- कई राज्यों की सरकारें इसे रोकने और इस ट्रेंड को उल्टा करने के लिए सरकारी स्कूलों में अंग्रेज़ी माध्यम शिक्षण अपना रही हैं। (*ibid*)

*3 सितंबर 2020 तक की स्थिति- भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ दिए गए आदेश पर रोक लगाने से इन्कार किया है. साथ ही उच्च न्यायालय इस बात की भी समीक्षा कर रहा है कि क्या आंध्र प्रदेश सरकार, राज्य में शिक्षा की अनिवार्य भाषा के रूप में अंग्रेज़ी को लागू करने पर ज़ोर दे सकती है या नहीं?

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

स्कूल में बच्चों की पढ़ाई का प्रदर्शन सुधारने में मातृभाषा का महत्व

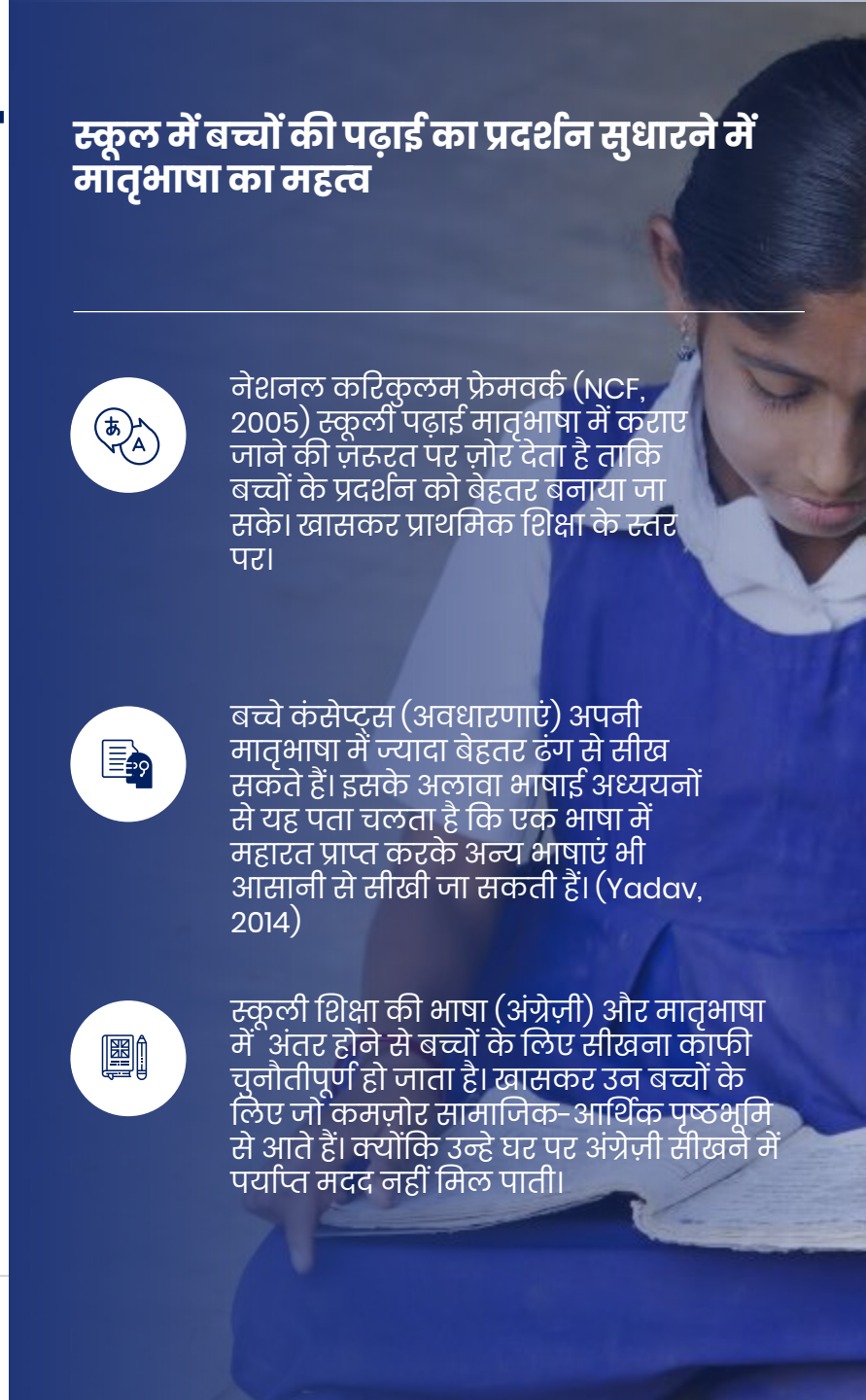

- नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF, 2005) स्कूली पढ़ाई मातृभाषा में कराए जाने की ज़रूरत पर ज़ोर देता है ताकि बच्चों के प्रदर्शन को बेहतर बनाया जा सके। खासकर प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर।
- बच्चे कंसेप्ट्स (अवधारणाएं) अपनी मातृभाषा में ज्यादा बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। इसके अलावा भाषाई अध्ययनों से यह पता चलता है कि एक भाषा में महारत प्राप्त करके अन्य भाषाएं भी आसानी से सीखी जा सकती हैं। (Yadav, 2014)
- स्कूली शिक्षा की भाषा (अंग्रेज़ी) और मातृभाषा में अंतर होने से बच्चों के लिए सीखना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। खासकर उन बच्चों के लिए जो कमज़ोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। क्योंकि उन्हे घर पर अंग्रेज़ी सीखने में पर्याप्त मदद नहीं मिल पाती।

भारत में शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक

समीक्षा

भारत में शिक्षा क्षेत्र में राज्यों के प्रदर्शन का आंकलन और मानदंड तय करने के लिए दो अलग-अलग सूचकांक हैं।

परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI)

शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी (DoSEL) द्वारा विकसित PGI एक आकांक्षापूर्ण एवं स्थिर सूचकांक है।

स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स (SEQI)

नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया SEQI, एक सक्रिय सूचकांक है, जो मौजूदा समय में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों द्वारा स्थापित किया गया है।

मापदंड	PGI	SEQI
संस्थान	DoSEL	नीति (NITI) आयोग
कवरेज	भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश	भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
सूचकांक के घटक/क्षेत्र	लर्निंग आउटकम और क्वालिटी, उपलब्धता, बुनियादी ढांचा, समानता और गवर्नेंस प्रक्रिया	लर्निंग के नतीजे, उपलब्धता का नतीजा, बुनियादी ढांचे का नतीजा और गवर्नेंस प्रक्रिया का नतीजा
लक्ष्य	स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता	शिक्षा का नतीजा
आंकड़ों के स्त्रोत	NAS, UDISE, MHRD's Shagun MIS/ State, MDM पोर्टल	NAS, UDISE, MHRD's Shagun MIS/ State
इंडिकेटर्स की संख्या	70	30 (PGI इंडिकेटर्स का एक घटक)
नतीजे	हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के इंडेक्स स्कोर के आधार पर उसे ग्रेड दिया जाता है	हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का इंडेक्स स्कोर

SEQI का उद्देश्य (SEQI रिपोर्ट, NITI आयोग, 2019)

- स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए एक खाका प्रदान करना
- इंडेक्स का लक्ष्य है भारत में पढ़ाई, उपलब्धता, समानता एवं गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों समेत शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार की ओर शिक्षा नीति को लक्षित करना।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक ऐसा मंच उपलब्ध करवाना जहां वे शिक्षा क्षेत्र में अपने प्रदर्शन का आंकलन कर सकें और ज़रूरत के मुताबिक नीतिगत हस्तक्षेप या पाठ्यक्रम में सुधार संबंधी कदम उठा सकें।

PGI: डेटा एवं प्रक्रिया

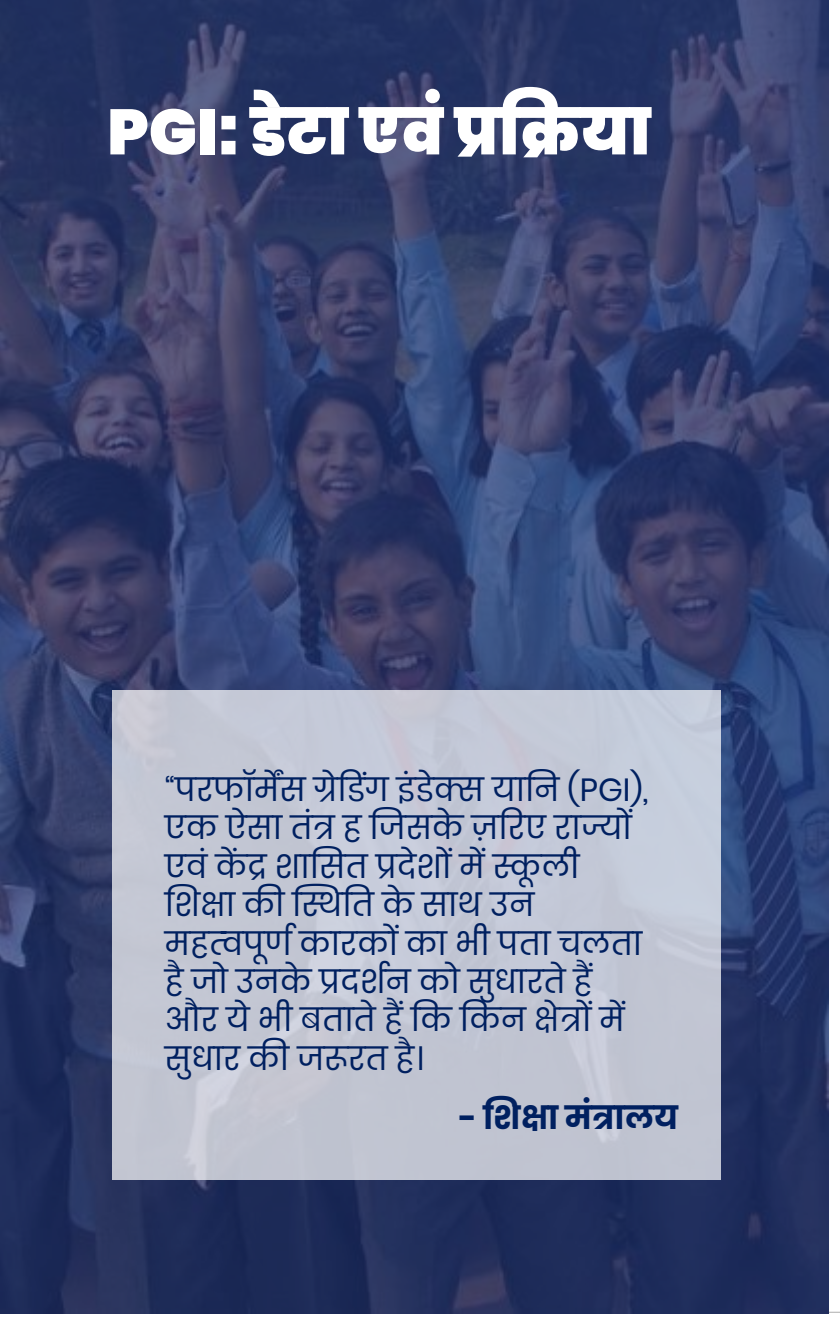

"परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानि (PGI), एक ऐसा तंत्र ह जिसके ज़रिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा की स्थिति के साथ उन महत्वपूर्ण कारकों का भी पता चलता है जो उनके प्रदर्शन को सुधारते हैं और ये भी बताते हैं कि किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है।

- शिक्षा मंत्रालय

इंडेक्स श्रेणियों, क्षेत्रों और डेटा स्त्रोतों का संक्षिप्त विवरण				
श्रेणी	**क्षेत्र**	**सूचंकांकों की संख्या**	**कुल प्रमाण**	**डेटा स्त्रोत**
1. **नतीजे**	1 शैक्षणिक परिणाम एवं गुणवत्ता	9	180	NAS, शगुन
	2 उपलब्धता	8	80	UDISE, शगुन
	3 संसाधन एवं सुविधाएं	11	150	UDISE, शगुन MDM पोर्टल
	4 समानता	16	230	NAS, UDISE, शगुन
2. **गवर्नेंस और प्रबंधन**	1 गवर्नेंस प्रक्रिया	26	360	UDISE, शगुन
कुल		**70**	**1000**	

PGI, 2018-19 में भारतीय राज्यों का प्रदर्शन

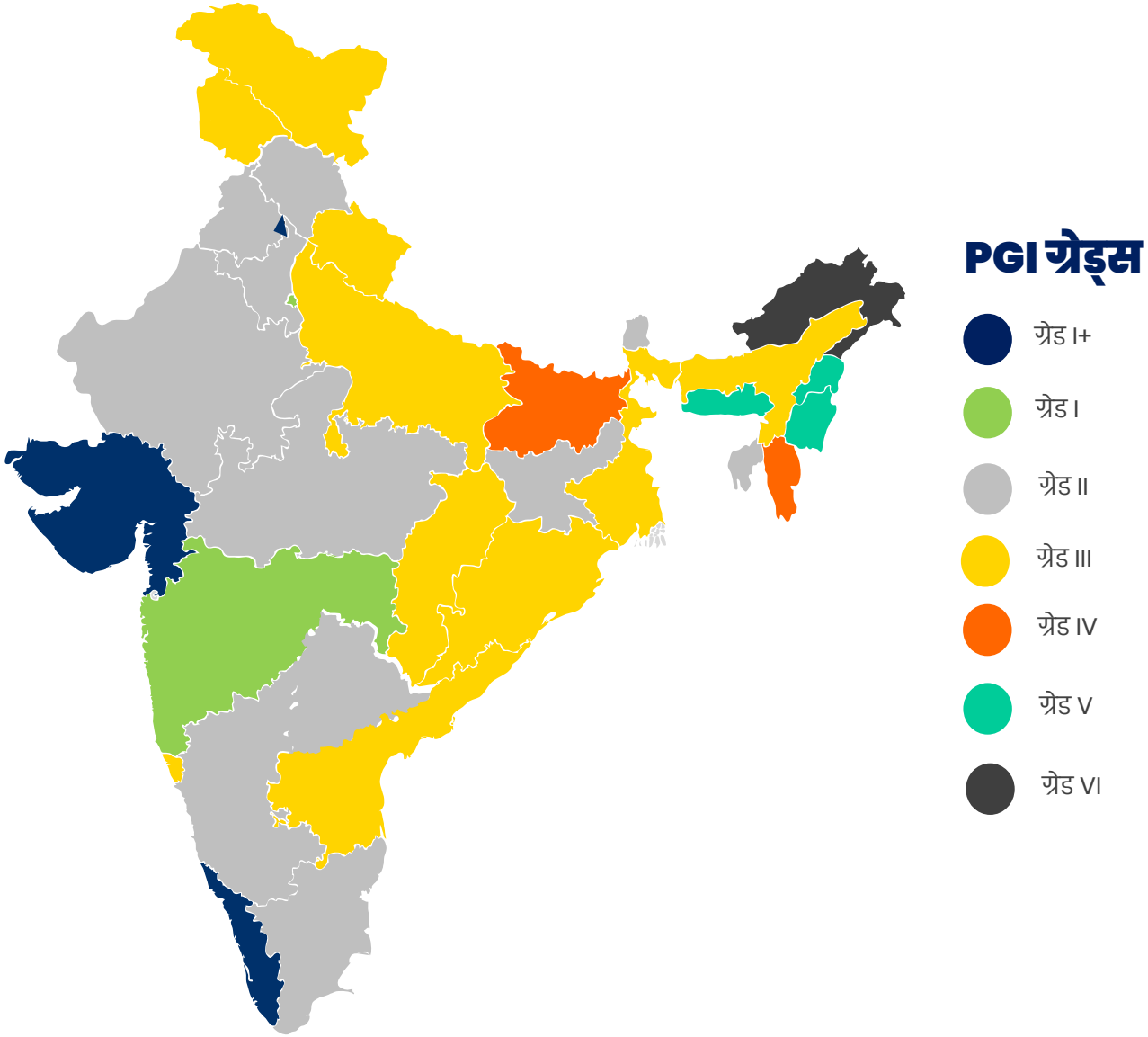

क्षेत्र	क्षेत्र-वार सफल होने वाले प्रमुख
शैक्षणिक परिणाम एवं गुणवत्ता	▪ राजस्थान (168/180) ▪ चंडीगढ़ (160/180) ▪ कर्नाटक (160/180) ▪ झारखंड(156/180)
प्रवेश	▪ केरल(79/80) ▪ हरियाणा (78/80) ▪ दिल्ली (77/80) ▪ आंध्र प्रदेश (77/80)
बुनियादी ढांचा और सुविधाएं	▪ गोवा (137/150) ▪ चंडीगढ़ (136/150) ▪ दिल्ली (130/150) ▪ पंजाब (128/150)
समानता	▪ दिल्ली (220/230) ▪ पश्चिम बंगाल (217/230) ▪ दादरा एवं नगर हवेली (217/230) ▪ गुजरात (213/230)
सरकारी प्रक्रियाएं	▪ गुजरात (315/360) ▪ चंडीगढ़ (310/360) ▪ केरल (296/360) ▪ ओडीशा (282/360)

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

स्त्रोत – शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार - http://pgi.seshagun.gov.in/

SEQI: आंकड़े और कार्य-प्रणाली

"SEQI संकेतों पर आधारित एक ऐसी प्रक्रिया है जो संपूर्ण भारतीय स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था के प्रभाव, गुणवत्ता और क्षमता का आंकलन करती है।"

नीति आयोग, 2019

सूचकांक की श्रेणियों,क्षेत्रों और आंकड़ों के स्त्रोतों का संक्षिप्त विवरण				
श्रेणी	**क्षेत्र**	**संकेतों की संख्या**	**कुल मान**	**आंकड़ों के स्त्रोत**
1. नतीजे	**1.1** पढ़ाई के नतीजे	3	360	NAS
	1.2 उपलब्धता के नतीजे	3	100	UDISE, MHRD's Shagun MIS/ States
	1.3 नतीजों के लिए बुनियादी ढांचा और सुविधाएं	3	25	UDISE
	1.4 समानता के नतीजे	7	200	NAS
2. गवर्नेंस प्रक्रिया और सहायता के नतीजे	विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता, पर्याप्त प्रशान, प्रशिक्षण, जवाबदेही और पारदर्शिता	14	280	UDISE, MHRD's Shagun MIS/ States
Total		30	965	

Source: NITI Aayog, 2019, School Education Quality Index (SEQI)

SEQI संपूर्ण प्रदर्शन स्कोर : बड़े राज्य

- बड़े राज्यों का संपूर्ण प्रदर्शन अंक, केरल के लिए **76.6%** और उत्तर प्रदेश के लिए **36.4%** के बीच रहा।
- 20 बड़े राज्यों में से 18 राज्यों ने 2015-16 और 2016-17 के बीच अपने संपूर्ण प्रदर्शन स्कोर में सुधार किया।

चित्र अ : बड़े राज्य : संपूर्ण और श्रेणीबद्ध प्रदर्शन , 2016-2017

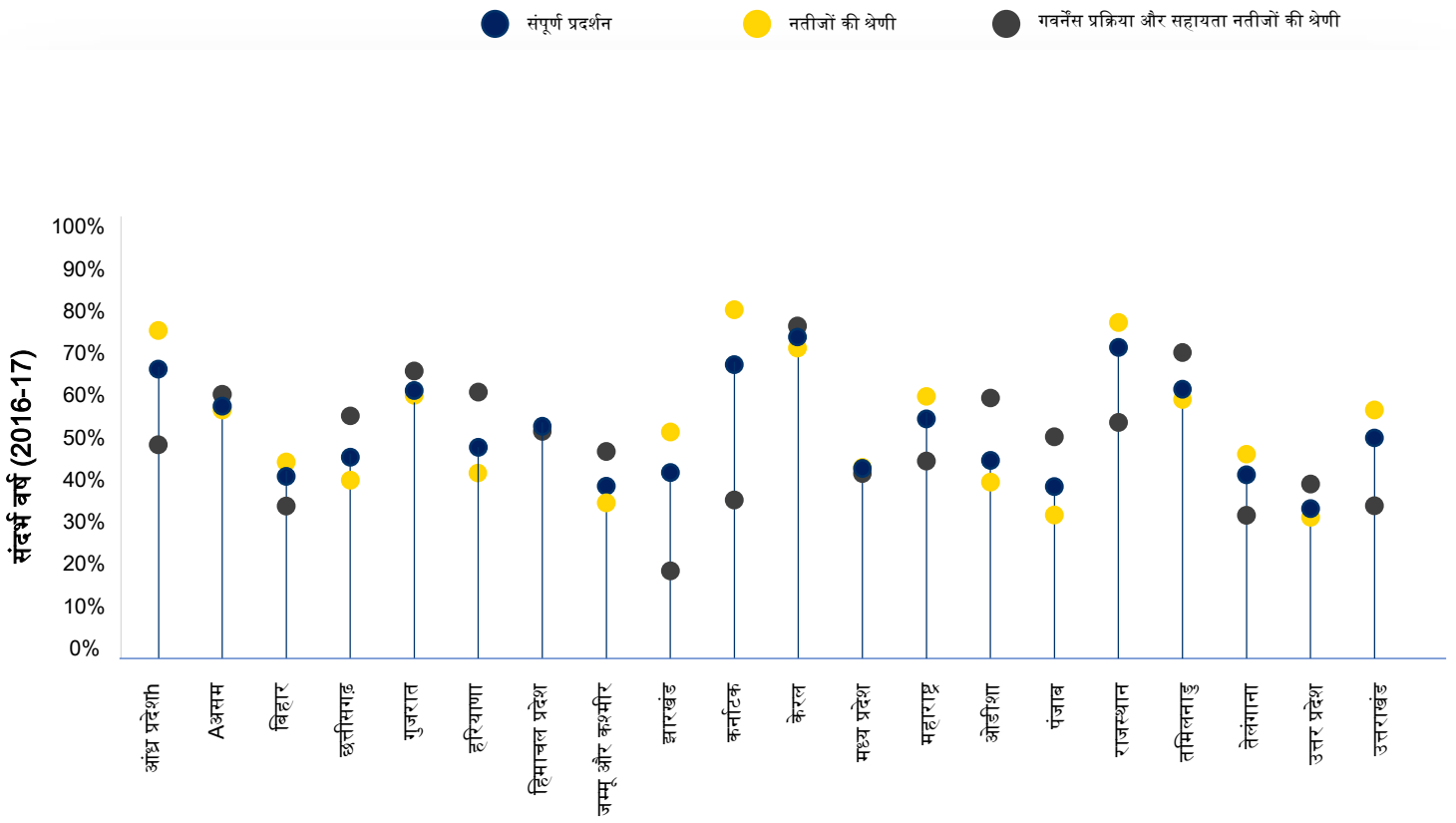

Source: NITI Aayog, 2019, School Education Quality Index (SEQI) Report

SEQI संपूर्ण प्रदर्शन स्कोर : छोटे राज्य

- छोटे राज्यों में संपूर्ण प्रदर्शन स्कोर मणिपुर के **68.8%** से लेकर अरुणाचल प्रदेश के **24.6% के बीच रहा**
- केंद्रशासित प्रदेशों में संपूर्ण प्रदर्शन स्कोर सीमा चंडीगढ़ के **82.9%** से लेकर लक्ष्द्वीप के **31.9%** के बीच रहा

चित्र ब : छोटे राज्यऔर केंद्रशासित प्रदेश : संपूर्ण एवं श्रेणीबद्ध प्रदर्शन, 2016-17

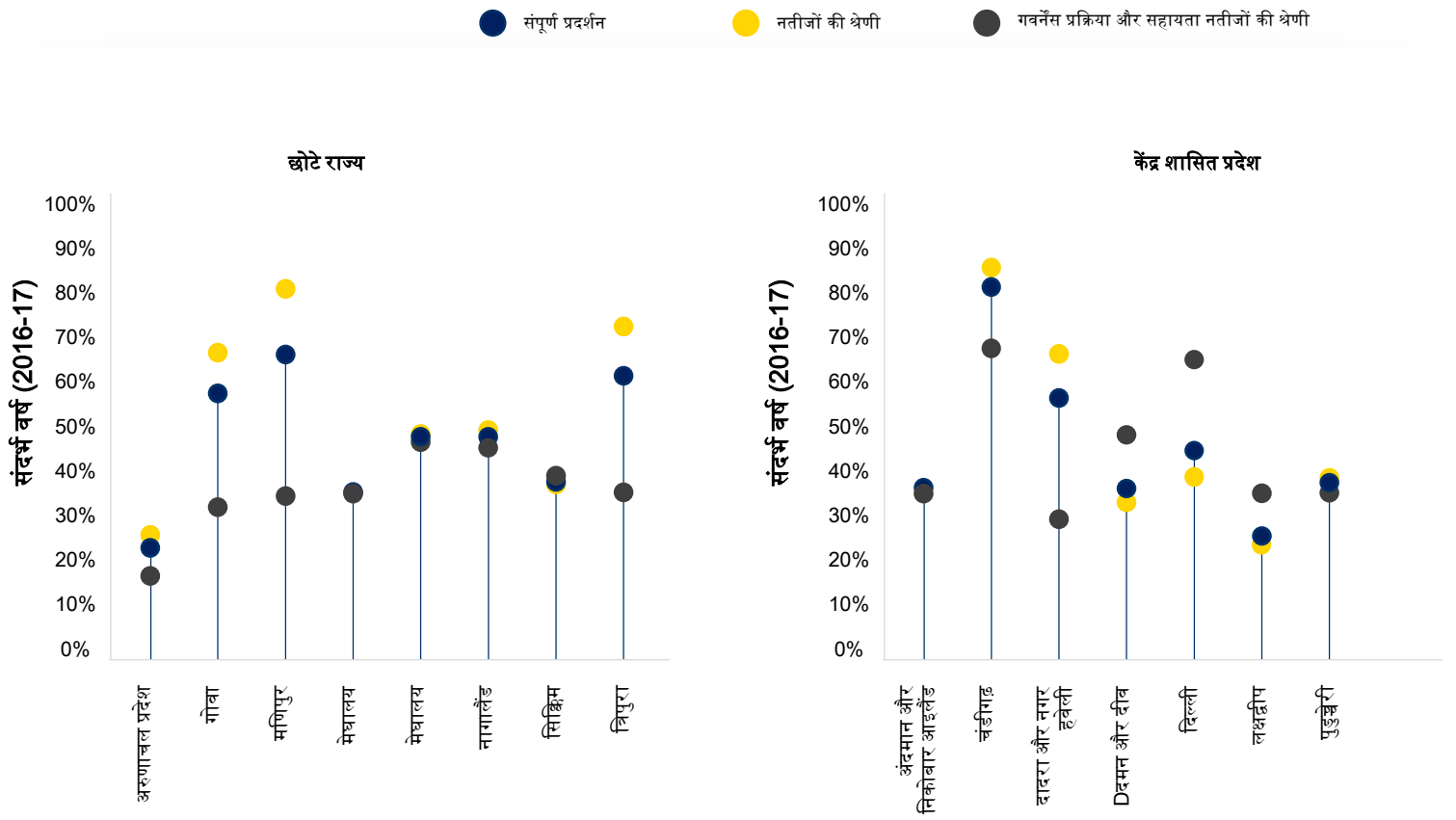

Note: The Outcomes Category score for Himachal Pradesh is 55.6 Percent and Meghalaya is 46.0 percent

केस स्टडी

ब्राज़ील ने कैसे बनाया बेसिक एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स?

Indice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)

ब्राज़ील के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2007 में शुरुआत

ब्राज़ील के सभी स्कूलों, नगपालिका, राज्य, संघीय ज़िलों और प्रदेशों में बुनियादी शिक्षा में प्रगति की व्यवस्थित ढंग से निगरानी के लिए

बच्चों के पढ़ाई में प्रदर्शन और उनकी लयता – कक्षा में प्रगति, दोहराव और ग्रैजुएशन की दर

IDEB पर फोकस

- IDEB आधारित है प्रोवा ब्राज़ील – यानि ब्राज़ील में 4थी और 8वीं कक्षा के बच्चों के गणित और पुर्तगाली भाषा के नेशनल लर्निंग असेसमेंट पर।
- इस इंडेक्स की खासियत हैं वो घटक जिन्हें मिलाकर इसका निर्माण किया है। प्रोवा बाज़ील टेस्ट के परिणाम को स्कूलों में होने वाले दाखिले, दोहराव और प्रमोशन जैसे स्कूलों के प्रशासनिक डेटा को मिलाकर यह इंडेक्स तैयार किया गया है। (Bruns, Evans & Luque, 2012)
- इस इंडेक्स की रचना ऐसी है जो स्कूलों को इंडेक्स पर अपना प्रदर्शन बेहतर दिखाने के लिए उन बच्चों को प्रमोट करने से रोकती है जो कि पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहे। (*ibid*)
- IDEB बहुत कम समय में निजी स्कूलों, नगरपालिका और राज्य की स्कूली व्यवस्था से संबंधित प्रदर्शन के आंकलन का महत्वपूर्ण पैमाना बन चुका है। (*ibid*)
- IDEB के नतीजों को मीडिया में व्यापक तौर से प्रचार मिलता है। इसके अलावा वहां की संघीय सरकार भी देश के सभी 26 राज्यों (संघीय ज़िलों समेत) और मगरपालिका स्कूल व्यवस्था के तहत आने वाले 5,564 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की शिक्षा के नतीजों को सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। (*ibid*)

IDEB के प्रभाव का उदाहरण

- IDEB ने राज्य और नगरपालिका स्तर पर टीचर बोनस प्रोग्राम को लागू करना संभव बनाया है। (Bruns, Evans & Luque, 2012)
- हालांकि हर राज्य और नगरपालिका के प्रोग्राम्स में अनेकों संरचनात्मक विशेषताएं हैं। लेकिन ये सभी IDEB मेट्रिक्स में तय किए गए सालान लक्ष्य पर ही आधारित हैं। (*ibid*)

मोटे तौर पर देखा जाए तो IDEB ने बुनियादी शिक्षा के मामले में राज्यों (फेडरल ज़िलों) और नगपालिका ओं में अन्वेषण के तुलनात्मक अध्ययन का एक सशक्त प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। (*ibid*)

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट (PISA) में भारत की वापसी

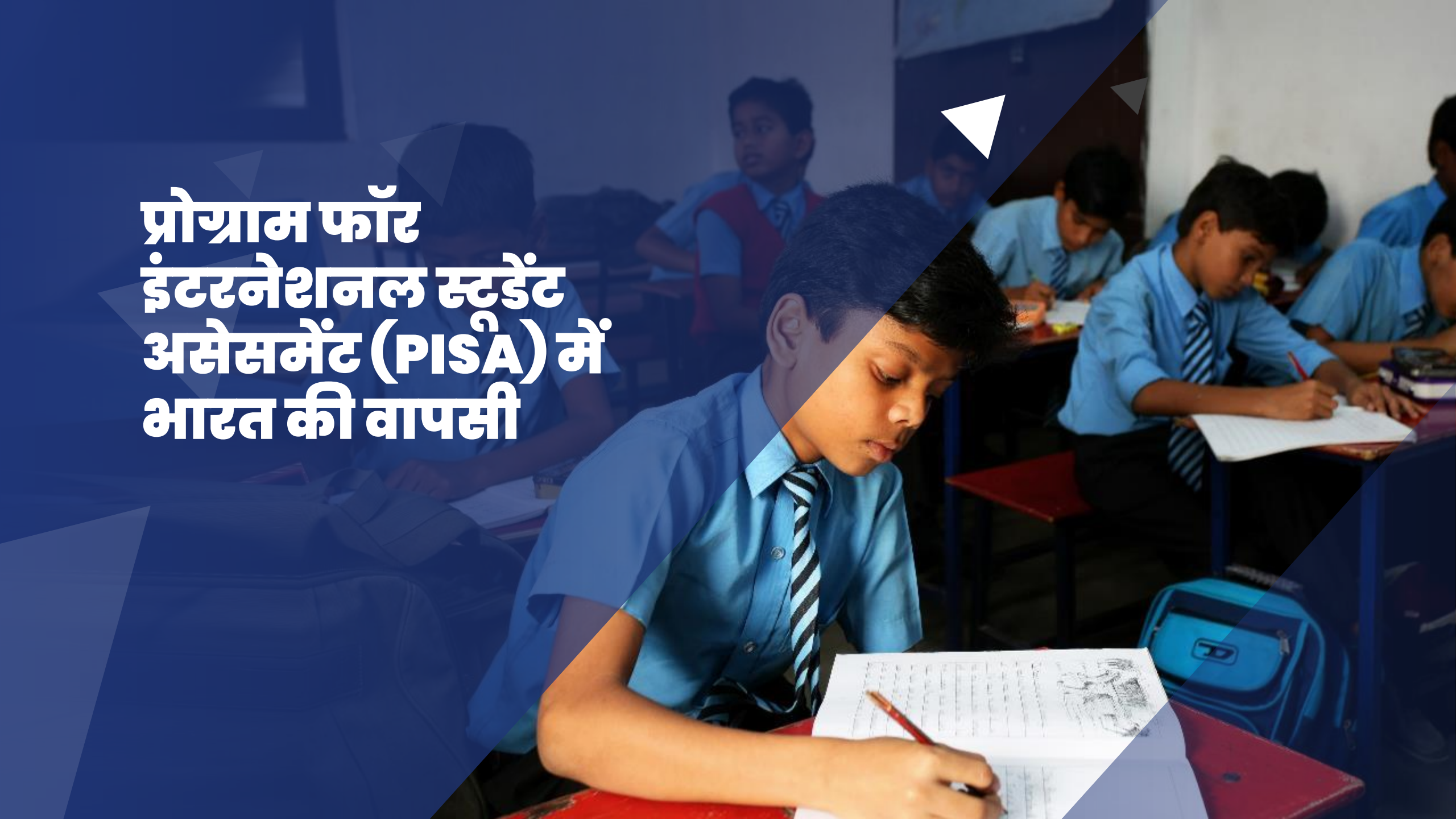

समीक्षा

13 सों के अंतराल के बाद भारत 2022 में प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट (PISA) में हिस्सा लेगा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने PISA का आयोजन करनेवाली संस्था OECD के साथ करार किया है। इससे इस तीन वर्ष में एक बार होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में भारत की भागीदारी की पुष्टि हो गई है। इस सर्वे के तहत 15 साल के विद्यार्थियों का रीडिंग, गणित, विज्ञान और कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में आंकलन किया जाता है। (Business Standard, 2019)

3 घंटे का PISA टेस्ट (2022)

1.75 लाख **विद्यार्थी**
चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों से

600 **नवोदय विद्यालय**

3000 **केंद्रीय विद्यालय**

PISA अधिकारियों की एक टीम वर्ष 2021 में प्रतिभागी स्कूलों में एक ट्रायल टेस्ट आयोजित करेगी।

PISA में भारत का पूर्व अनुभव

- भारत ने 2009 में PISA में प्रतिभाग किया था। यह आंकलन भारत के दो राज्यों, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में किया गया था। (Rana, 2019)
- इस टेस्ट में भारत का प्रदर्शन काफी खराब रहा। टेस्ट में भाग लेनेवाले 73 देशों में भारत 72वें स्थान पर रहा। (*ibid*)
- रिपोर्ट्स के मुताबिक NCERT अधिकारियों ने पाया कि विद्यार्थियों ने PISA टेस्ट के गणित वर्ग में सबसे खराब प्रदर्शन किया। (*ibid*)

PISA से क्या सीख सकता है भारत ?

- PISA से भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में मदद मिल सकती है। यह टेस्ट एक तरह की जांच का काम करेगा जिससे मौजूदा व्यवस्था की कमियों का बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। (Mehta, 2019)
- साथ ही PISA में भाग लेकर भारत को, इस टेस्ट में शामिल होने वाले दुनियाभर के 88 अन्य देशों के मुकाबले अपना मानक तय करने में मदद मिलेगी। (*ibid*)
- NAS, जो कि देश की शिक्षा व्यवस्था का आंकलन करने वाला भारत का अपना सर्वे है, धीरे- धीरे प्रतिस्पर्धा आधारित पढ़ाई का आंकलन करने की ओर बढ़ रहा है। PISA, NAS का पूरक हो सकता है।

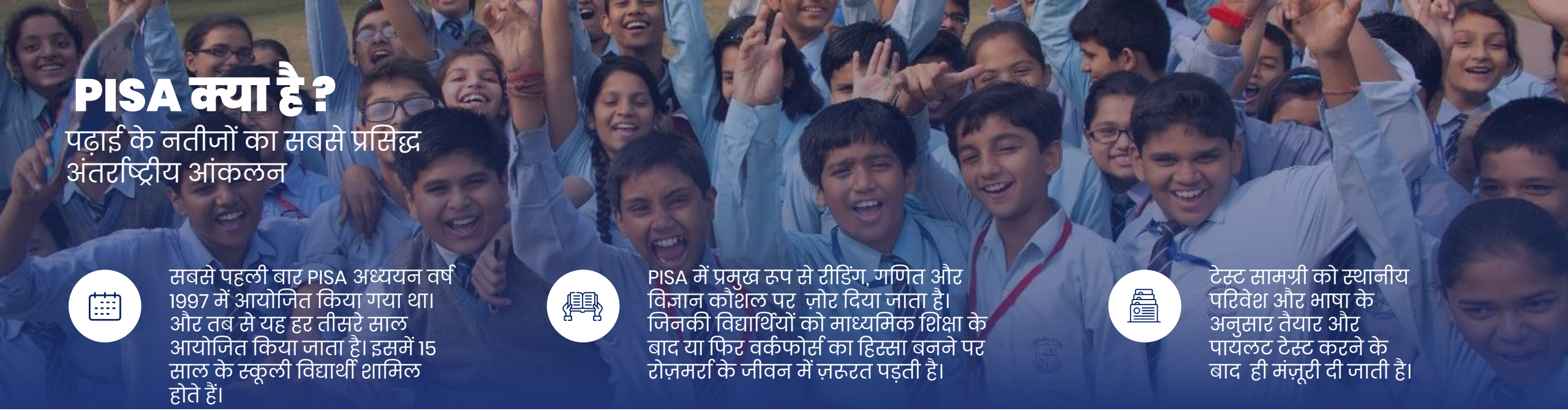

PISA क्या है ?

पढ़ाई के नतीजों का सबसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय आंकलन

सबसे पहली बार PISA अध्ययन वर्ष 1997 में आयोजित किया गया था। और तब से यह हर तीसरे साल आयोजित किया जाता है। इसमें 15 साल के स्कूली विद्यार्थी शामिल होते हैं।

PISA में प्रमुख रूप से रीडिंग, गणित और विज्ञान कौशल पर ज़ोर दिया जाता है। जिनकी विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा के बाद या फिर वर्कफोर्स का हिस्सा बनने पर रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूरत पड़ती है।

टेस्ट सामग्री को स्थानीय परिवेश और भाषा के अनुसार तैयार और पायलट टेस्ट करने के बाद ही मंज़ूरी दी जाती है।

PISA , इन तीन पहलुओं विद्यार्थियों को परखता है

PISA 2015 असेसमेंट और एनालिटिकल फ्रेमवर्क में इन पहलुओं को इस प्रकार परिभाषित किया गया है (OECD, 2015)

- **वैज्ञानिक समझ –** विज्ञान से संबंधित समस्याओं या सवालों को एक विचारवान नागरिक की तरह वैज्ञानिक समझ के साथ हल करने की क्षमता
- **पढ़ना – यानि लिखे हुए शब्दों को समझने, पढ़ने, इस्तेमाल करने , उन पर विचार कर सकने की विद्यार्थी की क्षमता** जिसका इस्तेमाल कर वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ज्ञान बढ़ा सकता है और समाज में हिस्सेदारी ले सकता है।
- **गणित की समझ –** इसे विद्यार्थियों की विभिन्न परिपेक्ष्यों के संबंध में गणितीय सूत्र निकालने, गणना करके इतेमाल करने और अर्थ निकालने की क्षमता के तौर पर समझा जा सकता है। इसमें विवेकात्मक क्षमता, गणितीय अवधारणाओं, प्रक्रियाओं, तथ्यों और परिभाषित करने, समझाने और किसी घटना की भविष्यवाणी करने की क्षमता भी शामिल है।

PISA नतीज़ों की दूसरे देशों से सीमित तुलनात्मकता

- PISA के तहत गैर OECD देशों के नतीजों की सीधे तौर पर OECD देशों के नतीजों से तुलना नहीं की जा सकती।
- PISA में अक्सर गैर OECDदेशों में विद्यार्थियों का नमूना, उसी देश के एक चुने हुए प्रांत से लिया जाता है। इसीलिए यह नमूना राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।
- उदाहरण के तौर पर चीन के PISA के नतीजे बीजिंग, शांघाई, जियांगसू ,और ग्वांगडॉन्ग समेत केवल चार प्रांतों के आंकलन पर आधारित होते हैं।

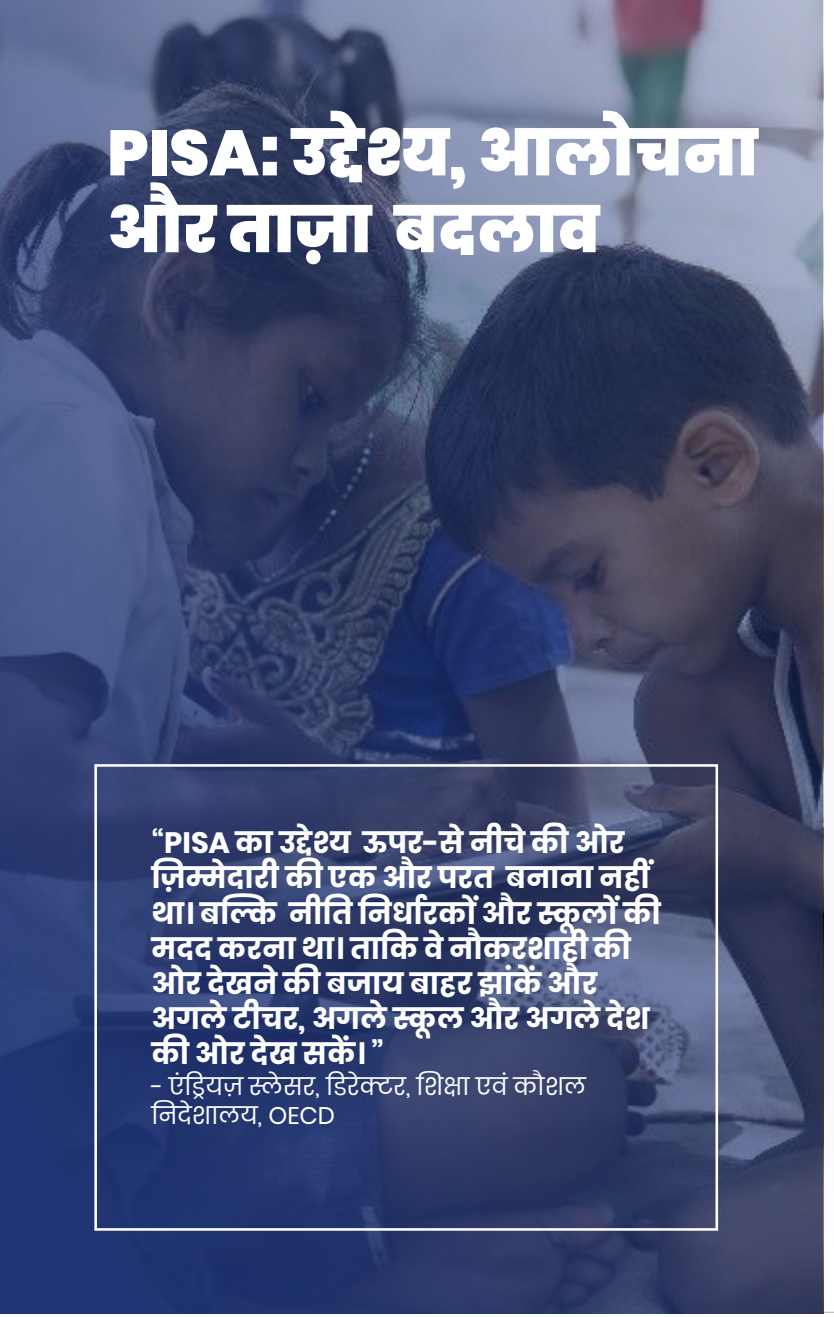

PISA: उद्देश्य, आलोचना और ताज़ा बदलाव

> “PISA का उद्देश्य ऊपर-से नीचे की ओर ज़िम्मेदारी की एक और परत बनाना नहीं था। बल्कि नीति निर्धारकों और स्कूलों की मदद करना था। ताकि वे नौकरशाही की ओर देखने की बजाय बाहर झांकें और अगले टीचर, अगले स्कूल और अगले देश की ओर देख सकें।”
> - एंड्रियज़ स्लेसर, डिरेक्टर, शिक्षा एवं कौशल निदेशालय, OECD

PISA का प्रभाव

- वोलांट (2017) द्वारा की गई एक क्रॉस कल्चरल एनालिसिस में सामने आया कि दुनिया भर में PISA का प्रभाव बढ़ रहा है।
- जर्मनी और कनाडा जैसे देशों में आंकलन व्यवस्था को इस प्रकार विकसित किया गया है कि वे PISA टेस्ट को प्रतिबिंबित करें। (Volante et al, 2019)
- सरकारें अक्सर PISA नतीजों को अन्य सामाजिक घटकों जैसे शिक्षा में समानता, सामाजिक गतिशीलता या अप्रवासी सफलता जैसे नीतिगत फैसलों के समकक्ष रखती हैं। (*ibid*)

PISA की आलोचना

- आलोचकों का मत है कि PISA बहुत ज्यादा करने की कोशिश करता है, ज़रूरी तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर दिखाता है और शिक्षा क्षेत्र में घुड़दौड़ को बढ़ावा देता है। (Andreson & Shendruk, 2019)
- PISA टेस्टिंग पर अति-निर्भरता को बढ़ावा देता है। साथ ही इसका झुकाव जटिल समस्याओं के लिए साधारण समाधान सुझाने की ओर रहता है। (*ibid*)
- वर्ष 2014 में, दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा शिक्षाविदों ने PISA टेस्टिंग पर रोक लगाने की सलाह दी थी। (Gaurdian, 2014)

PISA में बदलाव

- **2015** – जांच या मापन की गड़बड़ियां दूर करने के लिए OECD ने उस मॉडल को बदला जिस पर पूर्व के PISA स्कोर आधारित थे। (Volante et al, 2019)
- **2015 & 18** – इस टेस्ट में मिलकर समस्या सुलझाने, वित्तीय साक्षरता और ग्लोबल कॉम्पिटेंस जैसे नए विषयों को शामिल किया। (*ibid*)
- **2021** – PISA में रचनात्मक सोच पर भी एक असेसमेंट शामिल किया जाएगा। (OECD, 2019)

क्या विद्यार्थियों का आंकलन सुधार को गति देगा ?

- क्या शिक्षा प्रणाली में परीक्षाओं एवं मूल्यांकन के जरिये बेहतर शिक्षा के परिणाम मिल सकते हैं, यह चर्चा का विषय है।

- विरोधियों का तर्क है कि ऐसे टेस्ट जहां इतना कुछ दांव पर लगा हो, यह सही नहीं है। (Koretz, 2017) विद्यार्थियों के टेस्ट लेने के लगातार बढ़ रहे ट्रेंड ने स्कूली शिक्षा को नुकसान पहुंचाया है। (Hout & Elliott, 2011)। लेकिन अन्य लोगों का मत है कि ज्यादा संख्या में टेस्ट लेना ज़रूरी है क्योंकि इसे शैक्षणिक और आर्थिक परिणामों में सुधार किया जा सकता है। (World Bank, 2018; Hanushek and Woessmann, 2014)

- ऐसी स्कूली व्यवस्था के छात्र, जहां स्थानीय स्वायत्तता के साथ बाहर से इम्तिहान देने की सुविधा है, वे अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। (Woessman, 2018)

- इसके उलट, बर्गबॉर एट अल (2018) की एक समीक्षा में सामने आया कि बिना टेस्टिंग के स्वायत्तता का नतीजा होता है टेस्ट में खराब प्रदर्शन। जिसका मतलब ये है कि अभिभावकों की ओर से सोच- समझकर की गई मांग ही असली अंतर ला सकती है।

ब्राज़ील के औसत PISA स्कोर में सुधार (2000-2009)

4% **रीडिंग में**
(वर्ष 2000 में 396 से 2009 में 412)

8% **गणित में**
(2003 में 356 से 2009 में 386)

3% **विज्ञान में**
(2006 में 390 से 2009 में 405)

OECD, 2011

केस स्टडी

ब्राज़ील में शैक्षणिक सुधार

ब्राज़ील ने पिछले 15 सालों में एक के बाद एक कई शैक्षणिक सुधारों के स्कूलों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ पढ़ने और सीखने को बढ़ावा दिया है।

- देश के राष्ट्रीय आंकलन के लिए PISA को मानदंड बनाया गया और साल 2000 से इसमें सराहनीय सुधार देखने को मिला है।

- साल 2005 में राष्ट्रीय परीक्षा के तहत हर विद्यार्थी का आंकलन करने की शुरुआत के बाद से अब काफी बढ़िया नतीजे मिल रहे हैं। साथ ही सरकार, मीडिया, और सिविल सोसायटी ग्रुप्स ने भी इन नतीजों का काफी ज़ोर-शोर से प्रचार किया।

- 2005 में बुनियादी शिक्षा विकास सूचकांक की शुरुआत की गई। इसके तहत अभिभावक देश के PISA स्कोर के साथ 10 अंकों के स्केल पर स्कूल की उपलब्धि और उन्नति की तुलना कर सकते हैं। (*ibid*)

- ब्राज़ील ने अपने स्कूलों की फंडिंग, शैक्षणिक ज़रूरतों के साथ टीचरों की तनख्वाह और बोनस में भी सुधार किया। (OECD, 2015)

- 12 साल की स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किया गया। पाठ्यक्रम को दोबारा डिज़ाइन करके स्कूल के घंटों को बढ़ाया गया। (*ibid*)

- इन सुधारों से जवाबदेही बढ़ी। खासकर ब्राज़ील के सबसे गरीब राज्यों में। (OECD, 2011)

2

शिक्षा क्षेत्र में सरकारी पहल*

*यहां शामिल किए गए कदमों की सूची पूरी नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों ने यहां बताए गए कामों के अलावा भी शिक्षा क्षेत्र में ढेरों काम किए हैं। इस क्षेत्र के जानकारों के साथ बातचीत के आधार पर उन कदमों का चुनाव किया है जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ट्रेनिंग, डेटा, सुधार कार्यक्रमों जैसे बृहद कार्यक्रमों के मामले में ठाए गए हैं और हमारे विषय के मुताबिक इनोवेटिव भी हैं।

यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+)

- एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम जो आगे चलकर रियल टाइम डेटा इकट्ठा करेगा।
- दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा MIS

18 लाख
स्कूल

85 लाख
टीचर

25 करोड़
विद्यार्थी

28
राज्य

08
केंद्र शासित प्रदेश

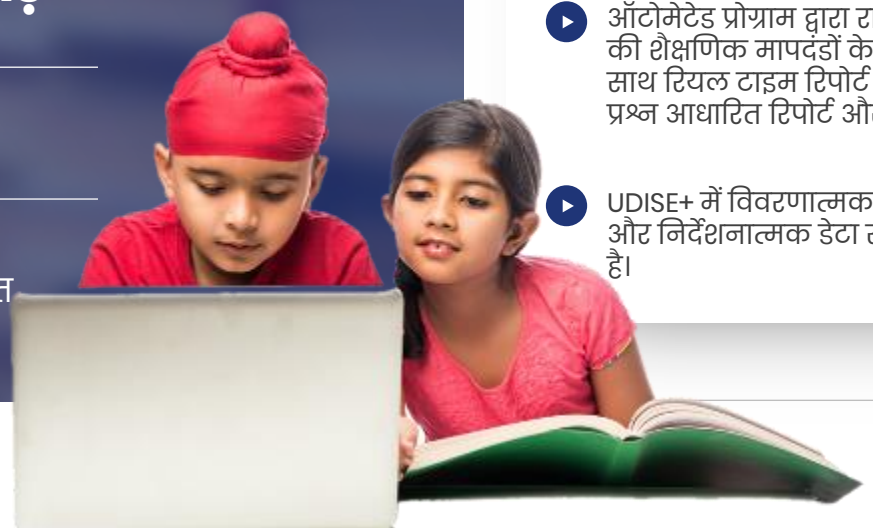

UDISE+ की विशेषताएं

UDISE+ की परिकल्पना, UDISE की सीमाओं को ध्यान में रखकर इसे और बृहद रूप देने की दृष्टि से की गई है। विभिन्न हितधारकों और जानकारों के साथ व्यापक बात-चीत के बाद इसे अमल में लाया गया है। UDISE+ बुकलेट, 2019 के अनुसार इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- DCFs का पुनर्गठन कर डेटा की ऑनलाइन अपडेटिंग को संभव बनाया गया ताकि इसका सही से पता लगाया जा सके।
- UDISE+ को NIC के सर्वर पर होस्ट किया गया है, जिस पर इसकी पूरी निगरानी की ज़िम्मेदारी है।
- इन्टीग्रेटेड जियो-स्पेशल डेटाबेस के साथ UDISE+ डेटा, जिससे GIS स्कूल मैपिंग की जा सकती है।
- इस डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए UDISE+ में जानकारी को थर्ड पार्टी ऐप द्वारा सत्यापित किए जाने की भी व्यवस्था है।
- ऑटोमेटेड प्रोग्राम द्वारा राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की शैक्षणिक मापदंडों के आधार पर डेटा समीक्षा के साथ रियल टाइम रिपोर्ट दी जाएगी। साथ ही इसमें प्रश्न आधारित रिपोर्ट और चार्ट का भी प्रवाधान है।
- UDISE+ में विवरणात्मक, जांच, पूर्वानुमान और निर्देशनात्मक डेटा समीक्षा की व्यवस्था है।

UDISE की सीमाएं और UDISE+ की आवश्यकता (UDISE+ booklet, 2019)

- यह एक ऑफलाइन डेटा कलेक्शन सिस्टम है जिसमें डेटा की क्वालिटी, सत्यता, और सामयिकता प्रभावित होती है।
- ऑडिट ट्रेल न होने के कारण जवाबदेही की कमी
- सभी श्रेणि के स्कूलों के लिए सिंगल डेटा कलेक्शन फॉर्म (DCF) के कारण अव्यवस्था और असंगतता
- UDISE डेटा का सीमित सत्यापन और पुनर्विचार के लिए सत्यापित डेटा की समीक्षा करने की व्यवस्था नहीं
- अत्याधिक समय और समन्वयन के कारण NIEPA के लिए UDISE का निरीक्षण करना मुश्किल हो गया। क्योंकि देश भर में बढ़ते स्कूली की संख्या को देखते हुए इसके पास ज़रूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर, संसाधन और निपुणता नहीं थी।
- कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में डेटा कलेक्शन सॉफ्टवेयर के अलग-अलग वर्ज़न का इस्तेमाल

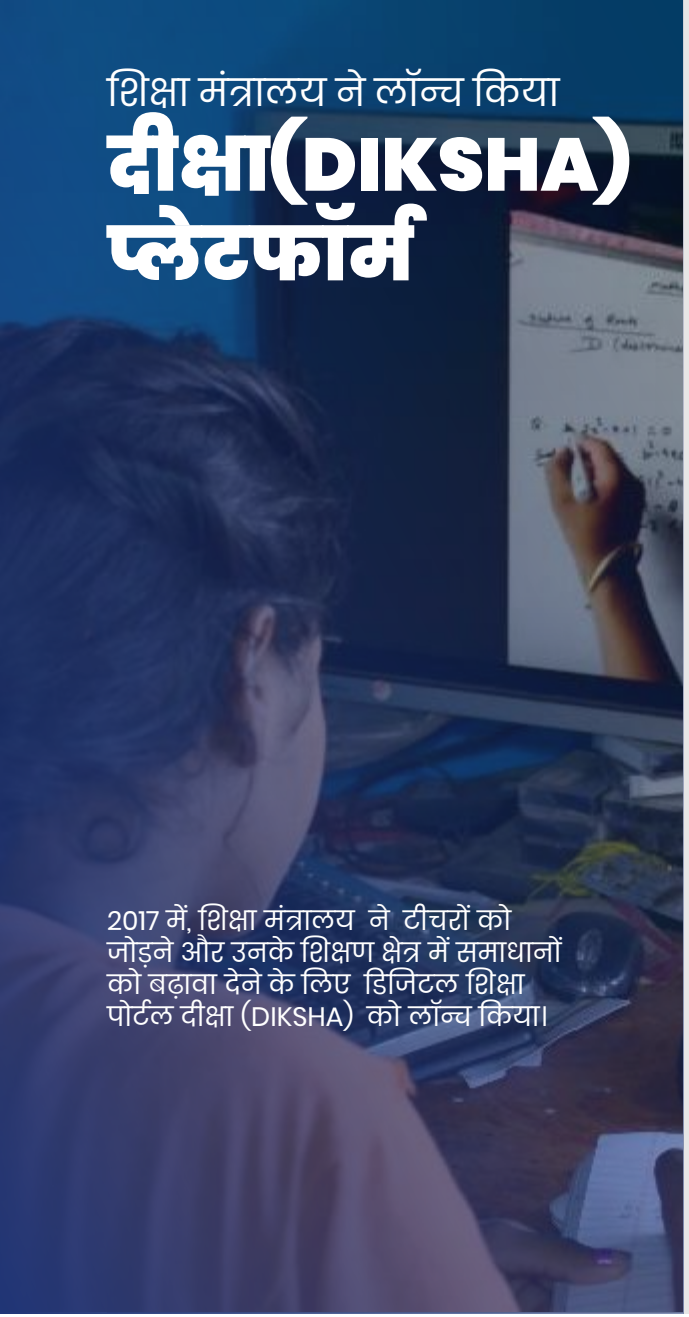

शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया

दीक्षा(DIKSHA) प्लेटफॉर्म

2017 में, शिक्षा मंत्रालय ने टीचरों को जोड़ने और उनके शिक्षण क्षेत्र में समाधानों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल शिक्षा पोर्टल दीक्षा (DIKSHA) को लॉन्च किया।

टीचर अपने पाठ्यक्रम संबंधी डिजिटल कॉन्टेन्ट बना, अपलोड और देख सकते हैं। साथ ही वे अपने विद्यार्थियों को सिखाने (और एकाग्रता बढ़ाने)के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

कक्षा 9 और 10 के लिए QR-कोड वाली किताबें लाईं गईं। ये QR कोड्स किताबों में जानकारों द्वारा बताई गई सख्त जगहों पर बने थे।

DIKSHA पर फोकस

- DIKSHA का उद्देश्य है देश भर के टीचरों को आपस में जोड़कर एक ऐसा मंच उपलब्ध करवाना जहां वे शैक्षणिक सामग्री बनाकर शेयर और सत्यापित कर सकते हैं।
- इस प्लेटफॉर्म पर टीचरों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी हैं। यानि एक ही जगह पर टीचरों को उनकी ज़रूरत की सारी सामग्री मिल सकती है।
- हालांकि इसकी शुरुआत टीचरों को ध्यान में रखकर की गई थी, लेकिन DIKSHA का इस्तेमाल सिर्फ टीचरों तक सीमित नहीं है। कोई भी भारतीय नागरिक अपने ईमेल एड्रेस के साथ इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद सामग्री देख सकता है।(Ramanujam, 2019)
- QR कोड वाली किताबें जिन्हें एनजाइज़्ड टेक्स्टबुक या ETBs भी कहा जाता है, विद्यार्थियों को सहूलियत देती हैं कि वे इंटरनेट वाले स्मार्टफोन से डिजिटल कॉन्टेन्ट को प्राप्त कर सकें।
- हर QR कोड DIKSHA-संबंधित कॉन्टेन्ट मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। यह कोई एनिमेशन, वीडियो या पहेली कुछ भी हो सकता है। ताकि विद्यार्थी को किसी विशेष कॉन्सेप्ट को सीखने में मदद मिल सके। (Ramanujam, 2019)
- ETBs से सीखने में दिलचस्पी बढ़ती है और विद्यार्थियों में खुद सीखने की आदत को बढ़ावा मिलता है। (The Hindu, 2020)

राज्यों द्वारा अपनाई गई ETBs की एक झलक

- आंध्र प्रदेश में कक्षा 6 से 10 के लिए अंग्रेज़ी और तेलुगू में ETBs का इस्तेमाल किया जाएगा। इस काम के लिए 70 लाख से भी ज्यादा किताबें छापी जा रही हैं।
- महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में क्रमश: कक्षा 1 से 10 और कक्षा 1 से 8 तक सभी विषयों के लिए ETBs अपनाया जा रहा है। (*ibid*)
- 2018 में तमिलनाडु में कक्षा 1,6 और 9 के लिए QR कोड वाली किताबों की शुरुआत की गई। (Ramanujam, 2019)
- केरल सरकार ने भी कक्षा 8 से 12 के लिए 2021 से ETBs की शुरुआत करने की योजना बनाई है। (The Hindu, 2020).

शिक्षा मंत्रालय का

निष्ठा (NISHTHA) प्रोग्राम

स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय पहल (NISHTHA)

(2019-20 में समग्र शिक्षा के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना)

इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग के ज़रिए प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई के नतीजे सुधारने के लिए एक राष्ट्रीय योजना

उद्देश्य

- टीचरों को प्रेरणा और संसाधन उपलब्ध करवाएं जाएं ताकि वे बच्चों को विवेचनात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रोत्साहन और बढ़ावा दें जिससे उनकी पढ़ाई के नतीजे बेहतर हो सकें। (PIB, 2019)
- संचालकों को पढ़ाई के नतीजों, स्कूल आधारित परीक्षा, विद्यार्थी केंद्रित अध्यापन, शिक्षा क्षेत्र में नए कदमों, बच्चों की अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अध्यापन के विभिन्न तरीकों आदि के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। (*ibid*)
- इसके साथ ही इस क्षमता निर्माण पहल के अंतर्गत ट्रेनिंग, निगरानी और सपोर्ट मकैनिज़्म के लिए एक MIS भी जोड़ा जाएगा। (NISHTHA website, 2019)
- यह ट्रेनिंग सीधे 33,120 की रिसोर्स पर्सन्स (KRPs) द्वारा दी जाएगी। इन KRPs को NCERT, NIEPA, केंद्रीय विद्यालय संगठन, सीबीएसई, एनजीओ आदि द्वारा चिन्हित 120 नेशनल रिसोर्ट पर्सन्स द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। (Livemint, 2019)

कवरेज

सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार NISHTHA का उद्देश्य है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 42 लाख प्रतिभागियों का क्षमता निर्माण करना। इनमें शामिल हैं:

- सभी सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर के टीचर और प्रधानाचार्य
- स्टेट काउंसिल्स ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) की अध्यापक मंडली के सदस्य
- ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIETs)
- ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स (BRCs) और क्लस्टर रिसोर्ट सेंटर्स (CRCs) के अधिकारी और रिसोर्स पर्सन्स

नीति (NITI) आयोग ने लॉन्च की

साथ- ई (SATH-E)

सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन

- स्कूली शिक्षा में व्यवस्थात्मक सुधार और रूपांतरण के ज़रिए मॉडल राज्य बनाने का लक्ष्य ।
- 30 महीनों की अवधि में चरणों में लागू किया गया प्रोग्राम। 2020 में पूर्ण होगा।

SATH-E प्रोग्राम

- नीति (NITI) आयोग ने SATH-E प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि 3 ऐसे मॉडल राज्यों की पहचान की जा सके जो भारत में स्कूली शिक्षा के लिए संभावित बेंचमार्क बन सकते हैं।
- चैलेंज मेथड पर आधारित त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया से गुज़रने वाले 16 राज्यों में से तीन राज्य- झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडीशा का चुनाव किया गया, जहां इस प्रोजेक्ट को लागू किया जा सके। (PIB, 2018)
- एक त्रिपक्षीय करार के ज़रिए इन तीन राज्यों में SATH-E लागू किया गया। जिसमें राज्य सरकारें, नॉलेज पार्टनर बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के साथ पिरामल फाउंडेशन और नीति (NITI) आयोग शामिल हैं। (NITI Aayog Annual Report, 2019-2020)
- नेशनल स्टीयरिंग ग्रुप ने SATH-E प्रोजेक्ट की समीक्षा में पाया कि इस प्रोग्राम के लागू होने के बाद से इन तीन राज्यों में शिक्षा के परिणामों में सुधार आया है। (*ibid*)

SATH-E के तहत कुछ महत्वपूर्ण सुधार

(NITI आयोग वार्षिक रिपोर्ट, 2019-2020

- बड़े पैमाने पर शिक्षा सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत
- स्कूलों को साथ मिलाकर उनका एकीकरण करना
- टीचरों का चयन और व्यवस्थानुसार नियुक्ति
- संपूर्ण व्यवस्था में प्रशिक्षण और निरीक्षण कार्यक्रम
- मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (MIS) को मज़बूती देना
- ज़िलावार स्कोरकार्ड के जरिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा
- स्कूल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम

दिल्ली सरकार द्वारा शैक्षणिक सुधार

2015 से दिल्ली सरकार ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं।

- इन सुधारों में स्कूली शिक्षण में विभिन्न हितधारकों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त प्रयासों की व्यवस्था है। जिनका लक्ष्य विशेष रूप से विद्यार्थी, प्रधानाचार्य और शिक्षक, स्कूल कम्युनिटी और बुनियादी ढांचे पर है।

- यहां हम 2018 से केवल विद्यार्थियों से संबंधितप्रयासों पर ध्यान दे रहे हैं।

विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में सुधार

मिशन बुनियाद

इसकी शुरुआत 2018 में की गई। इसका उद्देश्य था दिल्ली में स्थित राज्य सरकार और नगरपालिका स्कूलों में कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई का स्तर सुधारना। (Govt. of Delhi, 2018)। पढ़ाई के स्तर में बेहतरीन सुधार आने के बाद इसे 2019 में दोबारा लागू किया गया। (Baruah, 2019)।

खुशियों वाला पाठ्यक्रम

दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों के नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के पारंपरिक शैक्षिक पाठ्यक्रम में ध्यान, मूल्य आधारित शिक्षा और मेन्टल एक्सरसाइज़ जैसे विषयों का समावेश कर समग्र शिक्षण पर ध्यान (Govt. of Delhi, 2018)।

उद्यमशील मानसिकता के विकास के लिए पाठ्यक्रम

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों में उद्यमशीलता के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता और जानकारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पाठ्यक्रम लागू किया गया। यह कार्यक्रम एक्टिविटी आधारित पाठ्यक्रम पर आधारित है जो कि SCERTद्वारा विकित किया गया है। (Education Times, 2019) साथ ही इसमें बच्चों को दिल्ली के उद्यमियों के साथ बात-चीत का मौका भी मिलता है। (India Today, 2019)

सुधारों के लिए अनुकूल स्थितियां

- शिक्षा क्षेत्र के बजट में बढ़ोत्तरी; 2019-20 के दिल्ली सरकार के बजट का 26% हिस्सा इस क्षेत्र के लिए आबंटित किया गया। India Today, 2019)
- 2015-18 के बीच स्कूलों और सहायक ढांचे का बड़े पैमाने पर निर्माण (Outlook, 2019)
- समुदाय से जुड़ने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों का पुनर्नियोजन (The Hindu, 2020)
- टीचर्स के लिए प्रशिक्षण, सहायता और करीयर में उन्नति के ज्यादा मौके (*ibid*)

मिशन प्रेरणा

उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना

1.6 लाख स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना

बुनियादी शिक्षण कौशल पर ध्यान

विद्यार्थियों का लर्निंग आउटकम

मुख्य लक्ष्य

मार्च 2022 तक कक्षा 1 से 5 में बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करना

- ASER सर्वे- जिसमें भाषा और गणित में बच्चों के ज्ञान का आंकलन किया जाता है, इसमें उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन हमेशा से ही खराब रहा है।
- मिशन प्रेरणा की परिकल्पना है उत्तर प्रदेश में खराब लर्निंग आउटकम की समस्या को सुलझाना। Gupta (2020) में आलेखित मिशन प्रेरणा की प्रक्रिया।

प्रेरणा लक्ष्य

'प्रेरणा लक्ष्य' यानि कक्षावार लर्निंग के लक्ष्य का आंकलन। इसे हिंदी और गणित के लिए भी स्थापित किया गया है। इस लक्ष्य में अक्षरों की पहचान, पढ़ने की गति, पाठ की समझ, अंकों की पहचान और मूलभूत अंकगणितीय कार्य आदि शामिल हैं।

प्रेरणा सूचि और प्रेरणा तालिका

कक्षा में हर बच्चे की प्रगति को चिन्हित कर उन पर नज़र रखना। टीचरों को प्रेरणा सूचि और प्रेरणा तालिका उपलब्ध कराई जाएगी।

अक्षर

प्रेरणा घोषणा

जब कोई ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) को पूरा भरोसा हो जाए कि उनके ब्लॉक के विद्यार्थी प्रेरणा लक्ष्य के लिए तैयार हैं, तो वह प्रेरणा घोषणा के ज़रिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा अपने ब्लॉक के बच्चों के लर्निंग लेवल का आंकलन करने के लिए अपने ब्लॉक को खुद ही नामांकित कर सकता है।

प्रेरणा ब्लॉक

ऊपरी आंकलन के नतीजे आने के बाद इस ब्लॉक को प्रेरणा ब्लॉक दल के रूप में नामित किया जाएगा।

प्रेरक ब्लॉक

जब ब्लॉक के सभी स्कूलों के **80%** विद्यार्थी प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लेंगे

प्रेरक ज़िला

जब ज़िले के सभी ब्लॉक प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे

प्रेरक खंड

जब सभी ज़िले प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे

प्रेरक प्रदेश

3
कोविड-19 के दौर में शिक्षा

कोविड-19 और दुनियाभर में स्कूल बंदी

कोविड-19 की वजह से बंद स्कूलों का वैश्विक निरीक्षण

(Source: Humandata.org, as of 20th July 2020)

कोविड-19 के कारण बंद स्कूलों का वैश्विक निरीक्षण

168 देशों में देशव्यापी बंद

दुनिया भर में 1.2 अरब विद्यार्थी प्रभावित

दाखिला लेने वालों में से कुल **71%** विद्यार्थी प्रभावित

शिक्षा पर कोविड-19 का संभावित प्रभाव

वर्ल्ड बैंक (2020) द्वारा महामारी के कारण स्कूल बंदी से स्कूली शिक्षा पर पड़नेवाले संभावित प्रभावों का रेखांकन

- स्कूलबंदी की वजह से जहां छोटी अवधि में पढ़ाई का नुकसान तय है, वहीं ज्यादा दिनों तक स्कूल बंद रहने का नतीजा लंबे समय में मानवीय पूंजी के नुकसान और आर्थिक मौकों की कमी के रूप में सामने आ सकता है।
- शिक्षा प्रभावित होने से सबसे ज्यादा नुकसान उन देशों को होगा जहां की शिक्षा व्यवस्था काफी कमज़ोर है, पढ़ने/सीखने की दर कम है, ड्रॉपआउट दर काफी ज्यादा है और झटके सहन करने की क्षमता कम है।
- स्कूल बंदी का सबसे ज्यादा नुकसान अति संवेदनशील बच्चों पर पड़ेगा क्योंकि उनके पास घर पर सीखने के मौके काफी होते हैं।
- स्कूली भोजन के अभाव में गरीब परिवारों के पास इतने संसाधन नहीं होंगे कि वे बच्चों की ज्यादा समय तक देखभाल कर सकें या उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार दे सकें।

देश इस समस्या से कैसे उबर रहे हैं ?

- ज्यादातर देशों ने रिमोट या डिस्टेंस लर्निंग और अन्य शिक्षण संसाधनों को अपनाकर पढ़ाई के नुकसान को कम करने का प्रयास किया है। (World Bank, 2020)
- इसके तहत शिक्षा तकनीक या EdTech जो कि पिछले कुछ सालों से उभर रहा था, उसका फायदा उठाया गया। लेकिन रिमोट लर्निंग संसाधनों की एक समान उपलब्धता की चुनौती लगातार बनी हुई है।

भारत में कोविड-19 के कारण मिला ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा; लेकिन उपलब्धता की चुनौती बरकरार

कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने पर दुनिया भर के 50 से अधिक देशों ने इंटरनेट, टीवी या रेडियो के ज़रिए डिस्टेंस लर्निंग की व्यवस्था लागू करने की घोषणा की।

भारत

- लॉकडाउन के कारण हुई स्कूल बंदी की का असर स्कूलों के शैक्षणिक सत्र, बोर्ड इम्तिहान की तारीख और अगली साल होने वाली कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं पर पड़ा है।
- पढ़ाने के उद्देश्य से तकनीक के इस्तेमाल पर कोई गंभीर प्रयास नहीं किए जा रहे।
- स्वयं (SWAYAM) या ई-पाठशाला जैसे ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल्स के साथ इंटरनेट आधारित पारंपरिक डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स ही फिलहाल केंद्र में हैं।

ऑनलाइन लर्निंग की चुनौतियां

- इस दौर में जबकि दुनिया भर के देश रिमोट लर्निंग नीति की ओर बढ़ रहे हैं ऐसे में ऑनलाइन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग का सबसे आम तरीका बनकर उभर रहा है। हालांकि इन सबके बीच इंटरनेट की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है।
- निम्न और निम्न मध्यम आय वर्ग के **40%** से भी कम घरों में इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध है। (Carvalho & Hares, 2020)
- टेक आधारित ब्रिजिंग सल्यूशन्स की पहुंच सीमित है। खासकर सरकारी और प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के बीच (Choudhary, 2020)
- अगर महामारी के साथ आर्थिक संकट का दौर भी आता है तो इन एडटेक समाधानों की पहुंच और भी सीमित हो जाएगी। खासकर निम्न आय वर्ग के घर इंटरनेट पैकेज नहीं खरीद पाएंगे।

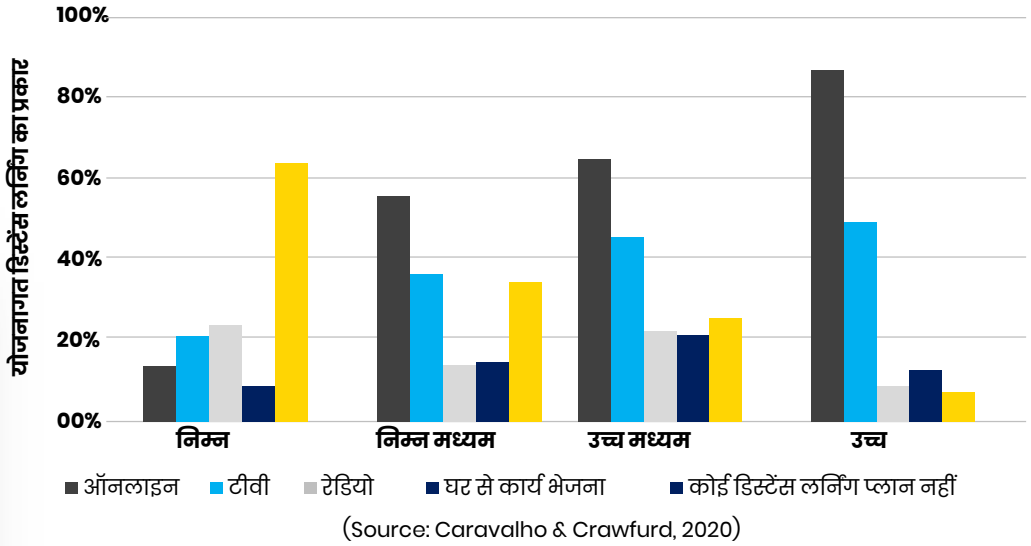

(Source: Caravalho & Crawfurd, 2020)

किसी देश के डिस्टेंस लर्निंग योजना की घोषणा करने या न करने का संबंध काफी हद तक उसकी आय से है

- उच्च आय वाले 85% देशों ने डिस्टेंस लर्निंग योजना घोषित की। जबकि निम्न आय वर्ग के देशों में से महज़ 15% ने इसका एलान किया।
- सब-सहारन अफ्रीका में बड़े पैमाने पर बंदी का एलान करने वाले 30 से भी ज्यादा देशों में से महज़ 4 देशों ने प्राथमिक और माध्यमिक काओं के लिए डिस्टेंस लर्निंग योजना की घोषणा की है। इनमें केन्या, सेनेगल, सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

स्कूल बंदी के दौरान मिड-डे मील की उपलब्धता में पड़ा व्यवधान दूर करना

मिड-डे मील (MDM) योजना से देश भर में 11.5 करोड़ विद्यार्थियों को लाभ मिलता है।

सभी प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय इकाई के स्कूल, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के स्कूल और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट (NCLP) स्कूल जिन्हें श्रम मंत्रालय चलाता है, में पढ़ने वाले विद्यार्थी MDM योजना के पात्र हैं।

कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने के चलते, केंद्रीय मंत्रालय ने स्कूल बंदी की अवधि के दौरान, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पात्र विद्यार्थियों को मिड-डे मील के तौर पर पका हुआ भोजन या खाद्य सुरक्षा भत्ता देने को कहा है।

मिड-डे मील में पड़ा व्यवधान और कुछ राज्यों द्वारा किए गए प्रयास (मार्च-अप्रैल 2020)

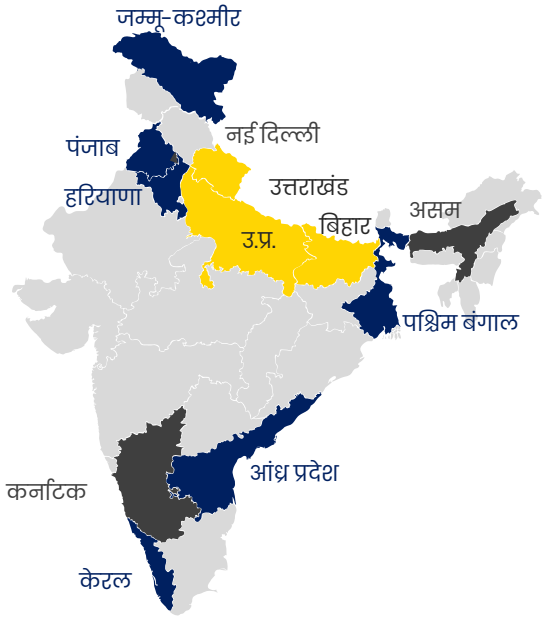

मिड-डे मील के वितरण का क्रियान्वन

- मिड-डे मील के लिए सूखे राशन के वितरण के लिए कई राज्य सरकारों ने टीचरों, आंगनवाड़ी कर्मचारियों, मजदूरों और स्वयंसेवकों की सहायता ली।
- रिपोर्ट्स के मुताबिक पके हुए मिड-डे मील की व्यवस्था कर पाना राज्यों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा।

कोविड-19 लॉकडाउन के कारण हुई शैक्षणिक उथल-पुथल पर भारतीय राज्यों की प्रतिक्रिया

केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

- कोविड-19 के कारण हुई स्कूल बंदी के दौरान घर पर शिक्षा देने के लिए वर्चुअल क्लास, फोन ऐप और वेब आधारित शैक्षणिक पोर्टल्स के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग सुविधा उपलब्ध करवाना राज्यों की प्रमुख नीति रही।
- मई 2020 में वित्त मंत्री ने कई प्रकार से डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ई-विद्या प्रोग्राम का एलान किया। इसके तहत अन्य सुविधाओं के अलावा कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी कक्षाओं के लिए एक विशेष टीवी चैनल की व्यवस्था की गई। (Times of India, 2020)
- उपलब्धता की समस्या को समझते हुए राज्यों ने रेडियो और टीवी आधारित प्रोग्राम्स के साथ एसएमएस और IVRs के ज़रिए भी अपने लर्निंग कॉन्टेन्ट उपलब्ध करवाए।
- कई राज्यों में व्हाट्सएप एक महत्वपूर्ण लर्निंग माध्यम बन गया है। जहां टीचर्स वॉइस और टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए बच्चों और उनके अभिभावकों से जुडते हैं। इसके तहत बच्चों के इम्तिहान भी व्हाट्सएप पर ही लिए जा रहे हैं।

ढांचागत समस्याओं के कारण एडटेक का प्रभाव सीमित

- बिजली, कंप्यूटर और स्मार्टफोन की उपलब्धता के मामले में भारत के अलग-अलग राज्यों के बीच बड़ी असमानता देखने को मिलती है।
- NSSO रिपोर्ट ऑन एजुकेशन (2017-18) के मुताबिक भारत के सिर्फ 24 % घरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन 5 से 24 साल की उम्र के सदस्यों वाले घरों में से महज़ 8% घर ऐसे हैं जहां इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर दोनों हैं।
- इंटरनेट की उपलब्धता में बड़ी असमानता- जहां 67% पुरुषों के पास इंटरनेट उपलब्ध है वही महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा 33% है। (Kala, 2019)
- ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए एक विशेष प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है जो कि मौजूदा टीचर ट्रेनिंग पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। इस कारण बड़ी संख्या में टीचर ऑनलाइन पढ़ाई कराने में असमर्थ हैं।
- अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों के लिए ऑनलाइन शिक्षा को अपनाना काफी आसान है बजाय भाषाई स्कूलों के। भारत के कुल स्कूलों की संख्या में बड़ा हिस्सा भाषाई स्कूलों का है। (Kalra, 2020)

स्कूल बंदी से उबरने के लिए किस तरह से निजी स्कूलों ने लिया एडटेक का सहारा ?

- राज्यों की तरह ही देश के कई निजी स्कूलों ने भी ऑनलाइन या वर्चुअल क्लास का रुख किया। ये क्लास गूगल मीट, ज़ूम, वेबएक्स या अन्य वेब आधारित प्लेटफॉर्म्स से संचालित होती हैं।
- रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूलों द्वारा वर्चुअल क्लास के ज़रिए उपलब्ध करवाई जा रही सामग्री की गुणवत्ता के लिहाज़ से देखा जाए, तो इनमें बड़ा अंतर है। कुछ स्कूल जहां व्यवस्थित क्लास लेते हैं तो वहीं कुछ महज़ पावर प्वाइंट प्रेज़ेन्टेशन के ज़रिए बच्चों से ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं।
- निजी स्कूलों के टीचर्स डिजिटल संसाधनों की सीमित उपलब्धता के बीच बच्चों और नके अभिभावकों से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप का सहारा ले रहे हैं।

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

पढ़ाई के नुकसान को कम करने के लिए राज्यों ने लिया डिजिटल, टीवी, रेडियो का सहारा; कुछ केस स्टडीज़ *

मध्य प्रदेश

डिजीलीप **डिजिटल लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम**

इस प्रोग्राम के तहत कक्षा 1 से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को व्हाट्सएप के ज़रिए सभी प्रमुख विषयों की पढ़ाई करने का मौका मिलता है। व्हाट्सएप की रचना इस प्रकार की गई हैकि इस प्रोग्राम के क्रियान्वन में मदद मिल सके।

सीएम राइज़

DIKHSA के ज़रिए डिजिटल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम

टॉप पेरेंट ऐप

इस ऐप में शुरुआती कक्षाओं में पढ़नेवाले बच्चों के लिए तीन अन्य उच्च गुणवत्ता वाली एडटेक ऐप्स का शुमार है। इससे अभिभावकों को बच्चे के प्रदर्शन पर नज़र रखने और उनकी पढ़ाई में योगदान देने में मदद मिलती है।

रेडियो स्कूल

ऑल इंडिया रेडियो के साथ मिलकर शुरू किए गए इस राज्यव्यापी कार्यक्रम को हर रोज़ एक घंटे चलाया जाता है। इसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए शैक्षणिक प्रोग्राम और कहानियां शामिल होती हैं।

डीडी एमपी- क्लासरूम

डीडी एमपी के साथ मिलकर टेलीकास्ट किए जाने वाले इस विशेष शैक्षणिक टीवी कार्यक्रम 'क्लासरूम ' को कक्षा 10 और 12 के लिए दिखाया जाता है। यह प्रोग्राम दिन में दो बार और सप्ताह के पांच दिन दिखाया जाता है। (Times of India, 2020)

उत्तर प्रदेश

गुप्ता (2020) के आलेख के अनुसार उत्तर प्रदेश ने इन घटकों के साथ एक बहुआयामी तरीका अपनाया है :

ई-पाठशाला

राज्य सरकार ई-पाठशाला के माध्यम से शिक्षण सामग्री को स्मार्टफोन के जरिए विद्यार्थियों तक पहुंचा रही है। इस काम के लिए जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर मौजूदा व्हाट्सएप ग्रुप्स का सहारा लिया जा रहा है।

दीक्षा (DIKSHA)

दीक्षा प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए कॉन्टेन्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध तीन कॉन्टेन्ट श्रेणियों मे टिक-टैक लर्न, खान अकैडमी और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन का कॉन्टेन्ट शामिल है।

टॉप पेरेंट ऐप

शुरुआती कक्षाओं के बच्चों के लिए टॉप पेरेंट ऐप और एडटेक की तीन हाई क्वालिटी ऐप जैसे चिंपल, मैथ मस्ती और बोलो- के इस्तेमाल को प्रोत्साहन किया जा रहा है।

डीडी- यूपी

जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है उनके लिए डीडी-यूपी, ऑल इंडिया रेडियो और कम्युनिटी रेडियो के ज़रिए शिक्षम सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

केरल

केरल सरकार के प्रयासों का समन्वयन केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नॉलजी ऑफ एजुकेशन (KITE)के ज़रिए का जा रहा है। जनॉय जोज़ पी (2020) राज्य के तरीके को इस प्रकार आलेखित करते हैं :

ऑनलाइन प्रशिक्षण

राज्य के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ानेवाले **81,000 शिक्षकों के लिए** ऑनलाइन ट्रेनिंग का आयोजन ताकि उनके डिजिटल कौशल को बढ़ाया जा सके।

अवदिकाल संतोषांगल (छुट्टियों की शुभकामनाएं)

एक ऐसा प्रोग्राम जिसके तहत राज्य के समग्र रिसोर्स पोर्टल पर ऑनलाइन शैक्षणिक मनोरंजन की सामग्री प्रदर्शित की गई। इसके पहले चरण को कक्षा 5 से 9 तक के विद्यार्थियों पर केंद्रित रखा गया।

अक्षर वृक्षम (अक्षरों वाला वृक्ष)

इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों द्वारा रचित कहानियों, कविताओं और लेखों को इकट्ठा करके संवारा और छापा जाता है। सबसे बेहतरीन एंट्रीज़ का चुनाव SCERT द्वारा किया गया, जिसे बाद में एक किताब के रूप में छापा जाएगा।

KITE का विक्टर टीवी

KITE के विक्टर टीवी पर विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। यह चैनल DTH पर उपलब्ध है। इसके साथ ही विक्टर टीवी पर टीचरों की सुविधाजनक ट्रेनिंग के लिए MOOC भी उपलब्ध है।

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

*ये ज़रूरी नहीं कि जिन राज्यों का यहां जिक्र किया गया है , वैसी ही शिक्षण सुविधा की व्यवस्था अन्य भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भी की हो। कस स्टडीज़ सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध जानकारी और संबंधित हितधारकों से बातचीत के आधार पर तैयार की जाती हैं। इसे राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 के दौर में शिक्षा क्षेत्र में उठाए गए कदमों का संपूर्ण चित्रण नहीं माना जाना चाहिए।

References

- Azam, M. & Kingdon, G. (2015). *Assessing teacher quality in India.* Journal of Development Economics. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304387815000802?via%3Dihub
- Andreson, J. & Shendruk, A. (2019, December 3). *The best students in the world, charted.* Quartz. https://qz.com/1759506/pisa-2018-results-the-best-and-worst-students-in-the-world/
- (2019, December 15). *Andhra Pradesh govt to enact law on education medium.* Economic Times. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/andhra-pradesh-govt-to-enact-law-on-education-medium/articleshow/72668836.cms?from=mdr
- Ahmad, S. (2019, March 25). *AAP govt fixed a broken state schooling system, but glitches remain.* Outlook India. https://www.outlookindia.com/magazine/story/india-news-a-for-aaplause-b-for-boos/301297
- Aslam, M., & Kingdon, G. (2011). What can teachers do to raise pupil achievement? *Economics of Education Review,* 30(3), 559–574.
- Bhattacharjea, S., Wadhwa, W., & Banerji, R. (2011). *Inside primary schools. A study of teaching and learning in rural India.* ASER. http://img.asercentre.org/docs/Publications/Inside_Primary_School/Report/tl_study_print_ready_version_oct_7_2011. pdf
- Bruns, B., Evans, D. & Luque, J. (2012). *Achieving World-Class Education in Brazil: The Next Agenda.* The World Bank. https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1596/978-0-8213-8854-9
- Bergbauer, A. B., Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2018). *Testing* (No. w24836). National Bureau of Economic Research.
- Bandhopadhyay, D.M. (2015). *Present status of infrastructure facilities in schools in India: From national and state level perspective.* New Delhi: National University of Educational Planning and Administration.
- Beuchert, L., Humlum, M. K., Nielsen, H. S., & Smith, N. (2018). *The short-term effects of school consolidation on student achievement: Evidence of disruption?.* Economics of Education Review, 65, 31-47.
- Bordoloi, M. & Shukla, R. (2019). *School Consolidation in Rajasthan Implementation and Short-Term Effects.* Centre for Policy Research. https://cprindia.org/research/papers/school-consolidation-rajasthan-implementation-and-short-term-effects
- Baruah, S. (2019, February 1). *Delhi: Jump in math and reading levels after Mission Buniyaad.* Indian Express. https://indianexpress.com/article/education/delhi-year-end-assessment-of-classes-3-to-8-5563666/
- Barrett, A. et al. (2007). Initiatives to improve the quality of teaching and learning: a review of recent literature. Background paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report 2008 'Education for All by 2015: will we make it?'
- (2011). *Chapter 8, Brazil: Encouraging Lessons from a Large Federal System of Strong Performers and Successful Reformers in Education: Lessons from PISA for United States.* OECD. http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46581300.pdf
- Chetty, R., Friedman N. J., & Rockoff, J.E. (2014). *"Measuring the Impacts of Teachers II: Teacher Value-Added and Student Outcomes in adulthood".* American Economic Review, 104 (9): 2633-79.
- Chopra, R. (2016, May 29). *The exam factor: Why RTE's no-detention provision is on test.* Indian Express. https://indianexpress.com/article/education/right-to-education-detention-policy-hrd-ministry-2823782/
- Choudhary, R. (2020, April 16). *COVID-19 Pandemic: Impact and strategies for education sector in India.* Economic Times. https://government.economictimes.indiatimes.com/news/education/covid-19-pandemic-impact-and-strategies-for-education-sector-in-india/75173099

References

- Carvalho, S., & Hares, S. (2020, March 30). *More from Our Database on School Closures: New Education Policies May Be Increasing Educational Inequality.* Centre for Global Development. https://www.cgdev.org/blog/more-our-database-school-closures-new-education-policies-may-be-increasing-educational
- Caravalho, S., & Crawfurd, L., (2020, March 25). *School's Out: Now What?.* Centre for Global Development. https://www.cgdev.org/blog/schools-out-now-what
- Koretz, D. (2017). *The Testing Charade: Pretending to Make Schools Better.* United States of America: The University of Chicago Press Chicago and London
- (2019, April 8). *Delhi government to implement Entrepreneurship Mindset curriculum in 1,022 schools.* Education Times. https://www.educationtimes.com/article/65779767/70179183/Delhi-government-to-implement-Entrepreneurship-Mindset-curriculum-in-1022-schools.html#gsc.tab=0
- (2019, September 18). *Delhi govt's entrepreneurship curriculum to deal with joblessness, economic slowdown: Manish Sisodia.* India Today. https://www.indiatoday.in/education-today/news/story/delhi-govt-s-entrepreneurship-curriculum-to-deal-with-joblessness-economic-slowdown-manish-sisodia-1600321-2019-09-18
- (2019, February 27). *Delhi budget 2019-20: Highest share of 26% allocated to education sector.* India Today. https://www.indiatoday.in/education-today/news/story/-delhi-budget-2019-20-highest-share-of-26-allocated-to-education-sector-1466163-2019-02-27#:~:text=The%20government%20has%20allocated%2026,total%20budget%20to%20education%20sector.&text=Delhi%20budget%202019%2D20%20was%20announced%20by%20Manish%20sisodia%20at,total%20budget%20to%20education%20sector.
- *2015 and beyond: Delhi Education Revolution.* Directorate of Education, Government of NCT of Delhi. http://www.edudel.nic.in/welcome_folder/delhi_education_revolution.pdf
- (2015, November). *Education Policy Outlook: Brazil.* OECD. http://www.oecd.org/education/Brazil-country-profile.pdf
- (2018). *Education Statistics at a Glance.* Ministry of Human Resource Development, Department of School Education & Literacy Statistics Division, New Delhi https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-new/ESAG-2018.pdf
- Gove, A., & Dubeck, M. M. (2016). *Assess reading early to inform instruction, improve quality, and realize possibilities.* Annual review of comparative and international education, 81-88.
- Gertler, P., Heckman, J., Pinto, R., Zanolini, A., Vermeersch, C., Walker, S., Chang, S. M., & Grantham-McGregor, S. (2014, May 30). *Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica. Science (New York, N.Y.), 344*(6187), 998–1001. https://doi.org/10.1126/science.1251178
- Gupta, S. (2020, March 19). *Look beyond Adityanath's saffron robe. His govt is revolutionising UP's primary education.* The Print. https://theprint.in/opinion/look-beyond-adityanaths-saffron-robe-his-govt-is-revolutionising-ups-primary-education/383509/
- Gupta, S. (2020, April 16). *CM Adityanath's 5-step plan for UP students under lockdown that other states can emulate.* The Print. https://theprint.in/opinion/cm-adityanaths-5-step-plan-for-up-students-under-lockdown-that-other-states-can-emulate/402610/
- Glewwe, P., Hanushek, E.A., Humpage, S., & Ravina, R. (2013). *Education Policy in Developing Countries. Chapter: School Resources and Educational Outcomes in Developing Countries: A Review of the Literature from 1990 to 2010.* University of Chicago Pressloui

References

- Hout & Elliott. (2011). National Research Council. (2011). *Incentives and test-based accountability in education.* National Academies Press.
- Hanushek, Eric & Schwerdt, Guido & Wiederhold, Simon & Woessmann, Ludger. (2014). *Returns to Skills around the world: evidence from PIAAC.* European Economic Review. 73. 10.1016/j.euroecorev.2014.10.006. (Hanushek, E., Schwerdt, G., Wiederhold, S., & Woessmann, L.)
- (2019, August 22). *HRD Ministry launches NISHTHA to train over 42 lakh teachers.* Livemint. https://www.livemint.com/news/india/hrd-ministry-launches-nishtha-to-train-over-42-lakh-teachers-1566450935178.html
- Ibid
- *The Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Bill, 2017*. Indian Parliament, Bill No. 166 of 2017. http://164.100.47.4/billstexts/lsbilltexts/asintroduced/166_2017_LS_Eng.pdf
- (2019, January 28). *India to participate in PISA in 2021.* Business Standard. https://www.business-standard.com/article/pti-stories/india-to-participate-in-pisa-in-2021-119012801243_1.html
- Ludwig, J., & Miller, D. L. (2007, February 1). *Does Head Start Improve Children's Life Chances? Evidence from a Regression Discontinuity Design.* The Quarterly Journal of Economics, Volume 122, Issue 1, Pages 159208, https://doi.org/10.1162/qjec.122.1.159
- Heckman, J. J. (2012). *Chapter: Case for Investing in Young Children.* Defending Childhood: Keeping the Promise of Early Education. New York: Teachers College Press https://books.google.co.in/books?hl=en&lr=&id=Jm7N_ME5K9gC&oi=fnd&pg=PA235&ots=F8TheIe3wE&sig=UwdFzKJjZSt5OlnUWRHnIE85NIE#v=onepage&q&f=false
- Jose, P. J. (2020, May 5). *KITE Corona and Kerala. The Hindu Business Line.* https://www.thehindubusinessline.com/specials/india-file/kite-corona-and-kerala/article31503987.ece
- Jha, S. (2020, May 8). *MP: State education department collaborates with Doordarshan to telecast educational programmes for class 10 and 12.* Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/mp-state-education-department-collaborates-with-doordarshan-to-telecast-educational-programmes-for-class-10-and-12/articleshow/75634213.cms
- Kidwai, H., Burnette, D., Rao, S., Nath, S., Bajaj, M., & Bajpai, N. (2013). *In-service teacher training for public primary schools in rural India findings from district Morigaon (Assam) and district Medak (Andhra Pradesh).*
- Karoly, L.A. et al. (1998). *Investing in our children: what we know and don't know about the costs and benefits of early childhood interventions.* Washington D.C.:RAND https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/1998/MR898.pdf
- Kaul, V., Bhattacharjea, S., Chaudhary, A. B., Ramanujan, P., Banerji, M., & Nanda, M. (2017). *The India Early Childhood Education Impact Study. New Delhi.* UNICEF.
- Kundu, P. (2020, May 5). *Indian education can't go online – only 8% of homes with young members have computer with net link.* Scroll. https://scroll.in/article/960939/indian-education-cant-go-online-only-8-of-homes-with-school-children-have-computer-with-net-link
- Kala, R.R. (2019, September 27). *High gender disparity among internet users in India.* Financial Express. https://www.financialexpress.com/industry/high-gender-disparity-among-internet-users-in-india/1718951/
- Kalra, S. (2020, May 4). *Lack of regional language content, infrastructure: Online education double trouble for hinterlands.* Indian Express. https://indianexpress.com/article/education/lack-of-regional-language-content-infrastructure-online-education-double-trouble-for-hinterlands-6360040/
- Kingdon, G.G. (2006). Teacher characteristics and student performance in India: a pupil fixed effects approach. *Global Poverty Research Group Working Paper 59* http://economics.ouls.ox.ac.uk/14026/1/gprg-wps-059.pdf

References

- (2018). Learning to realize education's promise. World Development Report. The World Bank. https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018
- Lee, M., Louis, K. S., & Anderson, S. (2012). Local education authorities and student learning: the effects of policies and practices. *School Effectiveness and School Improvement,* 23 (2), 133–158.
- Lloyd, C.B. & J. Young. (2009). *New Lessons: The Power of Educating Adolescent Girls,* Population Council. https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2009PGY_NewLessons.pdf
- Menon, S. (2014). *Language and literacy learning in early years: what should it look like?* Learning Curve, (22), 50-53.
- Menon, S., Krishnamurthy, R., Kutty, S., Apte, N., Basargekar, A., Subramaniam, S., & Modugala, M. (2017). *Literacy Research in Indian Languages (LiRIL): Research report of a Study of Literacy Acquisition in Kannada and Marathi* (2013-2016).
- National Education Policy, 2020. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- Muralidharan, K. & Prakash, N. (2017). *Cycling to school: increasing secondary school enrollment for girls in India.* American Economic Journal: Applied Economics, 9 (3): 321-50. DOI: 10.1257/app.20160004
- Mahapatra, S. K. (2016). Accessibility and Quality Education of Persons with Disabilities in India: An Open Schooling Perspective. https://www.researchgate.net/profile/Sukanta_Mahapatra2/publication/318387111_Accessibility_and_Quality_Education_of_Persons_with_Disabilities_in_India_An_Open_Schooling_Perspective/links/5966d3ba0f7e9b80917ffa5f/Accessibility-and-Quality-Education-of-Persons-with-Disabilities-in-India-An-Open-Schooling-Perspective.pdf
- M., Sateesh & Sekher, T V. (2014). *Factors leading to school dropouts in India: an analysis of National Family Health Survey-3 data.* International Journal of Research & Method in Education. 4. 75-83. 10.9790/7388-04637583.
- Mody A. (2019, November 18). *The false allure of English-medium schooling.* The Hindu. https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/the-false-allure-of-english-medium-schooling/article30000571.ece
- Mehta N. (2019, March 1). *India choosing to benchmark itself on PISA a massive signal … it says India wants to be measured globally*. Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/academic-interest/india-choosing-to-benchmark-itself-on-pisa-a-massive-signal-probably-our-pisa-colleagues-celebrating-more-than-india/
- (2019, November 18). *Ministry of HRD has launched NISHTHA Programme to improve learning outcomes at Elementary level through a massive Teacher Training Programme: Dr.*
- *Ramesh Pokhriyal 'Nishank'*. Press Information Bureau. Government of India. https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/lu196.pdf
- (2020, April 10). *Madhya Pradesh government launches 'Top Parent App'; students can study at home.* https://hindi.news18.com/news/career/mp-government-launched-top-parent-app-children-will-be-able-to-study-at-home-3003163.html (TRANSLATED THE HEADLINE TO ENGLISH)
- Nakajima, M., Kijima, Y. & Keijiro, O. (2018). *Is the learning crisis responsible for school dropout? A longitudinal study of Andhra Pradesh, India*. International Journal of Educational Development, vol. 62, issue C, p. 245-253. https://EconPapers.repec.org/RePEc:eee:injoed:v:62:y:2018:i:c:p:245-253.
- NITI Aayog. (2019). NITI Aayog Annual Report 2019-2020. Niti Aayog. https://niti.gov.in/sites/default/files/2020-02/Annual_Report_2019-20.pdf
- NITI Aayog. (2019). *The School Education Quality Index (SEQI)*. https://niti.gov.in/sites/default/files/2019-09/seqi_document.pdf
- (2019, December 15). *New AP law to replace Telugu with English as teaching language in schools*. Business Standard. https://www.business-standard.com/article/pti-stories/ap-govt-to-enact-law-on-education-medium-119121500237_1.html

References

- (2018, March 19). *NITI Aayog Released SATH-Education Roadmaps 2018-2020 on 17 March 2018.* Press Information Bureau. https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1525111
- NISHTHA : National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement. 'n.d.' Ministry of Human Resource Development. https://itpd.ncert.gov.in/mod/page/view.php?id=504
- OECD. (2016). *Education in Colombia, Reviews of National Policies for Education:* OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264250604-en.https://doi.org/10.1787/9789264250604-en.
- (2014, May 6). *OECD and Pisa tests are damaging education worldwide – academics.* The Guardian. https://www.theguardian.com/education/2014/may/06/oecd-pisa-tests-damaging-education-academics
- Singh, R. (2013). *Professional development of teachers: need of the hour.* Young Lives India Policy Brief https://www.younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/3aAoZmcBS2.pdf
- Puppala, A. (2018, September 22). *Teachers spend only 19.1 per cent time teaching.* Deccan Chronicle. https://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/220918/teachers-spend-only-191-per-cent-time-teaching.html
- Pandey, N. (2018, June 16). *From this academic session, school textbooks to turn smarter with QR codes.* Hindustan Times. https://www.hindustantimes.com/education/from-this-academic-session-school-textbooks-to-turn-smarter-with-qr-codes/story-2FcRTWwPHrg7geWzCH64HI.html
- (2020, May 19). *PM eVidya programme: big push for online courses to ensure edu doesn't suffer.* Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/pm-e-vidya-programme-big-push-for-online-courses-to-ensure-edu-doesnt-suffer/articleshow/75825888.cms
- OECD. (2017, August 31). *PISA 2015 Assessment and Analytical Framework.* Science, Reading, Mathematic, Financial Literacy and Collaborative Problem Solving. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264281820-en.
- (2019, April) *PISA 2021 Creative Thinking Framework (Third Draft).* OECD. https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA-2021-creative-thinking-framework.pdf
- (2020, February 26). *QR codes in all textbooks for classes 8 to 12 next year.* The Hindu. https://www.thehindu.com/news/national/kerala/qr-codes-in-all-textbooks-for-classes-8-to-12-next-year/article30924104.ece
- Ramanujam, A. (2019, December 16). *DIKSHA: The Long-Awaited Antidote to India's Education Crisis?.* The Bastion Development in Depth. https://thebastion.co.in/politics-and/diksha-the-long-awaited-antidote-to-indias-education-crisis/#:~:text=Although%20the%20platform%20was%20initially,nothing%20more%20than%20a%20smartphone.
- Rana, C. (2019, December 4). *Explained: What is PISA test and why is it significant?.* Indian Express. https://indianexpress.com/article/explained/explained-what-is-pisa-test-and-why-is-it-significant-6147829/
- Rajagopalan, S., & Agnihotri, V. (2014). Establishing Benchmarks of Student Learning (Rep.). Educational Initiatives and Michael & Susan Dell Foundation. doi:https://www.ei-india.com/newEIWebsite/eiasset/pdf/Establishing-Benchmarks-of-Student-Learning-Final.pdf

References

- Sajjad, H., Iqbal, M., Siddiqui, M. & Siddiqui, L. (2012). *Socio-Economic Determinants of Primary School Dropout: Evidence from South East Delhi, India*. European Journal of Social Sciences. 30. 1450-2267.
- Sharma, K. (2019, November 7). *India prepares hard for global student assessment test — last time it finished in bottom two.* The Print. https://theprint.in/india/education/india-prepares-hard-for-pisa-global-student-assessment-test-last-time-it-finished-in-bottom-2/316843/
- Sharma, S. (2020, February 12). *The Delhi model of education.* The Hindu. https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/the-delhi-model-of-education/article30796187.ece
- Shukla, R. (2019, October 15). *School Consolidation: Catalyst for Change or an Inequitable Policy?*. Centre for Policy Research. https://www.cprindia.org/news/school-consolidation-catalyst-change-or-inequitable-policy
- (2020, April 1). *State Education Center and AIR start unique Radio School in Madhya Pradesh.* News Services Division, All India Radio. http://www.newsonair.com/Main-News-Details.aspx?id=384348
- Thomas, W. P., & Collier, V. (2002). *A national study of school effectiveness for language minority students' long-term academic achievement.* UC Berkeley: Center for Research on Education, Diversity and Excellence. https://escholarship.org/uc/item/65j213pt (added this on my own pls check if it is correct)
- (2019, April). *Guidelines for design and implementation of early learning programmes.* UNICEF-LLF
- (2019, April). *UDISE+ Booklet.* Ministry of Human Resource Development. http://164.100.77.133/informationDetails.action?fileId=4#
- Vygotsky, L. S. (1978). Socio-cultural theory. Mind in society. The development of higher psychological processes. Massachusetts: Harvard University Press http://csieme.us/documents/Example-Annotated-Bib.pdf
- Volante, L. (Ed.). (2017). *The PISA effect on global educational governance*. New York: Routledge https://doi.org/10.4324/9781315440521
- Woessmann, L. (2018). *Central exit exams improve student outcomes.* IZA World of Labor, Institute of Labor Economics (IZA)
- Volante, L., Jerrim, J., Ritzen. J., & Schnepf, S. (2019, April 17). *New global testing standards will force countries to revisit academic rankings.* The Conversation. https://theconversation.com/new-global-testing-standards-will-force-countries-to-revisit-academic-rankings-115199
- (August, 2012). *Vision of teacher education in India, quality and regulatory perspective.* Volume 1. Ministry of Human Resources Development. https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/JVC%20Vol%201.pdf
- Walker, S.P., Chang, S.M., Vera-Hernández, M., Grantham-McGregor, S. (2011). *Early childhood stimulation benefits adult competence and reduces violent behavior*. American Academy of Pediatrics;127(5):849-857. doi:10.1542/peds.2010-2231
- (2020, July 24). *World Bank Education and COVID-19.* The World Bank. https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/03/24/world-bank-education-and-covid-19
- Yadav, M. (2014). *Role of Mother Tongue in Second Language Learning.* International Journal of Research. 11. 572-582

CENTRAL SQUARE FOUNDATION

सहयोगी:

मयंक भूषण
प्रतिभा जोशी
सुधांशु शर्मा

आभार:

इस विषय पर गहन चर्चा के लिए हम सेंट्रल स्क्वेयर फाउंडेशन के सहकर्मियों के प्रति आभारी हैं। इस रिपोर्ट को बनाने में दिए गए परामर्श और सहभागिता के लिए हम विशेष रूप से बिक्रम दौलत सिंह, श्वेता शर्मा कुकरेजा, डॉ. जयश्री ओझा और प्रवीण खांगटा के प्रति आभारी हैं। पल्लवी झींगरन को उनके महत्वपूर्ण सुझावों के लिए और उत्कृष्ट डेटा उपलब्ध करवाने के लिए तन्वी भांबरी और देविका ग्रोवर का विशेष रूप से धन्यवाद। साथ ही डॉ. धीर झींगरन,प्रणव कोठारी, स्टीव कैन्ड्रेल और शैलेन्द्र शर्मा को उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों एवं सहयोग के लिए धन्यवाद। यदि रिपोर्ट में कोई त्रुटि है तो वह पूर्णतया हमारी ज़िम्मेदारी है।

किसी भी प्रश्न, सुझाव, टिप्पणी या सुधार के लिए कृपया हमें ईमेल करें – **csf.research@centralsquarefoundation.org**